# हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 02.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

## प्रश्नकाल

## तारांकित प्रश्न

01-12-2025/1400/NS-HK/1

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, हमारा व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न है। हम आप पर भरोसा रखते हैं।

**अध्यक्ष** : यही तो फैसला हुआ था कि प्रश्नकाल के बाद ही व्यवस्था का प्रश्न उठाएंगे। आप उस भरोसे को बना कर रखें। मैं आपको पूरा सहयोग दे रहा हूं। प्रश्नकाल के बाद आपको मौका दिया जाएगा।

**प्रश्न संख्या : 2627**

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता था कि प्रदेश व केंद्र सरकार की ओर से किन-किन मदों के तहत धनराशि विकास कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में आबंटित की गई है? क्या पिछले दिनों पंचायती राज विभाग की ओर से कोई अधिसूचना जारी की गई है कि ब्लॉक्स में अलग-अलग मदों का जो पैसा विकास कार्यों के लिए आया है या अनस्पैंट पड़ा हुआ है उसको वापिस कर दिया जाए? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है? ब्लॉक्स में इसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। जैसे मेरा विकास खंड, सुलह या विकास खंड, भवारना है तो मेरी जानकारी के अनुसार सुलह, विकास खंड से लगभग 20 लाख रुपये वापिस हुए हैं और भवारना, विकास खंड से लगभग 7-8 लाख रुपये वापिस हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा पूरे प्रदेश में हुआ है और ऐसा पहली बार हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये पैसा हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा में अलग-अलग स्थानों पर उपयोग किया जा रहा है? दूसरा, मैंने इस बारे में जिला प्रशासन से भी बात की थी क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जब पैसा वापिस चला गया तब हमें जानकारी मिली। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह राशि प्राकृतिक आपदा के अलग-अलग मद में विकास कार्यों में लगाई जा रही है? क्या पूरे प्रदेश में इस राशि को वापिस लेने के आदेश हुए हैं? इसके क्या कारण रहे हैं और कुल मिला कर कितनी राशि वैस्ट की गई है?

01-12-2025/1400/NS-HK/2

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न इन्होंने पूछा है तो इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विभिन्न मदों के पैसे ट्रेजरी में वापिस लिए गए हैं या नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन 59 स्कीम्ज प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा ऐडिड हैं जिनमें राज्य सरकार व केंद्र सरकार का पैसा पंचायतों के माध्यम से खर्च होता है। Over a period of time हालांकि, हर सरकार के कार्यकाल में 3-4 वर्षों के बाद रिव्यू होता है कि कुछ 15वें वित्तायोग के पैसे और कुछ विभिन्न मदों से पैसा आया होता है तथा कुछ डी0सी0पी0 फंड होता है। जो भी अनस्पेंट मनी है वह पंचायतों के पास रहता है। Over a period of time चाहे शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई और विभाग हो, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की बात करें तो इतने वर्षों से जो अमाउंट्स हैं, वे अनस्पैंट पड़े हुए हैं जैसे अगर 2 लाख रुपये दिए गए हैं तो उनमें से 1.80 लाख रुपये खर्च हुए हैं और 20,000 रुपये खर्च नहीं हुए हैं। इस तरह से ये राशियां बहुत बड़ी हो गई थीं इसलिए अधिसूचना की गई थी कि अनस्पैंट मनी को ट्रेजरी में वापिस जमा करवाया जाए। परन्तु जो सेंट्रल ऐडिड स्कीम्ज हैं उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनस्पैंट मनी को वापिस ट्रेजरी में जमा करवाया जाए। ऐसी कोई अधिसूचना सेंट्रल ऐडिड स्कीम्ज के लिए जारी नहीं हुई है।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.12.2025/1405/RKS/Hk-1

प्रश्न संख्याः 2627... जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री.... जारी

वह अधिसूचना विधायक क्षेत्रीय विकास निधि और और डी0सी0पी0 फंड के लिए जारी की थी। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2023 से पहले का कुछ अमाउंट ट्रेज़री में वापिस आया है। यह कुल कितना अमाउंट है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यह प्रश्न पहले भी श्री बलबीर सिंह वर्मा जी ने सदन में उठाया था और इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। हम इस अमाउंट का सही आंकड़ा आपको उपलब्ध करवा देंगे। अधिसूचना में यह भी लिखा है कि अगर विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का पैसा वापिस किया होगा तो जिन माननीय सदस्यों का जितना अमाउंट वापिस हुआ है वे उसे लेने के लिए आवेदन करें ताकि वह अनस्पेंट मनी दोबारा से रिलीज किया जा सके।

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम केंद्रीय प्रोयोजित योजनाओं का अमाउंट ट्रेजरी में वेस्ट नहीं करते। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अनस्पेंट मनी व्यय न होने के क्या कारण हैं? क्या पंचायती राज विभाग द्वारा इस अमाउंट को असैस किया गया है? जो विधायकों को पैसे जारी होते हैं उन्हें विधायक अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग पंचायतों में देते हैं। लेकिन आपने उस पैसे को भी वापिस ले लिया। उसी तरह एस0सी0 कंपोनेंट और बैकवर्ड एरिया सब प्लान में अलग-अलग मदों में राशि स्वीकृत होती है। इन कंपोनेंट के तहत लगभग 38 मद हैं और इसमें असैसमेंट का क्या आधार है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपकी ओर से यह फरमान जारी किया गया है कि इस पैसे को वापिस किया जाएगा? एक ब्लॉक में जितनी पंचायतें हैं वहां पर एक सेक्रेटरी के पास कई पंचायतों का कार्यभार है। एक-एक सेक्रेटरी को तीन-चार पंचायतें दी गई हैं और तकनीकी सहायकों के पास भी 6-6 पंचायतों का कार्यभार है। वह तकनीकी सहायक इन पंचायतों में कब घूमेगा और कब इन सभी कार्यों की असैसमेंट करेगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी असैसमेंट का क्या आधार है? हम सभी जनप्रतिनिधि हैं और इसके लिए जनप्रतिनिधियों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। अगर कहीं कोई लिटिगेशन या फोरेस्ट एक्ट का मामला है तो आप उसे हमारे ध्यान में लाते। हमने विधायक निधि से महिला मंडलों के लिए एक प्रोत्साहित राशि का प्रावधान किया था लेकिन वह पैसा भी आपने वापिस ले लिया। क्या

01.12.2025/1405/RKS/Hk-2

माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो पैसा वापिस लिया गया है वह पुनः रिलीज किया जाएगा?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो विधायक क्षेत्रीय विकास निधि या 15वें वित्त आयोग के डी.सी.पी. के अंतर्गत रिलीज किया जाता है। दूसरा उसका इंटरस्ट होता है। वर्ष 2023 से पूर्व किन्हीं भी कारणों से जो अनस्पेंट धनराशि पड़ी रही, चाहे एन.ओ.सी. न मिलना हो, फॉरेस्ट लैंड से संबंधित मुद्दे हों या लोग हमारे पास आकर आग्रह करते हों कि विकास कार्यों के लिए इतनी राशि डाल दी जाए तो कई बार बिना वेरिफिकेशन के राशि डाल दी जाती थी किंतु औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण वह राशि कई वर्षों तक खर्च नहीं हो पाती था। जो हमारे ब्याज का बड़ा पार्ट था उसे वापिस लिया गया है। मैं पूरे सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि चाहे विधायक ऐच्छिक निधि हो या एम.एल.ए. फंड या जो भी राशि किसी कारणवश खर्च न हो पाई और वापिस आई है उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पहले भी स्पष्ट कहा है कि माननीय विधायकगण इसके बारे में लिखित में दे दें। प्रत्येक विधायक को यह जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी कि वर्ष 2023 से पूर्व एम.एल.ए. फंड या विधायक ऐच्छिक निधि की कितनी धनराशि वापिस आई है। आप इसे पुनः सबमिट कर दीजिए आपको धनराशि वापिस प्रदान कर दी जाएगी।

**श्री बिक्रम सिंह** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के माध्यम से यह उत्तर दिया कि धन और उसका ब्याज वापिस लिया गया। लेकिन जो क्षेत्रीय विकास निधि आप हमें जारी करते हैं उसकी रिकमेंडेशन तो विधायक ही देते हैं।

श्री... बी0एस0द्वारा जारी

01.12.2025/1410/बी.एस./वाई.के.-1

प्रश्न संख्याः 2627 क्रमांगत

**श्री बिक्रम सिंह जारी...**

जो क्षेत्रीय विकास निधि आप हमें देते हैं, वह क्षेत्रीय विकास निधि की रिकमेंडेशन विधायक करके भेजता है और विधायक ने जो रिकमेंडशन करके भेजी है वहां से आज तब वह पैसा ब्लॉक में नहीं आया है। हमने जो रिकमेंडशन की उसके बाद वह चिट्ठी चली गई और उसके बाद उपायुक्त महोदय ने कहा कि आपके पैसे तो मंजूर हो गए हैं परंतु वह पैसा न तो बी0डी0ओ0 के पास आया है और ट्रेजरी वाले वहां से पैसा मंजूर नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने किया है क्या हमारे वाला पैसा भी ऐसे तो नहीं चला गया? जो पिछली किस्त आपने काग़जों के अंदर दी है परंतु उसका पैसा विकास कार्यों के लिए बी0डी0ओ0 कार्यालय में नहीं आया है। मंत्री जी बताने की कृपा करें कि इसके क्या करण हैं?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि जो पैसे वापिस हुए हैं वे 31 मार्च, 2023 से पहले के हुए हैं। दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं that does not pertain to this question.

**श्री जय राम ठाकुर :** अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है और इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। मैं समझ सकता हूं कि सरकार के पास आर्थिक संसाधन की कमी है और अनस्पेंट पैसा जहां भी पड़ा है उस पैसे को इकट्ठा करके ये ट्रेजरी में जमा कर रहे हैं। लेकिन इसमें दिचस्प पार्ट यह है कि अलग-अलग मदों का पैसा इन्होंने वापिस लिया और वापिस लेने के बाद वह पैसा आपने कहां खर्च किया? जैसे विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा है, मुख्य मंत्री जी आप मंत्री जी को दबाव न डालिए कि यह बोलना है। कृपया, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि वर्ष 2023 से पहले की विधायक क्षेत्र विकास निधि को वापिस लिया गया है। क्या आपने इस बात को जरुरी नहीं समझा कि जो विधायक वहां पर चुन करके आए हैं, यह विधायक क्षेत्र विकास निधि एक बजट के प्रोविज के अंतर्गत आपने उन्हें आबंटित की है पहले उनसे बात कर लें। आप इस

पैसे को बी0डी0ओ0 को भेज दें या दूसरे विभाग जिममें विधायक क्षेत्र विकास निधि का पैसा भेगा गया। परंतु उस पैसे को खर्च करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधायक को है।

01.12.2025/1410/बी.एस./वाई.के.-2

जिन्होंने अपनी चिट्ठी लिख करके उसकी स्वीकृति प्रदान की है। आपने उनको भी पूछना उचित नहीं समझा? वर्ष 2023 से पहले हो सकता है कि दूसरा विधायक हो। हमें तो 6 बार के विधायक हैं। हम वर्ष 2009, 2012, 2017 और 2023 में भी थे। लेकिन आपने पूछने की आवश्यकता ही नही समझी। सीधा-सीधा विधायकों के जो अधिकार है उनका भी हनन है। दूसरा, क्या आपने वह विधायक विकास निधि अगर वापिस ली या बैकवर्ड एरिया सब प्लान का पैसा आपने वापिस लिया बाद में आपने उस पैसे को किस मद में खर्चा है? उसकी एलोकेशन क्या है और उस पैसे कहां पर खर्च किया गया है? क्या सरकार चलाने के लिए किया क्योंकि बैकवर्ड सब प्लान का पैसा निर्धारित है। विधायक विकास निधि का पैसा निर्धारित है। अगर वह पैसा वापिस लिया है तो वह पैसा उसी मद में खर्च होना चाहिए।

**अध्यक्ष** : ठाकुर साहब, आपका प्रश्न आ गया है,

**श्री जय राम ठाकुर** : मेरा मूल रूप से प्रश्न यह है कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जितना भी पैसा इस प्रकार से गया है वहां के चुने हुए प्रतिनिधि, विधायक को भी विश्वास में ले करके आप सुनिश्चित करेंगे कि जो वास्तविक कारण है वह पैसा अनस्पेंट पड़ा है उसकी तहकीकात करें और तहकीकात करने के बाद विधायक

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**01.12.2025.1415.डी0टी0-वाई0के0.-1**
**प्रश्न संख्या 2627.... जारी**
**श्री जय राम ठाकुर जारी...**

को भी विश्वास में लेकर आप सुनिश्चित करेंगे कि जो जेनुइन रिजन है जिसके कारण वह पैसा अनसपेंट पड़ा है, उसकी तहकीकात करें और तहकीकात करने के बाद विधायक उसमें अपनी संतुति-स्वीकृति दे की इस पैसे को दूसरी जगह खर्च किया जाए या वापिस लिया जाए। मेरे ब्लॉक में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ था और उस पैसे को वापिस लिया गया। लेकिन वह पैसा हमें पूछे बिना वापिस लिया गया। अगर आप मुझसे पूछते तो मै उस पैसे को उस स्कीम में डालने के लिए कहता जो सैंक्शन होने के बाद भी एग्ज्यूकूट नहीं हो पाई या मैं दूसरी जगह उस निधि को खर्च सकता था। आपने एक विधायक को उस अधिकारी से वंचित कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात पर आपका भी संरक्षण चाहूंगा कि सरकार विधायकों को इस अधिकार से क्यों वंचित कर रही है इसका आप संज्ञान लें? विधायक क्षेत्र विकास निधि जो केवल और केवल विधायक के माध्यम से ही खर्च होनी है वह उनके माध्यम से ही खर्च हो क्या ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे और पुनः विचार करेंगे कि जितना पैसा सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि का वापिस लिया है उस पैसे को पुनः विधायकों से पूछ कर रिएलोकेट करेंगे?

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी को बतलाना चाहूंगा, वैसे तो यह पूर्व में मुख्य भी रहे हैं और पूरा वित्त विभाग के बारे में ये जानते होंगे। इनको पता होगा कि ट्रेजरी कैसे चलती है और ये मुझसे बेहतर जानते भी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो पैसे वापिस लिए गये वह तकनीकी कारणों से वापिस लिए गये। जिनकी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हो पाई जैसे सरकारी भूमि है, एफ0सी0ए0 की क्लीयरेंस नहीं हो पाई या कोई अन्य कारण है, उसके कारण जो अनस्पेंट मनी को उसे वापिस लिया गया। अगर मान लीजिए किसी स्कीम में 2 लाख रुपये डालें हैं और उसमें से 20 हजार की राशि बच गई या उस राशि के ऊपर कोई इंटरस्ट मिला है, वही पैसा वापिस लिया गया है। जैसे मैंने पहले भी जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने पूछा तक उसके उत्तर में कहा कि सभी विधायकों this is not a concern of one MLA or two MLAs, this is a concern of everybody. उनको जो पैसे वापिस गये हैं उनकी एक लिस्ट बनाएंगे। हालांकि इस

**01.12.2025.1415.डी0टी0-वाई0के0.-2**

संबंध में समय-समय पर उपायुक्तों द्वारा रिव्यू मीटिंग्ज की जाती है। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी पैस क्षेत्रीय विधायक **विकास निधि या ऐच्छिक निधि के वापिस गये हैं, उसके संबंध में संबंधित विधायक को विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया जायेगा। ताकि वह पुनः छोटे-छोटे अमाउंटस की स्कीम को कंसोलिडेट कर के एक नई स्कीम डाल सके।**

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी इसमें तो मंत्री जी का आश्वासन आ गया। ठीक है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए पर आपका अनुपूरक प्रश्न इसी से संबंधित होना चाहिए। ...(व्यवधान) नहीं यह पहले भी नहीं था। This was not ariising out of Question but still I allowed Shri Jai Ram Thakur Ji.

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो पूछा गया है उसकी के बारे में मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। विधायक एक संस्था है और यह संस्था कंटीन्यूटि में रहती है। आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी तो लगातार विधायक रहे परंतु यदि किसी विधान सभा क्षेत्र में विधायक बदलता भी है, मैं वर्ष 2007 से लेकर 2017 तक विधायक रहा और 2017 से 2022 तक विधायक नहीं था तो मेरी जो सैंक्शन्ज खर्च नहीं हुई थी तो जो 2017 से 2002 तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे उन्होंने उन सैंक्शन्ज को चेंज किया और उनको यह अधिकार भी है क्योंकि विधायकों की संस्था कन्टिनयूटि में है और सांसदों का भी ऐसा ही होता है। परंतु अब आपने वे सारा, चाहे विधायक पहले था-नहीं था, यानी दो साल में जो पैसा खर्च नहीं हुआ उसे बदल रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। जो भी इस प्रकार की राशि है वह वापिस आनी चाहिए।

**Speaker** : That what he has assured.

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने दोनों के बारे में आश्वासन नहीं दिया इन्होंने ऐच्छिक निधि के बारे में आश्वासन दिया है।

**अध्यक्ष** : नहीं मंत्री जी द्वारा दोनों का आश्वासन दिया गया है।

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय दूसरी बात माननीय मंत्री जी को कह रहे हैं वह प्रदेश की योजनाओं के बारे में कह रहे हैं। केंद्र की 15वें वित्त आयोग में योजना के पैसे को भी जल शक्ति विभाग के 70 पंचायतों में गये और वह पैसा भी डायवर्ट हुआ। जब कि 15वें

वित्त आयोग का पैसा केंद्र द्वारा पंचायतों के लिए आया और इस पैसे को खर्च करने की गाइडलाइंस भी हैं। उस पैसे को भी डायवर्ट करने के आदेश ग्रामीण विकास

**01.12.2025.1415.डी0टी0-वाई0के0.-3**

एवं पंचायती राज विभाग के निदेशालय से आए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह निर्देश किस आधार पर आपके द्वारा दिए गये, जो पैसा चला गया क्या वह पैसा वापिस आयेगा; और अगर नहीं गया तो क्या आप वह निर्देश वापिस लेंगे? क्योंकि प्रदेश सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों के लिए दिए गये पैसे को किसी विभाग को डायवर्ट किया जा सके।

**(15वें वित्तायोग के अन्तर्गत टाइड मद की राशि को जल शक्ति विभाग हो हस्तांतरित करने बारे पत्र को सभा पर रखा गया।)**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो 2007 से 2017 तक विधायक रहे इसकी समय-समय पर रिव्यू मीटिंग्ज करनी चाहिए और जो छोटे-छोटे अमाउंटस जोड़-जोड़ करके इतने बड़े अमाउंटस बन गये हैं, उनको वापिस लेना अनिवार्य है।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1420/ए.जी.-एन.जी./1**

**प्रश्न संख्या - 2627 (स्थगित).......जारी**

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री........जारी**

उनकी समय-समय पर रिव्यू मीटिंग्स करनी चाहिएं। छोटे-छोटे अमाऊंट्स जोड़ कर बहुत बड़ा अमाऊंट बन गया है और उसे वापिस लेना अनिवार्य था।...(व्यवधान) मैंने पहले भी बोला है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : मंत्री जी, इनका अभिप्राय यह है कि इनको पूछ कर करना था। वैसे आपने पहले ही आश्वासन दे दिया है।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी वहीं कह रहा हूं कि **सभी माननीय विधायकों को पत्र जारी किए जाएंगे जिसमें अमाऊंट भी लिखा जाएगा और विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना व ऐच्छिक निधि को अलग-अलग दर्शाया जाएगा ताकि उन अमाऊंट्स को पुनः जारी किया जा सके।**

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 38 योजनाएं प्रदेश सरकार और 21 योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। हमारे विभाग की ओर से पैसा डायवर्ट करने का कोई भी आदेश नहीं हुआ है। माननीय सदस्य अनटाइड अमाऊंट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी डायवर्ट करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। अनटाइड पैसा पानी के लिए खर्च किया जाना था और पंचायतें स्वयं उन पैसों को खर्च करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा जल शक्ति विभाग के पास पैसों की शोर्टेज़ है। जिस कारण हमने एक फैसला किया है कि पैसा तो पंचायतों के माध्यम से ही खर्च होगा लेकिन योजनाओं का निर्माण जल शक्ति विभाग द्वारा किया जाएगा और वे सारी योजनाएं पंचायतों के नाम पर ही होंगी।...(व्यवधान)

**01.12.2025/1420/ए.जी.-एन.जी./2**

**अध्यक्ष** : अगला प्रश्न - 3137 ...(व्यवधान) माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बोल दिया है कि कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) This is what he has said it. ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, एक मिनट रुक जाइए। ...(व्यवधान) He has said it. माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बोल

दिया है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जो भी अनटाइड फंड जल शक्ति विभाग से संबंधित था वह पंचायतों द्वारा ही खर्च किया जाएगा लेकिन कार्यकारी एजेंसी जल शक्ति विभाग होगी। This is what he has said it. ...(व्यवधान) क्या आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है? ...(व्यवधान) इन्होंने प्रश्न का जवाब तो दे दिया है।...(व्यवधान) एक ही प्रश्न पर चर्चा करते हुए 20 मिनट हो गए हैं।...(व्यवधान)

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, 15वें वित्तायोग के पैसों को खर्च करने की कुछ गाइडलाइन्ज़ बनी हुई हैं और उनके अनुसार वह पैसा पंचायतों द्वारा ही खर्च किया जा सकता है तथा वह पैसा विभाग को नहीं दिया जा सकता।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : श्री रणधीर शर्मा जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) एक प्रश्न पर ही इतनी ज्यादा चर्चा नहीं करवाई जा सकती।...(व्यवधान) आप इस विषय को नियम-61 के तहत ले आइए और I will give you a chance under Rule 61 - Half an Hour Discussion. तथा जो आपकी क्वारीज़ हैं, वे सभी रेज़ हो जाएंगी।...(व्यवधान) अभी भी इस प्रश्न पर 20 मिनट तक चर्चा चल चुकी है।...(व्यवधान) माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने बोल दिया है कि इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है। If you have a copy of that order, please place it on the Table of the House. ...(व्यवधान)

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रश्न का हल निकालना चाहते हैं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष** : श्री रणधीर शर्मा जी, इस प्रश्न का हल निकल रहा है और अगले प्रश्न भी पूछे जाने शेष हैं।...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी, प्लीज़, अब बहुत हो गया है।

**01.12.2025/1420/ए.जी.-एन.जी./3**

**प्रश्न संख्या : 3082 (स्थगित)**

**श्री सुधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछले सत्र में लगा था। प्रदेश सरकार ने ऐसी कितनी जांच समितियां गठित कर दी हैं कि अभी तक सूचना ही एकत्रित की जा रही है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सूचना अगले सत्र में या उससे पहले उपलब्ध करवा दी जाएगी?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा कई जांच समितियों का गठन किया गया है। माननीय सदस्य ने उनकी जांच रिपोर्ट के संदर्भ में भी पूछा है। इसलिए जांच करवाने और उनकी सूचनाएं एकत्रित करने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। **जैसे ही जांच रिपोर्ट्स की सूचनाएं एकत्रित कर ली जाएंगी, उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।**

**01.12.2025/1420/ए.जी.-एन.जी./4**

**प्रश्न संख्या : 3137**

**श्री लोकेन्दर कुमार** : अध्यक्ष महोदय, मैंने ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में पूछा था। इसके अलावा मैंने पूछा था कि गत 6 माह में आपसी सहमति से कितने कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है?

अध्यक्ष महोदय, हमारे दूर-दूराज के स्कूल व अस्पतालों में किसी भी नेता के डी0ओ0 नोट लगाकर कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा रहा है। जिससे बच्चों व मरीजों को काफी दिक्कत आ रही है। इसके बावजूद भी मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में क्या इतना भी सिस्टम नहीं बना पाया है कि मैंने जो छोटी- सी जानकारी मांगी है, उसकी सूचना समय पर उपलब्ध करवा दी जाए?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह पूर्व सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी है और अभी इसमें व्यवस्था परिवर्तन करना शेष है। **जैसे ही इसमें भी व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जाएगा, माननीय सदस्य को जवाब दे दिया जाएगा।**

अगला प्रश्न.....श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

**01.12.2025/1425/ए0जी0-पी0बी0/1**

**प्रश्न संख्याः 3616**

**Speaker:** Very exhaustive reply has been given by the Hon'ble Minister. माननीय सदस्य नीरज नैय्यर क्या आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं?

**श्री नीरज नैय्यर** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भविष्य में जो मणिमहेश यात्रा होगी क्या सरकार उसके लिए नए एस0ओ0पीज0 बनाने का विचार रखती है? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि चम्बा में आई आपदा से मणिमहेश यात्रा में कितने लोगों की मृत्यु हुई है क्योंकि इस त्रासदी के समय फेसबुक के माध्यम से मृत्यु का आंकड़ा हज़ारों में बताया गया था। यदि अभी आपके पास इसका डाटा है तो कृपया मुझे बताएं कि वास्तव में वहां कितने लोगों की मृत्यु हुई है? भगवान न करें कि ऐसी आपदा फिर से आए लेकिन लोगों द्वारा इस प्रकार की जो अफ़वाहें फैलाई जाती है उसके लिए क्या सरकार अगले वर्ष कोई ऐसी नीति बनाएगी जिसके अंतर्गत इस तरह की अफ़वाहों पर रोक लगाई जा सके? मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी का विशेषतौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब मैं आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में स्वंय गया था तो मुझे बताया गया कि रास्ते खुलने में लगभग 4 माह का समय लग जाएगा लेकिन सरकार द्वारा भरमौर तक बस जाने योग्य रास्ता 20 दिनों में ही खोल दिया गया और मुझे लगता है कि ये रास्ते छोटे वाहनों के लिए उससे भी पहले खोल दिए गए थे।

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, उस समय विपक्ष का यह कहना था कि चम्बा में आपदा से बंद हुई सड़कें 3-4 महीने में भी नहीं खुलेंगी परंतु जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि आपदा से प्रभावित सभी रास्तों को सरकार द्वारा 20 दिनों के रिकॉर्ड समय में खोल दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, चम्बा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। उस समय मुख्य मंत्री जी ने स्वंय चम्बा का दौरा किया और हेलीकॉप्टर से भरमौर का सर्वे भी किया लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर पाया। उस समय सोशल मीडिया पर मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित कई अफ़वाहें फैलाई गई जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि चार हज़ार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है जबकि

**01.12.2025/1425/ए0जी0-पी0बी0/2**

हकीकत यह है कि इस त्रासदी के दौरान कुल 17 लोगों की जानें गई हैं। इस प्रकार की अफ़वाहें फैलाने वाले लोगे कौन थे? अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा तो विपक्ष हल्ला करेगा। वे अफ़वाह फैलाने वाले लोग इन्हीं (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) की पार्टी के थे। ...(व्यवधान) मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। जब में चम्बा गया था तो मुझे रास्ते में इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग मिले थे जिनके चेहरे मुझे अभी तक याद है। वही ये सब अफ़वाहें फैला रहे थे कि यहां पर चार-पांच हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने इस प्रकार की अफ़वाहें फैलाकर मणिमहेश की यात्रा पर आए 15-16 हज़ार यात्रियों के परिवारजनों को बहुत पीड़ा दी है। दूसरा, इन्होंने एक अफ़वाह

**श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1430/A.S./A.P./ 01**

**प्रश्न संख्या 3616 जारी .....**

**राजस्व मंत्री जारी .....**

इसके अलावा, दूसरी अफवाह इन लोगों द्वारा फैलाई गई कि इंटरनेट सुविधा कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। अब आप बताइए कि इंटरनेट की सुविधा तो केंद्र सरकार के पास होती है। अगर वे बहुत चिंतित थे तो कोई दूसरा उपकरण लगाकर इंटरनेट चला लेते। हमारे हाथ में तो इंटरनेट था ही नहीं। जैसा माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने कहा कि अफवाहों द्वारा लोगों को गुमराह किया गया, जिससे उन्हें काफी पीड़ा हुई। इस बार ऐसे लोगों के खिलाफ नरमी बरती गई है, लेकिन आगे से अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसी यात्राओं के लिए एस0ओ0पी0 तैयार करने की आवश्यकता है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर ने कहा। हम इन पर विस्तृत एस0ओ0पी0 तैयार करेंगे। इस समय भी एस0ओ0पी0 बनाई गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वे इतनी सशक्त नहीं हैं। इस एस0ओ0पी0 को और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि इनमें खामियां कम-से-कम हों। इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि हमें बहुत से लोगों ने मदद की है। जैसे जिन लोगों ने वहां पर लंगर लगाए, चाहे वे प्रदेश के हों या प्रदेश के बाहर के सभी लोगों ने हमें मदद दी। पंचायतों द्वारा भी 16,000 लोगों को रास्ते में भोजन करवाया गया और रहने के लिए भी उचित जगह दी गई। उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। जहां तक सड़कों की बात है, हमने हर ब्लॉक प्वाइंट पर कोई न कोई अधिकारी तैनात किया था। जैसे ही मशीन वहां पहुंचती थी, उसे तुरंत लगाया जाता था और इसी कारण सड़कों को 20 दिनों में बहाल कर दिया गया, जबकि सामान्यतः इन्हें खोलने में चार से छह माह का समय लगता है।

**01.12.2025/1430/A.S./A.P./ 02**

**अध्यक्ष :** माननीय सदस्य डॉ 0 जनक राज जी।

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह मणिमहेश यात्रा के दौरान अव्यवस्था हुई है, उसे हम सबने देखा है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। परन्तु मणिमहेश यात्रा मेरे चुनाव क्षेत्र में होने वाली एक अत्यंत आध्यात्मिक और व्यावसायिक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान बहुत से स्थानीय लोग

रोजगार और व्यापार के लिए दुकानें लगाते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा एक शुल्क जमा करवाने के बाद अधिकृत रूप से दुकान लगाने की अनुमति दी जाती है। इस यात्रा के दौरान लंगर भी बड़ी संख्या में लगाए जाते हैं। लेकिन जब आपदा आई तो वहां पर बहुत से लोगों की दुकानें बह गईं और लंगर वालों का सामान भी नष्ट हो गया। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि उन गरीब लोगों के नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि जल्द-से-जल्द जारी की जाए।

**राजस्व मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जनक राज जी भरमौर विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वे भी मेरे बाद पैदल चलकर वहां गए थे। उस वास्तविक स्थिति से माननीय सदस्य भली-भांति अवगत हैं। वहां पर लंगर बहने की कोई सूचना नहीं आई। हां, लेकिन एक स्थान पर ऐसा हुआ था। वहां हमने पहले ही राहत मैनुअल के तहत मदद प्रदान कर दी थी। 10,000 से 20,000 की जो फीस हम लंगर लगाने वालों से लेते थे, उसी समय हमने यह घोषणा की थी कि अगली बार जो भी लंगर लगाएगा, उससे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी।

**अध्यक्ष** : माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी।

**श्री केवल सिंह पठानिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मणिमहेश यात्रा हमारी एक ऐतिहासिक यात्रा है। हमारे चंबा क्षेत्र में चमेरा-2, चमेरा-3, जे0एस0डब्ल्यू0, जे0एम0आर0 जैसे प्रोजेक्ट हैं, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र बोह और द्रणी से लगे हुए इलाके में स्थित हैं। हर साल यहां नुकसान होता है। चंबा में इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एस0ओ0पी0 तैयार की जाएगी, उसमें पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा उत्पन्न व्यवधानों को शामिल किया जाएगा या नहीं? क्या सरकार उन प्रोजेक्ट्स से आने वाले धन का कुछ हिस्सा बार-बार होने वाले नुकसान की

**01.12.2025/1430/A.S./A.P./ 03**

भरपाई और मणिमहेश यात्रा में लगाएगी? लगभग 16,000 व्यक्ति इस दौरान यात्रा में फंसे थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार से कोई मंत्री वहां पर आया। मैं यह भी पूछना

चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के साथ ऐसा पक्षपात क्यों किया जाता है। उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर में हादसा हुआ तो माननीय गृह मंत्री जी वहां पहुंचे। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि इस बार मणिमहेश यात्रा के दौरान छड़ी नहीं पहुंची। यह यात्रा हजारों सालों से होती आ रही है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि छड़ी यात्रा में नहीं पहुंच पाई। हमारा हिमाचल प्रदेश एक हिंदू प्रदेश है और इसे वास्तव में ऐसा ही बनना चाहिए। क्या इस हिंदू प्रदेश में, जहां 16,000 लोग इतने दिनों तक फंसे रहे, कोई केंद्र का एक भी प्रतिनिधि प्रदेश में आया?

श्री ए0टी0 द्वारा जारी....

**01.12.2025/1435/AT/ AS /1**

**प्रश्न संख्या-3616 जारी......**

**श्री केवल सिंह पठानिया जारी...**

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या केंद्र का कोई सेक्रेटरी, कोई जिम्मेदार आदमी या कोई प्रतिनिधिमंडल मणिमहेश यात्रियों के लिए आया? अगर प्रतिनिधिमंडल आया था तो उनके द्वारा यात्रियों को क्या सहायता दी गई?

**राजस्व मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं यहां तो हेलीकॉप्टर वायु सेवा लेने के लिए मुख्य मंत्री को एक बार नहीं, अनेकों बार और डिफेंस मिनिस्टर से भी बात करनी पड़ती है तभी हेलीकॉप्टर आता है। अब यह छड़ी की तो बात दूर है। अगर इतना ही हिन्दू धर्म का ख़याल करते तो छड़ी के लिए ही हेलीकॉप्टर दे देते हम हेलीकॉप्टर में छड़ी को ले जाते। यहां सबसे बड़ी बात है कि जो नेशनल हाईवे 154 पठानकोट से चंबा है, उसे बढ़िया बनाने की ज़रूरत है उसे सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है। इसमें छोटे-छोटे टनल बनाकर इसे ठीक तरीके से बनाएंगे। यह पूरा इलाका फ्रैजाइल है। जिन कंपनियों के हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वह सारे अब कमीशन पर हैं। उनका CSR का पैसा लेकर भी कुछ काम हो सकता है। पर नेशनल हाईवे केंद्र सरकार की

ज़िम्मेदारी है। बेहतर DPR बनाकर प्रस्तुत किया गया है परंतु उसमें बजट समय से मिल जाए ताकि यह सेफ रोड बन सके। यह आस्था का प्रश्न तो है ही।

**01.12.2025/1435/AT/ AS /2**

**प्रश्न संख्या** - **3617**

**श्री पवन कुमार काजलः** माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आया है कि 31.10.2025 तक मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 23279.45 लाख रुपये की धनराशि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आबंटित की गई। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता था कि कांगड़ा विधानसभा को इसमें बहुत कम धनराशि अलॉट हुई है। मेरी विधानसभा में एक रोड़ है घटा-चौंधा बाया मासा-बस्ती, वह NABARD से था। उसकी लंबाई 4,600 मीटर थी। जब डिपार्टमेंट ने काम किया तो चौंधा तक सड़क पूरी हुई। अप टू कुलथी तक 4,600 मीटर में कवर होता था, 800-900 मीटर पिछले चार-पांच साल से वैसे ही पड़ा है जबकि NABARD से उसकी स्वीकृति भी हुई थी। तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आवंटन करते समय ध्यान देंगे? इस 23279.45 लाख रुपये में कांगड़ा को लगभग कुछ नहीं दिया गया है। मेरी विधानसभा की दो-तीन-चार सड़कें थीं, जैसे झनयंकड़ की दो सड़कें उसमें कुछ 15-20 लाख रुपये की कुछ बरसों से सोलिंग,टायरिंग से वंचित हैं। अगर 35-40 लाख रुपये भी मिल जाए तो यह छोटी-छोटी सड़कें बन सकती हैं। अगर आप 40-50 लाख रुपये कर देंगे तो यह सड़क जो वर्षों से सोलिंग, वियरिंग और टायरिंग से वंचित है उसमें यह सब हो जाएगा और इससे ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिलेगा।

**मुख्य मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा कि मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कों का आवंटन किया जाता है। सड़कों का आबंटन नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसी योजना है जिसमें परिस्थितियों के हिसाब से सड़क का आवंटन होता है। मुख्य मंत्री जी जब दौरे पर जाते हैं, तो कई जगह छोटी-छोटी रोड्स होती हैं उनके लिए पैसा देते हैं। विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं वहां के लिए पैसा देते हैं। बाकी विधायकों को NABARD व बजट के तहत सड़के मिलती हैं। तो यह परिस्थितियों के हिसाब से मुख्य मंत्री के दौरे के दौरान जब लोग मुख्य मंत्री से मिलते हैं उस हिसाब से सड़कों का आवंटन

किया जाता है। मैं इनके क्षेत्र में जाऊंगा और जब वहां प्रोग्राम रखेंगे। जहां 800-900 मीटर सड़क होगी तो उसे देख लिया जायेगा।

**एम0डी0 द्वारा जारी ......**

**01-12-2025/1440/DC/MD/1**

**प्रश्न संख्या : 3617---जारी मुख्य मंत्री---जारी**

जो बजट दिया जाता है, वह प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अनुसार दिया जाता है। पहले किसी कार्य की स्वीकृति दी जाती है और उसके बाद 'सैंक्शन अमाउंट' जारी किया जाता है, लेकिन कई स्थानों पर अभी केवल स्वीकृति मिली है, सैंक्शन अमाउंट जारी नहीं हुआ है। जहां-जहां मुख्य मंत्री स्वयं जाकर घोषणाएं करते हैं और स्थिति देखते हैं, वहां उसी आधार पर ग्रामीण सड़कों का आवंटन किया जाता है। आने वाली सर्दियों के दौरान जब मैं उनके विधानसभा क्षेत्र में जाऊंगा, तो परिस्थितियों के अनुसार इस सड़क के लिए बजट आवंटन पर विचार किया जाएगा।

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमने इसलिए शुरू की थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें बार-बार खराब हो जाती हैं और लोगों को उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत पड़ती है। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए इस योजना में धन देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस योजना का पैसा अब मुख्य मंत्री के डिस्कृमिनेशन का पैसा हो गया है। मुख्य मंत्री जी के नजदीकी क्षेत्रों के विधायकों को तो 8-10 सड़कें, कहीं-कहीं 15-15 सड़कों तक की स्वीकृति दे दी गई है। जबकि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों को एक भी सड़क की स्वीकृति नहीं मिली। 3 वर्षों में मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में, जहां भारी नुकसान हुआ है उन तीन सालों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एक भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। यह योजना पूरे प्रदेश के लिए है, केवल सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप पूरे प्रदेश को अपना नहीं मानते। आपके द्वारा प्रदेश को वही माना जा रहा है जहां से आपकी सरकार के विधायक हैं। इसलिए क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के इस वित्त वर्ष के कुल आवंटित बजट में से जो हिस्सा अभी बचा है, उसे विपक्ष के

विधायकों के क्षेत्रों में भी समान रूप से, अनुपात के अनुसार जारी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह जनहित और प्रदेश हित में नहीं है। प्रदेश को एक नजर से देखिए, यह सारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है और आप पूरे राज्य के मुख्य मंत्री हैं। मुझे मालूम नहीं आप इसे कैसे सोचते हैं।

**01-12-2025/1440/DC/MD/2**

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा कि डिस्कृश्नरी है और मुझे इस बात का दुख है कि आप प्रश्न नहीं पढ़ते। आप अपने ही विधान सभा के क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पढ़ लें। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय, आप भी हमारी श्रेणी में आते हैं। मैंने सिराज के लिए 9 करोड़ 51 लाख रुपये, मंडी के लिए 93 लाख, नाचन के लिए 56 लाख, बल के लिए 42 लाख और करसोग के लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपये जारी किए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने सभी 68 विधान सभा क्षेत्रों की विस्तृत जानकारी दी है और माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी के लिए तो विशेष रूप से अधिक सहयोग किया है। आप कहते हैं कि हम आपको नहीं मानते, लेकिन हम आपको विपक्ष के नेता के रूप में पूरी इज्जत देते हैं, और जो आप कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। आप स्वयं देखिए सी0आर0एफ0 के तहत अभी तक 1 करोड़ रुपये आए, लेकिन हमने आप पर विशेष कृपा दिखाते हुए चैल चौक से छत्री तक की सड़क के लिए 134 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। क्या यह विपक्ष के विधायकों के प्रति हमारा सहयोग नहीं है? इसके अलावा, मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत जो पैसा आबंटन किया जा रहा है

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**01.12.2025/1445/केएस/डीसी/1**

**प्रश्न संख्या : 3617जारी**--

**मुख्य मंत्री जारी...**

अभी तो वह हमारा पैंशन और पे में जा रहा है परंतु स्वीकृति मिल सकती है और जब एस्टिमेट सेंक्शन की बारी आएगी तो कितने रुकते हैं उस अनुसार बजट के हिसाब से फैसला किया जाता है। अभी तो **अगर इनको समस्या होगी कि मुख्य मंत्री सड़क योजना के तहत इनको किसी सड़क को पैसे देने होंगे तो सभी विधायकों से अनुरोध है कि वे मेरे पास आएं, मुझसे मिले, हम उनको चाय भी पिलाएंगे और मैरिट के हिसाब से, विधान सभा की परफोर्मेंस के हिसाब से कुछ स्वीकृति भी दे देंगे**

**01.12.2025/1445/केएस/डीसी/2**

**प्रश्न संख्या 3618**

**डॉ0 जनक राज :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उसके संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रोबोटिक सर्जरी की निःशुल्क सुविधा प्रदेश के बी.पी.एल., आई.आर.डी.पी., हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिलेगी या नहीं?

दूसरे, वर्तमान में रोबोटिक सर्जरी करवाने के लिए सरकार ने कितना शुल्क निर्धारित किया है?

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, रोबोटिक सर्जरी हिमाचल के इतिहास में एक क्रान्तिकारी कदम है। पहली बार यह सोचा गया है कि हिमाचल की आम जनता को भी एम्ज़ के बराबर सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। रोबोटिक सर्जरी जब से शुरू हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो महीने के अंतराल में चमियाणा मैडिकल कॉलेज में इसके अंतर्गत लगभग 78 ऑप्रेशन हो चुके हैं। टांडा मैडिकल कॉलेज में लगभग 38 ऑप्रेशन हो चुके हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के डॉक्टरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि एक रोबोटिक सर्जन

---

हमें 4 से 5 लाख रुपये तक मिलता है लेकिन हिमाचल प्रदेश के जितने भी मैडिकल कॉलेजों के डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत जल्दी सीखकर इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाए हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश के सभी मैडिकल कॉलेजों के डॉक्टर मुबारकवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार का यह प्रण है कि एम्ज़ में जो सुविधा मिलती है, आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को, आम आदमी को वह सुविधा हिमाचल के सभी मैडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमारे यहां ऐसे-ऐसे मैडिकल कॉलेज हैं जहां 15-15 साल पुरानी एक्सरे मशीन है। आई.जी.एम.सी. शिमला का प्रीमियम हॉस्पिटल है जहां 19 साल पुरानी एम.आर.आई.की मशीन लगी है। डॉक्टर भी अपना कितना दिमाग खर्च करेगा जब वह लेटैस्ट टैक्नोलॉजी

**01.12.2025/1445/केएस/डीसी/3**

के हिसाब से मरीजों को नहीं देख पाएगा? ये रेफरल हॉस्पिटल बनते जा रहे थे। हिमाचल के आम नागरिक, गरीब मरीज 1000 करोड़ रुपये के लगभग का इलाज हिमाचल से बाहर करवाते थे। हमारी सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू किया और मैं बताना चाहता हूं कि हमने हैल्थ सेक्टर में कम से कम 3000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमैंट करने की बात बात की है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन मैडिकल कॉलेजों में अभी एम.आर.आई. मशीन नहीं है जैसें नेरचौक में नहीं है तो हमने वहां के लिए भी स्वीकृति दे दी है और आने वाले चार हफ्तों में तीन और मैडिकल कॉलेजों- हमीरपुर, नेरचौक और आई.जी.एम.सी.,शिमला में जनवरी तक रोबोटिक सर्जरी मशीन की स्थापना कर दी जाएगी और सभी जगह एम.आर.आई. की मशीन और एक स्मार्ट लैब स्थापित करेंगे। यह अभी एम्ज़ में आई हैं तथा तीन स्मार्ट लैब्ज़ हमने चमियाणा, आई.जी.एम.सी. और टांडा के लिए स्वीकृत की हैं। जो माननीय सदस्य ने सवाल किया था, बहुत ही कम दरों पर हम

---

आम नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। हमने कहा है कि जो भी गरीब आदमी आएगा, इसमें बहुत ज्यादा क्वालिटी का इलाज होता है और मेरी खुद की भी रोबोटिक सर्जरी हुई है। जब मैं बीमार था तो मैंने खुद स्टडी किया है अतः 30 हजार रुपये हम गरीब और आम आदमी जो कि पे कर सकता है, उससे लेते हैं और जो यह कहता है कि मुझे स्पेशल वार्ड में रहना है उससे 50 हजार रुपये लिए जाते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

01.12.2025/1450/av/hk/1

**प्रश्न संख्या : 3618---------- क्रमागत**

**मुख्य मंत्री------- जारी**

वैसे भी जो स्पेशल वार्ड में रहेगा उसको 50,000 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी0जी0आई0 चण्डीगढ़ में जो आयुष्मान भारत और हिम केयर कार्ड के तहत रेट लिया जाता है, हम भी उसी आधार पर पैसे ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग अब रोबोटिक सर्जरी यहां करवा रहे हैं। यहां पर बार-बार कहा जाता है कि हमने 3,000 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट स्वीकृत करवा दिया है। लेकिन मैं सदन के अंदर बताना चाहता हूं कि अभी तक जाइका के थ्रू हमारा कोई भी प्रोजैक्ट स्वीकृत नहीं हुआ है। सरकार ने रिकॉमेंडेशन दी है परंतु हमारी ई0ए0पी0 की लिमिट खत्म हो चुकी है और इसके बारे में हम 16वें वित्तायोग में सोचेंगे कि उसको डालना है या नहीं डालना है। हम भारत सरकार से भी अनुरोध करेंगे क्योंकि इसमें 72 प्रतिशत भारत सरकार और 28 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा हमारी लोन की लिमिट के माध्यम से दिया जाता है। ...(व्यवधान) इसमें 90:10 के हिसाब से नहीं दिया जाता। भविष्य में जैसे-जैसे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे तो गरीब आदमी के लिए रोबोटिक सर्जरी की दर को कम करने के बारे में सोचा जा सकता है।

**श्री बिक्रम सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने यह जो रोबोटिक सर्जरी शुरू की है तो इसमें हमारे पास कितने सर्जन है? इसके अतिरिक्त जो प्रश्न किया गया है कि क्या यह सत्य है कि जिनके पास हिमकेयर कार्ड या आयुष्मान भारत का कार्ड है, उनको इस सर्जरी को करवाते समय एन्टरटेन नहीं किया जाता? ऐसा सुनने में आ रहा है कि वहां पर हिमकेयर के मरीज एन्टरटेन नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद आपने रोबोटिक सर्जरी मशीनों की स्थापना और प्रशिक्षण पर खर्च के बारे में भी कहा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने डॉक्टर्ज को प्रशिक्षण दिया गया और उसके ऊपर कितना खर्च आया?

**01.12.2025/1450/av/hk/2**

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, इसमें यूरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी इत्यादि सब अलग-अलग हैं। हम एम्ज़ के ट्रैंड के हिसाब से ही कर रहे हैं और जैसे एम्ज़ में खर्च आता है उतना ही खर्च यहां आ रहा है। ...(व्यवधान) हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत डॉक्टर्ज ट्रेन्ड कर दिए हैं। अगर हिमकेयर वाले स्पेशल वार्ड मांगते हैं तो उनसे भी 50,000 रुपये ही लिए जाते हैं। ...(व्यवधान)

**श्री बिक्रम सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या आयुष्मान भारत और हिमकेयर कार्ड वाले मरीज को एंटरटेन किया जाता है या नहीं?

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, **अभी मेरे पास इसकी सूचना नहीं है और मैं यह सूचना बाद में दे दूंगा।**

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने जो प्रश्न पूछा है, मैं भी उसी के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि क्या रोबोटिक सर्जरी आयुष्मान भारत और हिमकेयर कार्ड वाले मरीज के लिए लागू है या नहीं? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी के लिए कितना-कितना खर्च आता है। मैं

यह कह रहा था कि रोबोटिक सर्जरी के लिए डेढ़ लाख रुपये लगते हैं और गुर्दे, यूरोलॉजी या स्त्री रोग के लिए दो से अढ़ाई लाख रुपये की राशि लगती है। इसके अतिरिक्त हृदय की लेप्रोस्कोपी के लिए कम खर्च आता है और रोबोटिक सर्जरी पर आठ से दस लाख रुपये का खर्च आता है। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या आपका इस प्रकार से हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान कार्ड चल रहा है? आप हमें केवल यह जानकारी दीजिए। ठीक है, यह जो रोबोटिक सर्जरी

**टी सी द्वारा जारी**

**01.12.2025/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1**

**प्रश्न संख्या : 3618. क्रमागत्**

**श्री विपिन सिंह परमार... जारी**

उसमें चीरा बहुत-छोटा होता है और कैमरे के माध्यम से सर्जरी होती है जिससे संक्रमण कम होता है तथा ब्लड भी कम लॉस होता है। परंतु आप जो आंकड़े दे रहे हैं उनके अनुसार हिमाचल प्रदेश के लोगों की जेब हल्की हो रही है तथा आयुष्मान व हिमकेयर कार्ड का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। क्या आप इस माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे कि आने वाले दिनों में जब भी रोबोटिक सर्जरी होगी तो ऐसे मरीजों को इन दोनों कार्डों का लाभ मिल सकेगा।

दूसरा, आप तीन मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं इसलिए आप इस सदन में यह बताइए कि इसकी फंडिंग कहां से रही है, क्या जाइका के माध्यम से भारत सरकार की ओर से या फिर भारत सरकार का इसमें मैक्सिमम शेयर है? उन्होंने आपसे भी 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने और रोबोटिक यूनिट्स तथा इंस्ट्रूमैंट्स लगाने के लिए कहा है। अध्यक्ष महोदय, यही मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसकी पूरी फंडिंग राज्य सरकार कर रही है और कोई फंडिंग जाइका से नहीं हुई है। इसके अलावा अन्य तीन मेडिकल कॉलेजों की फंडिंग भी हिमाचल प्रदेश सरकार खुद कर

रही है। यह फंडिंग न जाइका से हो रही है और न ही भारत सरकार के माध्यम से हो रही है।

इसके साथ ही मैं जाइका के बारे में भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक, जाइका, ए0एफ0डी0 किसी प्रोजैक्ट को धनराशि देते हैं और 15वां फाइनेंस कमीशन इसे रिकमेंड करता हैं कि आप वर्ष-दर वर्ष कितना पैसा ले सकते हैं। जाइका के द्वारा हमने प्रोजैक्ट बनाया है और इसे रिकमेंडेशन के लिए आगे भेजा है ताकि मेडिकल कॉलेजों के अलावा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल सके। यह प्रोजैक्ट उसी के तहत आएगा। अभी इसकी कोई स्वीकृति नहीं मिली है और जब

**01.12.2025/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2**

भारत सरकार का एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट इसे स्वीकृति देगा उसके बाद जाइका की मीटिंग होगी और तभी इसकी स्वीकृति मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड की बात है पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने खुद बता दिया कि इसका इलाज काफी महंगा है लेकिन हम पी0जी0आई0 के रेट के अनुसार तीस हजार रुपये और पचास हजार रुपये में इलाज कर रहे हैं। ... (व्यवधान) दोनों कार्ड नहीं चल रहे हैं अभी इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन यदि पी0जी0आई0 में हिमकेयर या आयुष्मान भारत कार्ड चल रहे हैं तो उस सुविधा को देने पर विचार किया जाएगा।

**01.12.2025/1455/टी0सी0वी0/वाई0के0/-3**

**प्रश्न संख्या : 3619**

**श्री किशोरी लाल जी** : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, वह मुझे उपलब्ध हुई है जिसमें लिखा है कि बैजनाथ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने

वाली खड्डों से कोई भी रॉयल्टी वसूली नहीं की जाती है। इसकी वजह से कूहलों के बांध और इरिगेशन स्कीमों के पंप हाउस के पास से लोग धड़ले से रेत और बजरी उठा रहे हैं जिससे कूहलों का आस्तित्व ही खत्म हो जाएगा तथा ये स्कीमें नहीं चल सकेंगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। जहां कूहलों के बांध हैं और लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें चालू होनी हैं उन क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाए और वहां से रेत-बजरी न निकाली जाए ताकि किसानों को पानी मिल सके।

**उद्योग मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न किया है मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इनके एरिया में इस तरह की कोई भी माइनिंग लीज नहीं दी गई है क्योंकि इनके विधान सभा क्षेत्र में बिनवा खड्डु पर बहुत-सारी स्कीमें, ब्रिज और अन्य संरचनाएं हैं तथा लीगल माइनिंग लीज के लिए वहां पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। इनके क्षेत्र की आवा खड्डु में एक ऑक्शन की गई थी लेकिन किसी ने लीज के लिए अप्लाई नहीं किया।

जहां तक इल्लीगल माइनिंग का प्रश्न है हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोकल लोग अवैध रूप से रेत निकालते हैं उनके अगेंस्ट उचित कार्रवाई हो ताकि वहां वाटर सप्लाई स्कीमें, पुल और अन्य संरचनाएं डैमेज न हों।

**अध्यक्ष :** प्रश्न काल समाप्त। ...(व्यवधान) श्री रणधीर शर्मा जी जीरो ऑवर से संबंधित कोई रेफरेंस है

एन0एस0 द्वारा जारी .....

01-12-2025/1500/NS-YK/1

अध्यक्ष -----जारी

आप इसको सभा पटल पर रख दें we will take cognizance of this. श्री जय राम ठाकुर जी आपने कुछ रेफरैंस करना है?

**व्यवस्था का प्रश्न**

**श्री जय राम ठाकुर** : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। हमने दिनाकं : 27 दिसम्बर, 2025 को एक विषय उठाया था जिसका आज भी थोड़ा जिक्र हुआ है कि चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते हमें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि बजट की कमिटमैंट के साथ उसमें जो बजट ऐलोकेटिड है और बजट बुक में जो बजट का प्रोवीजन किया गया है उसके तहत मिलनी चाहिए। हमें इस बात को लेकर बहुत दुःख है कि हमारे पास एकमात्र जरिया जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध है वह विधायक क्षेत्रीय विकास निधि है। सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास निधि की दो इंस्टालमैंट्स जारी की हैं लेकिन इसमें भी ऐसा है कि जो पैसा हम स्वीकृत करके भेज रहे हैं वह पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। मैं अगर अपने जिला मण्डी की बात कहूं तो कुल विधायक निधि हमें दो इंस्टालमैंट में जिला मण्डी के अंतर्गत सभी विधायकों को 1.10 करोड़ रुपये मिली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात कहूं तो उसमें से टोटल अमाउंट जो मैंने सैंक्शन किया है वह 71.96 लाख रुपये है लेकिन इसमें से अभी तक रिलीज हुआ पैसा सिर्फ 24.50 लाख रुपये हैं। हम सैंक्शन्ज भेज चुके हैं। इसके चिट्ठियां प्रधानों व विभागों के पास पड़ी हुई हैं। इसके बावजूद प्रधान बोलते हैं कि हमारा कार्यकाल पूरा हो गया है और हम इस चिट्ठी का क्या करें पैसा तो आया ही नहीं। विधायक की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। नेताओं की एक समस्या यह है और उसके लिए हम भी जिम्मेवार हो सकते हैं। भरोसा टूटा है। लोग हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको लगता हो कि जाली चिट्ठी बना कर इन्होंने हमें स्वीकृति दे दी है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। हमारी इसमें बहुत बड़ी फजीयत व बदनामी हो रही है। इसलिए मैं इस बात को इस माननीय सदन में रख रहा हूं क्योंकि रिकॉर्ड साफ व स्पष्ट रहना चाहिए। इसी संदर्भ में 27 तारीख को हम विधान सभा के गेट नम्बर : 3 के सामने थोड़े देर के लिए धरने पर भी बैठे थे कि हमें विधायक क्षेत्रीय विकास निधि दे दीजिए, विशष तौर से उन इलाकों में

01-12-2025/1500/NS-YK/2

जहां आपदा या त्रासदी आई है क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से और पैसा नहीं आ रहा है। अगर विधायक क्षेत्रीय विकास निधि आती तो कम से कम टूटे हुए रास्त, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए स्कूल भवनों को थोड़ा रिस्टोर करने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए

हम स्पष्ट चाहते हैं। जब हमारा फाइनैंशियल ईयर क्लोजर की तरफ बढ़ रहा है तो अभी तक तीसरी इंस्टालमैंट जारी नहीं हुई है। आप तीसरी की बात छोड़ो, अभी तो दूसरी इंस्टालमैंट जो आपने जारी की है उसका पैसा रिलीज नहीं किया है। क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप शीघ्र पैसा रिलीज करेंगे ताकि विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जो विकास कार्यों के लिए रिकोमैंडेशन की है उसके लिए पैसा लग सके? मेरा आपसे यही आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में हिमाचल का प्रदर्शन अच्छा है। हमारे यहां से क्रिकेट जगत में रेणुका ठाकुर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.12.2025/1505/RKS/yk-1

श्री जय राम ठाकुर...जारी

हम उनको बधाई देते हैं। भारतीय क्रिकेटर सुषमा जी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हम उन्हें पहले ही डी0एस0पी0 रैंक पर नियुक्ति दे चुके हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने रेणुका ठाकुर को एक करोड़ देने की घोषणा की है। इसी तरह वर्ष 2025 महिला कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ जिसमें हिमाचल प्रदेश से पांच बेटियों ने भाग लिया। इस टीम की कैप्टन ऋतु नेगी सिरमौर जिला के शिलाई क्षेत्र से संबंध रखती है। इतिहास में हमारा देश पहली बार कबड्डी में महिला वर्ल्ड कप जीत कर लाया और इस टीम में हिमाचल प्रदेश की बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप उन बेटियों को आर्थिक रूप से सम्मानित करते हुए उन्हें सरकारी क्षेत्र में नौकरी देंगे? मैं मुख्य मंत्री जी के समक्ष इस विषय को लेकर अपनी बात कह रहा हूं। धन्यवाद।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, आप विपक्ष पर बहुत कृपा दिखाते हैं। विपक्ष के नेता ने एक मुद्दे को लेकर प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था लेकिन इन्होंने दो विषय उठा दिए। यह आपकी लोकतांत्रिक सोच का परिणाम है जिसके कारण आप विपक्ष को बोलने के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। यह सही है कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि विधायक का अधिकार है। यह भी सही है कि प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमें दो इंस्टॉलमेंट देने के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट देने में दिक्कत आ रही है। मेरा यह भी मानना है कि विधायकों को पिछले कुछ समय से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों का वेतन/भत्ते संबंधित बिल 7 महीने पहले पास हुआ था। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने ठीक कहा कि जनता ने हमें इस बारे में बहुत कुछ लिखा। जब हमने कागज ले किए तो भी हमें बहुत कुछ लिखा गया लेकिन विधायकों को आजतक संशोधित वेतन/भत्ते नहीं मिल पाए। सभी विधायकों का यह कहना था कि जो हमारे वेतन/भत्ते बढ़ाए गए हैं इसका हमें क्या फायदा हुआ? विधायकों को इन्कम टैक्स, बिजली का बिल, मकान का किराया और मोबाइल का बिल अपनी सैलरी से देना पड़ रहा है। इसमें 60 हजार के तकरीबन कट लगा हुआ है। हिन्दुस्तान में केवल हिमाचल प्रदेश विधान सभा के विधायक ही इन चीजों को अपनी जेब से पे कर रहे हैं। इससे पहले इन चीजों पर विधायकों के

01.12.2025/1505/RKS/yk-2

वेतन/भत्तों से कटौती नहीं होती थी। इसका पूरा वहन सरकार द्वारा किया जाता था। सरकार की तरफ से विधायक का 30-40 हजार इन्कम टैक्स पे किया जाता था। अब विधायकों को 5 हजार मकान का किराया और पानी एवं बिजली का बिल अपने वेतन/भत्तों से वहन करना पड़ रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें आर0डी0जी0 पहले की अपेक्षा कम मिल रही है। जब वर्ष 2017-18 में स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने सत्ता संभाली तो उस समय 14वें और 15वें वित्तायोग में आर0डी0जी0 के 8000 करोड़ रुपये आए। फिर यह राशि कम हो गई। इनके समय पहले तीन सालों में 11000 करोड़ रुपये, 10,000 करोड़ रुपये और फिर 9000 करोड़ रुपये आए और उसके बाद हमारे समय में 8000 करोड़ रुपये

और 6000 करोड़ रुपये आए। इस समय हमें 3200 करोड़ रुपये आ रहे हैं। हम 11000 करोड़ रुपये से सीधे 3200 करोड़ रुपये पर पहुंच गए। हमें 8000 करोड़ रुपये का गैप पड़ गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन/भत्ते और पेंशन भी सरकार को देनी है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पूरे सदन के सामने प्रदेश की आर्थिक स्थिति की तस्वीर रखना चाहूंगा। भविष्य में चाहे जो भी सरकार आए लेकिन हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना है। हमारी स्थिति इस समय ऐसी है कि हमें दिनचर्या का खर्च चलाने के लिए सभी प्रकार की चीजों में कट लगाना पड़ रहा है। हम संसाधनों का उचित उपयोग कर सही जगह पैसा दे रहे हैं। हमारी इस विषय पर भारत सरकार से बात चली हुई है। हमारी स्थिति और टाइट इसलिए भी हो गई क्योंकि हमने अपनी पहली कैबिनेट में ओ0पी0एस0 बहाल की जिस कारण केंद्र सरकार ने हमारी 1600 करोड़ रुपये की अडिशनल बॉरोइंग बंद कर दी। हमारी हर साल 1600 करोड़ रुपये ऋण लेने की लिमिट बंद कर दी गई जिससे गत तीन वर्षों में हमारी 4800 करोड़ रुपये की अडिशनल बॉरोइंग बंद हो गई।

श्री... बी0एस0द्वारा जारी

01.12.2025/1510/बी.एस./एजी.-1

**मुख्य मंत्री जारी...**

उसके कारण भी हमारी पोजीशन में फर्क पड़ा है। मैं पिछले दिनों फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला और फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने अनुरोध किया कि आप हमें दो परसेंट के एडिशनल बोरिंग दीजिए। उनका भी एक क्वेश्चन था कि आपने ओ0पी0एस0 दे दिया परंतु पूरे हिंदुस्तान में तो ओ0पी0एस0 बंद हो रहा। अगर आप ओ0पी0एस0 न देते तो आपकी 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग बंद न की जाती। मैंने फिर भी उनसे प्रार्थना की और मैं माह जनवरी में जाकर फिर उनसे मिलूंग और उन्होंने बोला है कि आप जनवरी में आएं फिर हम आपके बात करेंगे कि कैसे आपकी स्थिति को संभाल जा सकता है और हमने उनके पास पूरे आंकड़े भी दिए हैं और यह आंकड़े भी पूरे तथ्य के साथ दिए। फाइनेंस कमीशन के पास भी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जानते हैं कि हमने अपने पॉइंट को रखा है।

फाइनेंस कमीशन से भी हमें ज्यादा अवार्ड की उम्मीद नहीं लगती है क्योंकि जिस प्रकार की हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई है तो उन्होंने और स्टेटस का भी पर कैपिटल इनकम की बात की है। यह आने वाली स्थिति केवल हमारे लिए ही नहीं है कि यह केवल हमारी सत्ता में ही है। यह स्थिति आने वाले पूरे 5 सालों के लिए है। पांच सालों में क्या स्थिति रहेगी उन चीजों पर हमें सोचना पड़ेगा और गहन विचार करना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि अभी हमारी स्थिति थोड़ी गंभीर है, मैं तो यह सोच रहा हूं कि विधायक रोज ही मुझे पूछते हैं कि बढ़ा हुआ पैसा कब देंगे। आपने हमें क्यों गाली दिला दी, उनकी पेंशन इस महीने खाते में पड़ जाए तो भी गणित होगी। मुझे इसकी संभावना अभी कम ही लग रही है और जो ऐछिक निधि की बात और विधायक निधि की बात है इसके लिए थोड़ा जनवरी तक हमें इंतजार करना पड़ेगा अगर फाइनेंस मिनिस्टर हमें कुछ सहयोग देंगे मैं तभी उसके बारे में आगे कह सकता हूं। अभी हमारी स्थिति अच्छी नहीं है।

**अध्यक्ष** : मुख्य मंत्री जी, आप स्टेटमेंट देना चाह रहे थे।

01.12.2025/1510/बी.एस./एजी.-2

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो कबड्डी में हमारी बेटियां खेलने गई हैं उनके बारे में दूसरा मुद्दा उठाया है, उन्हें भी पता है कि उन्हें कितना पुरस्कार मिलना है। मैं अभी उनको स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी मिला हूं। पिछली बार उनको कुछ नहीं मिलता था। वे साउथ एशियन गेम्ज में गई थी और कबड्डी की खिलाड़ी भी गई थी तो उनको हमने 33-33 लाख रुपए दिया था। हिमाचल प्रदेश से रेणुका ठाकुर एकमात्र खिलाड़ी थी जिसने इंडिया में वर्ल्ड कप फाइनल जीता और उसी तरह कबड्डी की टीम ने भी जीता है। जो प्रोपोशनल रेट पर है उन बेटियों को पता है। हम एक राज्य स्तरीय फंक्शन करते हैं उसमें यह पुरस्कार दिए जाते हैं और इनको भी दिया जाएगा और रेणुका को भी दिया जाएगा। हमने पिछली बार घोषणा की है और पिछली बार उनको कोई प्राइस नहीं था। साउथ एशिन गेम जीत कर आई तो 33 लाख रुपये दिया था। वर्ल्ड कप में तो उनको पता होगा कि कितना-कितना पैसा मिलेगा। जैसे ही राज्य सरकार अपना कार्यक्रम करेगी उस समय उनको यह जो भी प्राइस है, जो भी वर्ल्ड कप के अनुसार वर्ल्ड कप टीम के अनुसार जो

प्राइस बंटता है जैसे 5 करोड़ रुपये का हमारा प्राइस है और इसे हम बांटते हैं। **जो पांच खिलाड़ी गए हैं उनमें उसे बांटा जाएगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं**

**अध्यक्ष :** मुख्य मंत्री जी, आपके कुछ स्टेटमेंट देनी थी।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों और पेंशनों की देनदारियों के संबंध में वक्तव्य देना चाहता हूं। महोदय, भारतीय जनता पार्टी भी प्ले कार्ड लेकर बैठी हुई थी जिस दिन सरकारी कर्मचारी, सरकारी पेंशन भोगी जिन्होंने प्रदेश की सेवा की है वे जोरावर स्टेडियम में इकट्ठे हुए थे और मुझे भी उनके कुछ व्यक्ति मिले। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी और पेंशनरों की हितेषी रही है जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर के 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पारिवारिक पेंशनों को उनके बकाया पेंशन पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि 90 साल के भी आदमी वहां पर आए थे कि हमारे भी भुगतान नहीं हुए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसका भी 75 साल से ऊपर का कोई भी भुगतान है वह आकर जिस विभाग

01.12.2025/1510/बी.एस./एजी.-3

से रिटायर हुआ उसमें अपील कर सकता है। मेरा यह माना कि कोई भी ऐसा पेंशनर जो 75 साल से ऊपर के पेंशन संबंधि कोई भी एरियर का भुगतान हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा लंबित नहीं छोड़ा है, सारा भुगतान कर दिया गया है। हमारी सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन 70 प्रतिशत एरियर का भूगतान कर दिया है। पेंशनरों में 30 प्रतिशत भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा। इस पर लगभग 90 करोड़ रुपया खर्च होगा।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**01.12.2025.1515.डी0टी0-ए0जी0.-1**
**मुख्य मंत्री जारी...**

यानी इसी साल में 90 करोड़ रुपये का जो 70 साल से ऊपर छठे वित्त आयोग का जितना भी एरियर है, वह सारा भुगतान हम कर देंगे।

सरकार ने आयु के आधार पर पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस प्रकार किया हैः- 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। 70-75 वर्ष 70% भुगतान कर दिया गया है। इस वर्ष उनका भी पूरा भुगतान कर दिया जायेगा। 65-70 वर्ष का 38% एरियर का भुगतान कर दिया है। 58 से 65 वर्ष से कम 35% भुगतान कर दिया है।

सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2021 के दौरान सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके Gratuity एरियर के 20% भाग का भुगतान कर दिया गया है।

सरकार द्वारा कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर रुपये 50,000/-, प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों तथा रुपये 60,000/-, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।

सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20,000 रुपये का भुगतान दिनांक 19.10.2024 को किया गया ।

अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2155 करोड़ रूपये खर्च किये जा चुका है। वर्तमान में बकाया एरियर 8555 करोड़ रूपये है।

हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हित्त के फैसले लिए है। हमारी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है, इससे लगभग 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका मिला । इसके कारण केंद्र की सरकार ने हमारी 1600 करोड़ रुपये की एडिशनल बोरोइंगद बंद कर दिया। अभी कुछ समय पहले हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनके 5 साल की दैनिक सेवा के बदले 1 साल की qualifying service का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है। यानी जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और जो 8-9 साल की सर्विस पूरी कर गये उनको 10 साल सरकारी सेवा में पूर्ण न होने के कारण पेंशन नहीं मिलती थी, हमने उनको भी एक साल का अतिरिक्त लाभ देकर पेंशन की योजना में उनको ला दिया है।

**01.12.2025.1515.डी0टी0-ए0जी0.-2**

हमने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ्ढ बनाने के लिए कुछ आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा, और जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। कर्मचारियों एवं पेंशनर्ज से हमें अपेक्षा है कि वे प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु किए जा रहे प्रयासों में सरकार का साथ दें। हमने जो प्रयास आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए हैं, इस स्थिति में जब हमारी आर0डी0जी0 11000 करोंड़ रुपये से 32000 करोड़ रुपये हो गई है, आज भी हम सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और वेतन का भुगतान सही समय पर कर रहे हैं। तो निश्चिततौर पर आने वाले समय में जैसे ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, हम कर्मचारियों और पेंशनर्ज के एरियर का भुगतान करेंगे।

**01.12.2025.1515.डी0टी0-ए0जी0.-3**

## Zero Hour

**Speaker:** We have left with only 10 minutes. Whatever issues we can raise within 10 minutes, we see to it within 2-3 minutes if Members are in a position to raise their issues. Shri Jeet Ram Katwal. श्री जीत राम कटवाल जी आपका शून्य काल का इशू है क्या आप वह इशू उठाना चाहते है या नहीं?

**श्री जीत राम कटवाल द्वारा शून्य काल में "शिशु कल्याण परिषद में कार्यरत सेविकाओं को पिछले दो वर्ष से देय वेतनमान की अदायगी न होने से उत्पन्न स्थिति के बारे"में उठाया गया मामला।**

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, ये बाल सेविकाएं बालबाड़ी कार्यकर्ता हैं। पिछले विधान सभा सत्र के दौरान इसके बारे में चर्चा हुई थी और मैंने कहा था कि दो वषों से इन्हें मानदेय नहीं मिला है। इनमें से किसी को दो हजार रुपये मानदेय मिलता है और किसी को अढाई हजार रुपये मानदेय मिलता है और किसी को 1500 रुपये मानदेय मिलता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसका नोटिस लेते हुए कहा था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं लेकिन मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपये जारी कर दूंगा और इससे इनके मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा। यह पैसा भारत सरकार से आता है लेकिन in the mean time

इसका भुगतान करेंगे और ये बाल सेविकाएं जो बड़ी कठिनाइयों से अपना जीवन यापन करती हैं या बालबाड़ियों के अंतर्गत

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1520/ए.एस.-एन.जी./1**

**श्री जीत राम कटवाल........जारी**

बच्चों की देखभाल करती हैं और छोटी शिक्षा (शुरूआती शिक्षा) की व्यवस्था करती हैं। उन बच्चों को सम्भालना वास्तव में बहुत कठिन होता है और बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि इन्होंने पिछली बार पांच करोड़ रुपये देने की बात कही थी, उसे अभी जारी कर दें क्योंकि उन्हें यह पैसा जारी नहीं हुआ है। वे महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हैं। बाल सेविकाएं चाइल्ड वेल्फेयर काऊंसिल के अधीन होती हैं और इन्हें भारत सरकार से ग्रांट आती है। पिछले दो वर्षों से उसके लिए शायद कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और उसी कारण मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पांच करोड़ रुपये दे दिए जाएंगे। मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि इसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र गौर फरमाए। वे बाल सेविकाएं बहुत जरूरतमंद हैं और समाज का एक अहम तबका है। धन्यवाद।

**Speaker:** Hon'ble Chief Minister would you like to respond?...(Interruption). Hon'ble Chief Minister wants to respond to this issue.

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य द्वारा पिछली बार कही गई बात याद आ गई है और मैं इसके संदर्भ में पूरी डिटेल पता करूंगा कि ये पैसे क्यों जारी नहीं किए गए हैं। हम कोशिश करेंगे कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष :** अब क्या है? आपने बोल तो दिया है।...(व्यवधान) ठीक है, श्री जीत राम कटवाल जी, आप कहिए।

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि पांच करोड़ रुपये देंगे। इसका पैसा चाइल्ड वेल्फेयर काऊंसिल के माध्यम से भारत सरकार से आता है।

**01.12.2025/1520/ए.एस.-एन.जी./2**

मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि भारत सरकार से पैसा आता रहेगा और यह बात यहां पर रिकॉर्डिड भी है कि हम in the meantime पांच करोड़ रुपये अपने संसाधनों से जारी करेंगे। इन छोटे कार्यकर्ताओं पर बहुत जिम्मेवारी का काम जैसे छोटे-छोटे बच्चों की देखभाल व बालबाड़ियों को चलाने का काम दिया जाता है लेकिन इन्हें भुगतान हुए दो साल से भी ज्यादा समय हो गया है।

**Speaker:** Hon'ble Chief Minister has assured this House that he will look into this matter. ... (Interruption).

**श्री जीत राम कटवाल :** अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी को इनका आश्वासन संप्रेषित भी कर दिया था।...(व्यवधान) मेरा यही अनुरोध है कि इसे करवा दीजिए।...(व्यवधान)

**Speaker:** He has admitted that. Hon'ble Member, please take your seat. Hon'ble Chief Minister has assured this House that he will be taking cognizance of this issue. अगला विषय माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा रखा जाएगा।

**01.12.2025/1520/ए.एस.-एन.जी./3**

# पुहाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के दौरान हुई तीन व्यक्तियों की मृत्यु के संदर्भ में शुन्य काल के दौरान माननीय सदस्य, श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा उठाया गया विषय।

**श्री केवल सिंह पठानिया** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पुहाड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का काम चला हुआ है। वहां पर 10 दिन पहले भनाला क्षेत्र में पांच साल की बच्ची अंकिता पुत्री श्री अंकुश कुमार, पुहाड़ा में पुल की वेल्डिंग का कार्य करते हुए एक मजदूर पृथ्वी सिंह, आयु 40 वर्ष, और रैत में श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चंदो राम की मृत्यु हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने जो भी सवाल उठाए थे, वे सभी सच हैं क्योंकि उसी परिस्थिति से मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में तीन मौतें हुई हैं। श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री चंदो राम का मामला रैत में हुआ है और उस समय नेश्नल हाइवे का ठेकेदार भी वहीं पर था। यह व्यक्ति मिठाई की दुकान में काम करता है और वहां पर निर्माण कार्य के दौरान हुए एक खड्डे में गिर गया। वहां पर शाम को स्थानीय लोग और हम सब पहुंच गए थे लेकिन सात दिन तक नेश्नल हाइवे का एक भी आदमी इनके घर तक नहीं पहुंचा पाया। जब मैं और एस0डी0एम0 इनके घर पर गए तो ठेकेदार द्वारा पहले से ही वहां पर कंपनसेशन के नाम पर 50 हज़ार रुपये का एक झूठा चैक दे दिया गया था जोकि कैश नहीं हुआ। इसी प्रकार अंकिता और श्री पृथ्वी सिंह सुपुत्र श्री अमरीक मसही, निवासी गांव फहेलनंगल ब्लॉक धारिवाल, तहसील एवं जिला गुरदासपुर की मृत्यु हुई है। मेरे क्षेत्र में छतली, द्रमण, सापर, रैत, रजौल आदि तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम लगा हुआ है। पिछली बार मुझे आश्वासन दिया गया था कि उपायुक्त, कांगड़ा विजिट करेंगे। वहां पर इस निर्माण कार्य से लगभग 19 हैण्डपम्प और 45 बिजली के खम्बे डिस्टर्ब हुए हैं। वहां पर बिजली के कारण पशुओं की भी मौत हुई है। मैं

**01.12.2025/1520/ए.एस.-एन.जी./4**

चाहता हूं कि पिछली बार जो आश्वासन दिया गया था, चाहे वह हैण्डपम्पों को लेकर था या बिजली के खम्बों को लेकर था, उस पर अमल किया जाए। इसके अलावा जो अभी तीन मौतें हुई हैं तथा मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब सदन लगा था तो एक मौत हुई थी और उसके अलावा थोड़ा नुकसान हुआ था, इसके लिए माननीय राजस्व मंत्री ने कहा था

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

**01.12.2025/1525/ए0एस0-पी0बी0/1**

**श्री केवल सिंह पठानिया...जारी**

रिलीफ मैन्युल के आधार पर राहत दी जाएगी, वहां पर डिप्टी कमीश्नर भी जाएगा और नेशनल हाइवे के सारे मामलों को देखेगा। क्या डिप्टी कमीश्नर ने वहां जाकर अपनी रिपोर्ट दी है या वह वहां गया भी है या नहीं? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने भी यहां एक बड़ा मामला उठाया था और नेशनल हाइवे वालों के बारे में इन्होंने ठीक कहा है। जब मैंने भी नेशनल हाइवे वालों को बच्ची की मृत्यु के बारे में टेलीफोन किया तो उनका उल्टा ही जवाब आया कि नेशनल हाइवे निर्माण के दौरान ऐसी कई मृत्यु होती रहती हैं।

**Speaker :** Conclude please.

**श्री केवल सिंह पठानिया :** अध्यक्ष महोदय, एक चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा जवाब मिलता है। मैं उस समय चुप रहा लेकिन कभी किसी और विधायक को कोई मृत्यु हो जाने पर कंपनी या नेशनल हाइवे द्वारा यह कहा जाए कि ऐसी मौतें बहुत होती रहती है तो यह

किसी भी स्तर पर ठीक बात नहीं है। एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मेरा भी फर्ज़ बनता है कि मैं इस दिशा में अगला कदम उठाऊं इसलिए मैं यह चाहता हूं कि चाहे एन0एच0ए0आई0 हो या कोई अन्य कंपनी हो उनकी इस विषय पर जवाबदेही बनती है। जब आपने हस्तक्षेप किया था और कमेटी बनाई थी तो उस समय प्रभावितों को राहत राशि मिली थी। मैं चाहूंगा कि इस विषय में राजस्व मंत्री जी शीघ्र राहत देने का आश्वासन दें और साथ ही कल डिप्टी कमीश्नर की रिपोर्ट को सभा पटल पर भी रखें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछली बार डिप्टी कमीश्नर और एस0डी0एम0 के विजिट का जो आश्वासन दिया गया था क्या उन अधिकारियों द्वारा वह विजिट किया गया है?...(व्यवधान)

**Speaker :** This is a specific issue for the specific person. We cannot make it a debate.

**राजस्व मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे है कि आश्वासन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह विषय गंभीर है जिसका हम कड़ा संज्ञान

**01.12.2025/1525/ए0एस0-पी0बी0/2**

लेते हैं और **मैं दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रखूंगा।**

**अध्यक्ष :** अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया और श्री आर0एस0 बाली जी का एक और विषय शेष है। जिसे पठानिया जी ने 28 नवम्बर को दिया था और बाली जी ने आज दिया है। मैं आप दोनों को शून्यकाल में 2-3 मिनट का समय दूंगा please wind-up your issue because the time is slightly to finish यह विषय अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत करने बारे में है। पहले माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी अपनी बात रखेंगे।

**श्री केवल सिंह पठानिया** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला ओ0बी0सी0 का है। मैं सबसे पहले पूर्व की कांग्रेस सरकारों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ओ0बी0सी0 को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया और ओ0बी0सी0 फाइनेंस एंड डवलपमैंट कॉरपोरेशन का दफ्तर शिमला से कांगड़ा लाया है, उस वक्त स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री और प्रो0 चन्द्र कुमार जी मंत्री थे। कांगड़ा ओ0बी0सी0 बहुल इलाका है। जब स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी देश के एच0आर0डी0 मिनिस्टर थे, उस समय केंद्र सरकार ने ओ0बी0सी0 को मेडिकल संस्थानों में 18 प्रतिशत से 27 प्रतिशत के आरक्षण देने की बात कही थी। इस पर वर्तमान सरकार का क्या रुख है और क्या वह केंद्र की संस्तुति पर विचार करेगी? प्रदेश में इसी बीच कई सरकारें आई। पिछले वर्ष इस पर दो-तीन कमेटियां भी बनी थीं। क्या सरकार उन कमेटियों की सिफारिशों को लागू करना चाहती है? दूसरा, हमारे विधान सभा क्षेत्रों में ओ0बी0सी0 परिवारों के मकान बनाने के लिए राशि आती है। प्रदेश में कांगड़ा, ऊना और पांवटा-साहिब ओ0बी0सी0 बहुल क्षेत्र है लेकिन कई जिलों में ओ0बी0सी0 की जनसंख्या नहीं है वहां इन मकानों को बनाने के लिए जो राशि बाइफरकेट होकर जाती है, मैं उसके बारे में भी मंत्री जी से जानना चाहता हूं। मेरे यही दो प्रश्न हैं और मेरे पास केवल डेढ मिनट का ही समय है क्योंकि इस विषय पर आदरणीय बाली साहब ने भी आपनी बात रखनी है। हिमाचल प्रदेश की जो भी कंसर्निंग अथॉरटीज हैं वह हमें इस बारे में सीधा अपना पक्ष बता दें क्योंकि कांगड़ा, धर्मशाला और शाहपुर में ओ0बी0सी0 के

**01.12.2025/1525/ए0एस0-पी0बी0/3**

प्रतिनिधि हमसे इन विषयों पर बार-बार सवाल करते हैं। इस संदर्भ में मुख्य मंत्री जी ने कमेटी की रिपोर्ट भी मंगवाई है। हम यह चाहते हैं कि ओ0बी0सी0 को मेडिकल ऐजुकेशन में 27 प्रतिशत का आरक्षण मिलना चाहिए।

**01.12.2025/1525/ए0एस0-पी0बी0/4**

**श्री आर0 एस0 बाली :** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगण का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी हमेशा सदन की गरीमा को बनाए रखने और सदन को चलाने के लिए अध्यक्ष महोदय का सहयोग देते हैं। मैं आज जिस इशू के लिए यहां खड़ा हुआ हूं

**श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

01.12.2025/1530/D.C./A.P./ 01

**शून्य काल जारी .....**

**श्री आर0एस0 बाली जारी .....**

वह अत्यंत संवेदनशील, गंभीर, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ और सामाजिक न्याय से संबंधित है। वर्ष 2005 में जब केंद्र में यू0पी0ए0 की सरकार थी और स्वर्गीय डॉ0 मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय सरकार द्वारा 93वां संविधान संशोधन के तहत एक प्रावधान जोड़ा गया। यह प्रावधान ओ0बी0सी0 वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग की शिक्षा के लिए था, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में ओ0बी0सी0 के लिए आरक्षण बढ़ाया जा सके। 93वां संविधान संशोधन वर्ष 2006 में लागू किया गया और इसके बाद केंद्र सरकार के सभी बड़े संस्थानों -चाहे एम्स हों या आई0आई0टी0 - देश के सर्वोत्तम संस्थानों में ओ0बी0सी0 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देना शुरू कर दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इनके लिए आरक्षण लागू किया गया। हमारे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ संस्थानों में 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, तकनीकी शिक्षा संस्थान में ओ0बी0सी0 वर्ग के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। यह आरक्षण भी कांग्रेस की पिछली सरकार के समय से दिया गया था। लेकिन हमारे पूरे शिक्षा ढांचे में यह आरक्षण समान रूप से लागू नहीं है। जो 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वह भी यूनिफॉर्म नहीं है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मैं एक

ओ0बी0सी0 बहुल क्षेत्र से आता हूं और हर वर्ग की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। हर वर्ग को सामाजिक न्याय और हमारे लोकतांत्रिक समाज में संविधान के तहत जो भी अधिकार दिए गए हैं, वे उन्हें मिलने चाहिए, जिसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ओ0बी0सी0 समाज को 93वें संविधान संशोधन द्वारा दिए गए अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को समान रूप से 18 प्रतिशत किया जाए और 93वें संविधान संशोधन में दिए गए 27 प्रतिशत अधिकार को लागू करने के बारे में सरकार गंभीरता से विचार करे। मुझे लगता है कि यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

**अध्यक्ष** : माननीय मुख्य मंत्री जी।

**01.12.2025/1530/D.C./A.P./ 02**

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, सभी बातों का कानूनी तौर पर अध्ययन करने के बाद ही इस पर कोई विचार किया जा सकता है।

**श्री आर0एस0 बाली** : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत ही गंभीर है। हर वर्ग की आवाज माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचती है। इस विषय पर गहन चिंतन, गंभीर मंथन और ठोस निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। 18 प्रतिशत जो अभी आरक्षण यूनिफॉर्म नहीं है कम- से-कम सरकार इसको सबसे पहले यूनिफॉर्म तो करें। आपने मुझे बोलने का मोका दिया आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**Speaker** : Hon'ble Member Shri Raghuvir Singh Bali the issue which you have raised, Hon'ble Chief Minister has already said that he will study this issue thoroughly as per the legal provision and the Constitutional Amendment which are referred by you and thereafter he will come to the House with the detailed reply. Thank you. अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी, भरमौर, हडसर, मैहला में करवाए जा रहे सिवरेज कार्य के विषय में अपने विचार रखेंगे। वैसे तो यह समाप्त है,

लेकिन फिर भी I am giving you a chance. We will take up all the issues under Zero Hour.

**डॉ0 जनक राज** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र के भरमौर, मैहला, छतराड़ी और पांगी के किलाड़ क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से सीवरेज का कार्य चल रहा है। यह कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। सड़कों को उखाड़ दिया गया है, जिससे लोगों को चलने में असुविधा हो रही है। जब विभाग से सड़कों को ठीक करने और जगह-जगह हो रही लीकेज को सुधारने की बात की जाती है, तो विभाग इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि इन स्थानों पर सीवरेज कार्यों से उत्पन्न कमियों को जल्द-से-जल्द दूर किया जाए ताकि लोगों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

**01.12.2025/1535/AT/ DC/.01**

**Speaker:** This House has taken cognizance of this serious issue and we will be asking the Department to look into this matter. The Hon'ble Minister in-charge will respond on the issue to the House. Thank You. Next issue will be raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharma Ji.

**श्री रणधीर शर्मा:** अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय जल शक्ति विभाग से संबंधित है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय तो आए नहीं, यह भी पता नहीं कि कौन-से मंत्री इसका उत्तर देंगे।

**अध्यक्ष:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल जी हैं।

**श्री रणधीर शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बहुत गंभीर है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की भयंकर समस्या हो गई है। हालांकि पानी के सोर्सेस हैं परंतु उसके बावजूद लोगों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इसका एक कारण बरसात में जो नुकसान हुआ

लैंडस्लाइड हए जिससे पाइपलाइन टूटी, पर उनकी रिपेयर नहीं हुई। विभाग से बात करो तो कहते हैं पाइप नहीं है। किसी तरह प्लास्टिक की पाइप जोड़कर पानी देने की कोशिश की, परंतु वह बार-बार कभी पशुओं से, कभी अन्य कारणों से टूट जाती है और लोगों तक पानी ही नहीं पहुंचता।

दूसरा यह है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्टाफ की बहुत कमी है। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जे0ई0 की पोस्ट हैं जिनमें से 9 खाली हैं। आप समझ सकते हैं कि 9 जे0ई0 की पोस्ट खाली होने से कितनी दिक्कत होती है। यह आप जान सकते हैं। दुसरा फील्ड स्टाफ वह तो बिल्कुल नहीं है। अधिकतर स्कीमें ठेकेदारों के माध्यम से चल रही थीं परंतु ठेकेदारों को सरकार पेमेंट नहीं कर रही। लेबर को 6 महीने, 1 साल से पेमेंट नहीं मिली है। कोई बेलदार है, कोई पंप ऑपरेटर है पैसा न मिलने से वह काम नहीं कर रहे। कुछ छोड़कर चले गए हैं, कुछ धरने पर बैठे हैं। कुल मिलाकर, पानी की समस्या इन दो कारणों से भयंकर रूप ले रही है। इसके साथ-साथ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सिंचाई का चेंगर एरिया मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। वर्ष-2007 से वर्ष- 2012 के बीच इस पर 100 करोड़ रुपये खर्च करके इसे बनाया गया था। इसमें 2300 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है, ... (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय,9 पंचायतों में

**01.12.2025/1535/AT/ DC/.02**

सिंचाई की सब-डिवीजन है उसमें 5 जे0ई0 की पोस्ट हैं और पांचों ही खाली। मैं यह मुद्दा दो नहीं, तीन नहीं, चार बार विधान सभा में उठा चुका हूं परंतु अभी तक पोस्टें नहीं भरी गईं। उसके बावजूद वहां भी यही समस्या है कि बरसात में पाइपलाइन टूटी, उसकी रिपेयर का टेंडर दे दिया गया है। परंतु वह ठेकेदार काम नहीं कर रहा। वह कहता है कि मेरी पिछली पेमेंट नहीं हुई है। जो लेबर उसने लगाई थी उन्हें पेमेंट नहीं मिली, इसलिए वे मजदूर काम नहीं कर रहे। कुल मिलाकर, पैसे की समस्या के कारण, पीने के पानी और सिंचाई दोनों की समस्या खड़ी हो गई है। लोगों ने अब गेहूं की फसल बीज दी, अब वहां पानी लगाना है, पर पानी उपलब्ध नहीं है। लोग सड़कों पर आने को तैयार हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर तुरंत कोई व्यवस्था की जाए। ठेकेदारों की पेमेंट की जाए। वहां पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमों की जल्द मरम्मत

करवाकर इस समस्या का समाधान किया जाए। यह निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

**Health & Family welfare Minister( Authorized):** The issue raised by Hon'ble Member Shri Randhir Sharmaji in this august House is of people oriented problems. He has said that drinking water and irrigation pipes are broken and people are not getting water for drinking and for irrigation. The pipes are also not available. Secondly he has said that there is shortage of staff also which is very serious issue. I will brief this issue to Hon'ble Deputy Chief Minister and definitely he will give you a detailed reply on this.

**Speaker:** This House has also taken a cognizance on this very serious issue. We will be conveying it to the respective Department and we will definitely want the Hon'ble Deputy Minister as and when he comes to the Vidhan Sabha; to respond to this issue.

एम0डी0 द्वारा जारी ......

**1-12-2025/1540/HK/MD/1**

अध्यक्ष---**जारी :**

he responds to this issue. जीरो आवर समाप्त and all the issues listed for today's Zero Hour वे भी समाप्त हुए। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी भाग लेंगे।

**श्री नीरज नैय्यर** : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी लीवरेज ले रहा हूं, एक समस्या इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज स्पोर्टस से जुड़ा मुद्दा चर्चा में आया। मैं आपके माध्यम से माननीय

मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे जिले के दो स्पोर्ट्स स्टार हैं हमारे इलाके से एक सीमा है जिन्हें उड़न परी कहा जाता है and she is a Olympic prospect. I have seen her running. सीमा लगातार नेशनल और इंटरनेशनल दोनों स्तरों पर गोल्ड मेडल जीत रही हैं। लेकिन सरकार की वर्तमान नीति केवल ओलंपिक, एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने पर ही आर्थिक सहायता देती है। जबकि अन्य मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों की अनदेखी की जाती है। शूटिंग के अंदर मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा एक लड़का है जिसका नाम है फरहान मिर्जा उसको मैंने अपनी निधि से 2 लाख रुपये दिए, उसकी टिकट के भी पैसे दिए और एन0एच0पी0सी0 से भी कुछ पैसे दिलवाए। कोरिया के अंदर जिसमें 25 देशों ने भाग लिया and he won the bronze medal. लेकिन जब मैंने स्पोर्ट्स सचिव से बात की तो उन्होंने बताया कि हम इनको कंसीडर ही नहीं करते है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के यात्रा, टिकट, ठहरने और भोजन जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं का खर्च सरकार वहन करे, ताकि इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके और वे आगे बढ़ सकें।

**1-12-2025/1540/HK/MD/2**

## शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

**Speaker :** I think Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Minister for the Sports & Youth Services has taken a cognizance of this matter and will be certainly looking into it. अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सत्र की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सत्र की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं, जोकि इस प्रकार से है:-

सोमवार दिसम्बर 01 शासकीय/विधायी कार्य।
मंगलवार दिसम्बर 02 शासकीय/विधायी कार्य।

बुधवार दिसम्बर 03 शासकीय विधायी कार्य।
वीरवार दिसम्बर 04 (i) शासकीय/ विधायी कार्य।
(ii) गैर-सरकारी सदस्य कार्यदिवस
शुक्रवार दिसम्बर 05 शासकीय/विधायी कार्य।

## स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

**अध्यक्ष :** अब सचिव, विधान सभा, सदन द्वारा पारित उस विधेयक की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

**सचिव (विधान सभा)** - अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का अधिनियम संख्यांक 45) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

**1-12-2025/1540/HK/MD/3**

## कागजात सभा पटल पर

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता (छठा संशोधन), 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/Supply Code/438, दिनांक 17.03.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.03.2025 को प्रकाशित;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग संसाधन पर्याप्तता विनियम के लिए ढांचा, 32025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/RA/TTE/0225, दिनांक 28.04.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.05.2025 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विचलन निपटान विनियम (द्वितीय संशोधन) तंत्र और संबंधित मामले, 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC-H(1)25/2024, दिनांक 15.07.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.07.2025 को प्रकाशित;

**1-12-2025/1540/HK/MD/4**

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम (संशोधन), 2025 जोकि अधिसूचना संख्याः HPERC/151-Vol-III-2081, दिनांक 10.09.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.09.2025 को प्रकाशित; और

(v) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 394 (2) के अन्तर्गत एसजेवीएन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 ।

## सदन की समितियों के प्रतिवेदन

**अध्यक्ष** : अब माननीय श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2025-26), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगेः-

**श्री मोहन लाल ब्राक्टा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं :-

1. समिति का 44वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में संचालित "मुख्यमन्त्री शगुन योजना" की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित है; और

समिति का 45वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के अन्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों/ योजनाओं की संवीक्षा पर आधारित समिति के 23वें मूल

**1-12-2025/1540/HK/MD/5**

2. प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत्त कार्रवाई पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है।

**अध्यक्षः.......श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**01.12.2025/1545/केएस/एचके/1**

**अध्यक्ष : अब श्री संजय अवस्थी, सभापति मानव विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।**

**श्री संजय अवस्थी** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, (वर्ष 2025-26), का 31वां मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

## नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

**अध्यक्ष** : अब श्री आर0एस0 बाली, माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। श्री आर0एस0 बाली जी यदि चाहें तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण भी ले सकते हैं।

**श्री आर0 एस0 बाली** : अध्यक्ष महोदय, नियम-63 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया, आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय, टांडा मैडिकल कॉलेज हमारे निचले हिमाचल प्रदेश की एक लाइफलाइन है और एक ऐसा मैडिकल कॉलेज है जिसके ऊपर पूरा निचला हिमाचल निर्भर करता है। लोग दूर-दराज़ के क्षेत्रों से वहां आते हैं और जब अलग-अलग पी.एच.सी., सी.एच.सी. और जोनल हॉस्पिटल से उनको आगे रैफर किया जाता है तो वे टांडा पहुंचते हैं। एक मल्टी-स्पेशलिटी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए अनेकों सरकारों ने, अनेकों ऑफिसरों ने योगदान दिया तथा जिसको डॉक्टरों ने अपने खून-पसीने से सींचा, तब वह अस्पताल तैयार हुआ और आज लोगों की सेवा कर रहा है। आज इस माननीय सदन के सभी के सभी सदस्य इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने इसके लिए रात-दिन प्रयास किया और एक दूर दृष्टि के साथ काम किया जिसकी वजह से जो हमारी मांगें वर्ष 2010 से लम्बित थीं, वे पूरी हुईं। क्योंकि यह एक बड़ा संवेदनशीन मुद्दा है तो पहले मैं पॉज़िटिव बातों की ओर जाना चाहता हूं फिर अपनी ज़रूरतों की तरफ आना चाहूंगा। वर्ष 2010 से इस अस्पताल की कुछ हिस्टोरिक डिमांड्ज़ जो पूरी हुईं, पहले मैं

**01.12.2025/1545/केएस/एचके/2**

उनके बारे में बताना चाहूंगा। पूरी कैबिनेट तथा मुख्य मंत्री जी ने जो खास समय दिया, आज पूरे देश में इतने ज्यादा अस्पताल हैं परंतु इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी वहां नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या कोई भी जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसको इमरजेंसी डियूटी में रखना, ऐसा हिस्टोरिक डिसिजन, ऐसी हिस्टोरिक सोच के तहत हुआ। आज अलग-अलग श्रेणियों के 10 असिस्टेंट प्रोफेसर्ज़ की पोस्टें क्रिएट हुईं। कार्डियो, न्यूरो, गैस्ट्रो तथा अलग-अलग श्रेणियों के डॉक्टर्ज़ आए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सुपरस्पेशलिटी, एस0आर0 की डिमांड वर्ष 2010 से पैंडिंग थी। वर्ष 2025 में उनकी 27 पोस्टें नई क्रिएट हुईं हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। कार्डियो, रेडियो, सी.टी.वी.एस. आदि की पोस्टें भरी जाएंगी। टांडा अस्पताल को आगे जोड़ने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। रोबोटिक सर्जरी और अन्य चीजों के साथ उसको जोड़ा गया। एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि आज एक पैट स्कैन मशीन का एम.ओ.यू. भी साइन हो गया जो बहुत जल्दी टांडा मैडिकल कॉलेज में आ जाएगी। एम.आर.आई. की मशीन के लिए 10 करोड़ रुपये की पेमैंट हो गई है। वह भी वहां लगने वाली है। एक्सरे की मशीन का सप्लाई ऑर्डर प्लेस हो गया है। हमारी 8 लिफ्टों की समस्या थी जो हमने मांगी और उनके लिए भी 3 करोड़ रुपये रिसीव हो गए हैं जिससे हमारी 8 लिफ्टें ठीक हो जाएंगी। अध्यक्ष जी, ये अचीवमैंट्स हैं। इनकी सराहना करना भी ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर काम हुआ है। मुख्य मंत्री जी तीन-चार बार वहां खुद आए हैं, मीटिंग ली है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री धनीराम शांडिल जी, वरिष्ठ मंत्री ने प कई बार खुद आ कर इसके ऊपर मीटिंग भी ली, काम भी किया, उसका जायजा भी लिया और मुख्य मंत्री महोदय के साथ आ कर निर्णय भी लिया और उसके ऊपर काम भी हुआ।

---

अध्यक्ष जी, टांडा मैडिकल कॉलेज में आज इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज वहां पर रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है। आज तक वहां पर लगभग 20 रीनल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**01.12.2025/1550/av/yk/1**

**श्री आर0एस0 बाली------- जारी**

एक रीनल ट्रांसप्लांट के लिए पूरा परिवार बाहर जाता है। रीनल ट्रांसप्लांट से पहले चार महीने लगते हैं और उसके बाद पोस्ट केयर के लिए भी चार महीने का समय लगता है क्योंकि किसी के शरीर का अंग किसी दूसरे के शरीर में जाता है तथा उसके इम्यून सिस्टम को ठीक होने में समय लगता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से चार महीने पहले और चार महीने बाद में, लगभग आठ महीने से एक वर्ष का समय लग जाता है। उसके लिए पूरा परिवार अपने घर से बाहर रहता है तथा करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। अगर पी0जी0आई0 या एम्ज़ में जाएं तो गरीब आदमी का लाखों रुपया लगता है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 20 से ज्यादा रीनल ट्रांसप्लांट हो चुके हैं और एम्ज़, बिलासपुर में अभी तक दो ट्रांसप्लांट ही हुए हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो यह बहुत कम आंकड़ा है। टांडा मेडिकल कॉलेज की जो अचीवमैंट है, वह इसी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई है और यह बहुत बड़ी चीज है। अगर ऐसा ही सहयोग मिलता रहा तो भविष्य में यहां पर लीवर ट्रांसप्लांट, पेंक्रियाज ट्रांसप्लांट इत्यादि के बारे में सोचा जा सकता है। उसके लिए यहां पर अलग-अलग टीम्ज़ सर्वे कर रही हैं तथा उसके बारे में काम हो रहा है। रोबोटिक सर्जरी की मशीन 28 करोड़ रुपये में आती है जोकि यूरोलॉजी, गाइनोकोलॉजी तथा जनरल सर्जरी में काम आती है। आज सुबह इसके बारे में प्रश्न भी लगा था जिसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने बताया है कि 40 सर्जरी की जा चुकी हैं जोकि बहुत बड़ी अचीवमैंट है।

अध्यक्ष महोदय, इतने सारे डॉक्टर्ज आ गए तो अब हमें क्या चाहिए? माननीय मुख्य मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने डॉक्टर्ज की जॉब क्रिएट कर दी है। परंतु अब यह भी देखना पड़ेगा कि घर तो बना रहे हैं लेकिन उसको चलाना कैसे है? यह एक गंभीर समस्या है इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाना बहुत जरूरी है। आपके एस0आर0 डॉक्टर्ज आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्ज के लिए जो मशीनों की व्यवस्था करनी है, वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमें उन मशीन्ज की जल्दी-से-जल्दी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि आपके सुपर

**01.12.2025/1550/av/yk/2**

स्पेशेलिटी के डॉक्टर्ज वहां आकर बैठ जाएंगे। उनको वहां चलाने के लिए ओ0टी0 चाहिए। वर्तमान में टांडा मेडिकल कॉलेज में 22 ओ0टीज0 हैं जिनमें से अभी तक केवल 12 ओ0टीज0 चल रही हैं बाकी ओ0टीज0 एनेस्थीसिया के डॉक्टर्ज की कमी के कारण नहीं चल पा रहे हैं। अगर ओ0टी0 नहीं चलेंगे तो आपके वहां ऑपरेशन भी कम होंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में एक दिन में लगभग 2500 ओ0पी0डी0 होती हैं। अब आप अन्दाजा लगाइए कि एक महीने में वहां लगभग 60-70 हजार ओ0पी0डी0 होती हैं और रविवार का दिन निकाल दिया जाए तो वहां पर एक वर्ष के अंदर करीब 6-7 लाख ओ0पी0डी0 होती हैं। हिमाचल की आबादी लगभग 70 लाख है और टांडा मेडिकल कॉलेज में ही एक वर्ष में लगभग 7 लाख ओ0पी0डी0 होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। It is a big health institution which caters such a huge population. आप एक वर्ष में लगभग 7 लाख लोगों को डील कर रहे हैं और यह आंकड़ा कोई बनावटी नहीं है। उन सारे मरीजों के नाम, पते व संबंधित कागजात टांडा मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के पास है।

अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लाने से पहले मैंने इस विषय के बारे में सारे-का-सारा लेखा-जोखा एकत्रित किया है क्योंकि इसको आपके माध्यम से सदन के समक्ष लाना बहुत जरूरी था। मैंने जैसे बताया कि वहां पर वर्तमान में 22 ओ0टीज0 में से 12 ओ0टीज0 चल रही हैं। वहां गैस्ट्रो सर्जन, पीडियाट्रिक्स या मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी इत्यादि होती हैं। But they will not get O.T. because we can't run

the O.T. क्योंकि उसको चलाने के लिए आपको स्पेसिफिकली एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है। आप जब तक उसको लेकर नहीं आएंगे तब तक वहां पर दूसरे डॉक्टर्ज को तैनात करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। शिमला के अंदर

**टी सी द्वारा जारी**

**01.12.2025/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1**

**श्री आर0एस0 बाली ... जारी**

करीबन कुल 25 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और 24 एस0आर0 हैं यानी शिमला के आई0जी0एम0सी0 हॉस्पिटल में 49 फैकल्टी है और टांडा में जो कि उतनी ही ओ0पी0डी0 करता है उतनी ही सेवा देता है जितनी आई0जी0एम0सी0, शिमला देता है, यहां मात्र 11 फैकल्टी हैं। आई0जी0एम0सी0,शिमला के पास 49 फैकल्टी हैं जबकि हमारे पास हमारे पास केवल 21 हैं । यह बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसे पूरा करने के लिए सरकार को अवश्य काम करना पड़ेगा । आज नर्सिंग कॉलेज टांडा में चालू हुआ है और इससे पहले केवल आई0जी0एम0सी0 में नर्सिंग कॉलेज था । मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आज नर्सिंग कॉलेज का पहला बैच टांडा में बैठ गया है तथा बी0एस0सी0 नर्सिंग के 60 स्टूडेंट का बैच टांडा से निकलेगा। इससे पहले यहां केवल जी0एन0एम0 तक की पढ़ाई होती थी । आज पूरा कॉलेज बन गया है और उसका पहला बैच शुरू हो गया है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । पैरामेडिकल के बी0एस0सी0 के स्टूडेंट चाहे लेबोरेटरी टेक्निशियन हों चाहे ओ0टी0ए0 हों चाहे बी0एस0सी0 रेडियोलॉजी हो, पहले वे 54 होते थे, अब यह संख्या बढ़कर 150 हो गई है। नर्सिंग छात्राओं और पैरामेडिकल की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है लेकिन इनके लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं हैं और इनके रहने का भी प्रबंध नहीं है । जब तक इनके रहने का प्रावधान नहीं होगा तब तक स्टूडेंट तो यहां आएंगे लेकिन वे सुविधाओं के अभाव में परेशान होंगे। सरकार ने यह बहुत बड़ा काम बड़े कम समय में किया है, ऐसा ऐतिहासिक काम जो वर्ष 2010 से पहले से लंबित था और अब जाकर पूरा हुआ है लेकिन इसके लिए लंबी सोच रखना जरूरी है। हॉस्टल के लिए लैंड की पहचान करना, बिल्डिंग्स बनाना बहुत आवश्यक है। टांडा में रोज हजारों गाड़ियां आती हैं और पार्किंग की बहुत बड़ी

समस्या है। यहां जिला कांगड़ा, पूरे पार्लियामैंट और बाहर की पार्लियामैंट तक से लोग आते हैं लेकिन पार्किंग की उपलब्धता नहीं है इसलिए इस विषय पर गहन चर्चा और निर्णय लेने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि इसके लिए लैंड, बिल्डिंग, हॉस्टल और नये डॉक्टर्स की व्यवस्था जरूरी है । अब यहां नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। इसके लिए हमने आग्रह किया और सरकार ने प्रयास किए। इसके लिए मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार

**01.12.2025/1555/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2**

कल्याण मंत्री ने अपना पूरा सहयोग दिया। ओ0टी0 चालू करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए नहीं तो यह सारी मेहनत अधूरी रह जाएगी । इसके ऊपर कार्य करना आवश्यक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए स्पेशल प्रावधान करना चाहिए । इस हस्पताल पर अनेकों सरकारों और विशेष कर कांग्रेस सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये का खर्च किए गए लेकिन इसकी मेंटेनेंस की स्थिति ठीक नहीं है और उसे सुधारना आवश्यक है । मेरा आग्रह है कि इसके लिए सरकार स्पेशल बजट का प्रावधान अवश्य करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद

**मुख्य मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है, भाग्य से मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और मुख्य मंत्री भी हूं । जब हमने प्रथम वर्ष में हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की मीटिंग ली तो पाया कि सभी मेडिकल कॉलेज 40 से 50 प्रतिशत ऑक्यूपैंसी के साथ चल रहे हैं यानी 50 प्रतिशत न डॉक्टर हैं न पैरामेडिकल स्टाफ । सरकार के लिए इन मेडिकल कॉलेजों चाहे आई0जी0एम0सी0 हों चाहे टांडा हों को इस स्थिति से बाहर निकलना आवश्यक था। मेरा इन दोनों प्रीमियम मेडिकल कॉलेज आई0जी0एम0सी0 और टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ इंटरेक्शन हुआ।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

01-12-2025/1600/NS-AG/1

मुख्य मंत्री -----जारी

उसमें मेरे साथ माननीय आर0एस0 बाली जी और कांगड़ा के सभी विधायक भी उपस्थित थे। इंटरेक्शन के बाद वास्तविक स्थिति का पता लगता है। मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया और शिमला के पीटरहॉफ में इंटरेक्शन किया और रात्रि भोजन भी वहीं किया। वास्तविक स्थिति का पता लगने के बाद यह पाया गया कि हिमाचल की जो जनता मेडिकल कॉलेज, आई0जी0एम0सी0 या टांडा में इलाज करवाने आती है तो कहीं हम उनको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। यह सही है कि जब बुखार या थोड़ी बीमारी होती है एंटीबायोटिक दे देते हैं तो वह इससे ठीक हो जाती है। कई बीमारियां इतना भयंकर रूप धारण कर लेती हैं जो अंत तक भी ठीक नहीं होती हैं और व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इन चीज़ों को कैसे ढूंढा जाए और इन चीजों का कैसे पता लगाया जाए? इस दृष्टिकोण से हमने बैठकों का दौर शुरू किया। मुझे आज खुशी है कि जिला कांगड़ा का प्रीमियम इंस्टीच्यूट मेडिकल कॉलेज, टांडा है। लेकिन यहां के लोग इलाज करवाने के लिए प्रदेश से बाहर जाते हैं। वे लोग लुधियाना, होशियारपुर और पठानकोट जाते हैं। ऐसे क्या कारण हैं कि वे लोग इलाज करवाने बाहर जा रहे हैं? तब पता लगा कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं तो हमारा सिर्फ यह काम रह गया है कि डॉक्टर्ज की ट्रांसफर करवाई, प्राईमरी हैल्थ सेंटर से डॉक्टर आई0जी0एम0सी0 या टांडा में आ गया और सी0एच0सी0 से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज, टांडा में आ गया तथा जब काम का लोड पड़ा तो वहां से ट्रांसफर हो गया। पहले मूलभूत कारण क्या था हमने इसको जानने की कोशिश की। हमने मूलभूत कारण का पता लगाया और हमने ऐसा फैसला किया जिसमें डॉक्टर्ज ने कुछ स्ट्राइक भी की। हमने फैसला लिया कि पहले मेडिकल कॉलेज का काडर अलग किया जाएगा और डायरक्टरेट ऑफ हैल्थ सर्विसिज का काडर अलग किया जाएगा। हमने डायरक्टरेट ऑफ हैल्थ सर्विसिज का काडर अलग किया और डायरक्टरेट ऑफ मेडिकल कॉलेज का काडर अलग करने की दिशा में हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। फिर हमें पता चला कि मरीज सबसे पहले केजुअलिटी में जाता है। अगर मरीज मेडिकल कॉलेज, टांडा की केजुअलिटी में जाता है तो वहां क्या हालत है? हम इस पर अभी स्टडी कर ही रहे हैं। हमने पाया कि वहां मरीज को

01-12-2025/1600/NS-AG/2

चैक करने वाले डॉक्टर्ज पी0जी0 करने वाले डॉक्टर्ज हैं। वहां पर शाम को कोई कंसलटेंट आता ही नहीं है। वहां पर कोई असिस्टैंट प्रोफैसर नहीं होता है। अब इस स्थिति से कैसे निपटा जाए? पिछली कैबिनेट में हमने Department of Causality को अपग्रेड करके Department of Emergency Medicine बनाया और एम्स की तर्ज पर हमने कहा कि अब यहां हम स्पैशलिस्ट डॉक्टर्ज रखेंगे जिनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को कैबिनेट ने परमिशन दे दी है तथा जल्दी ही Department of Emergency Medicine का अलग से काडर बनेगा जहां असिस्टैंट प्रोफैसर से लेकर डॉक्टर्ज होंगे। यह मेन्डेटरी होगा कि 50 प्रतिशत रात को वहां पर कंसलटेंट रहेंगे ताकि मरीज का सही इलाज हो सके।

अध्यक्ष महोदय, फिर टेक्नोलॉजी की बात आई। किसी ने कभी टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने किसी मरीज की सिफारिश किसी डॉक्टर से कर दी और उसका इलाज हो गया। लेकिन डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से टेक्नोलॉजी का अध्ययन करता है कि मरीज को क्या हुआ है? इसका पता बाद में पी0जी0आई0, चंडीगढ़ में ही जा कर चलता है। इसके लिए मैं अपना ही उदाहरण देना चाहता हूं। मैं विधायक था और मुझे भी अपनी बीमारी का पता नहीं चला क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आई तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज, टांडा में 20 वर्ष पुरानी एक्स-रे मशीन है। एम0आर0आई0 1.5 टेस्ला अभी दो वर्ष पहले ही आई है। अब जब डायग्नोज ही नहीं होगा कि मुझे बीमारी क्या है तो मरीज क्या इलाज करवाएगा? हम आधुनिकता की दुनिया में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी व डिजिटाइजेशन की दुनिया में रह रहे हैं। फिर हमने सोचा और कहा कि इसके लिए धन की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मैंने हैल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखा। सरकार की दूसरी प्रायोरिटी पर हैल्थ सेक्टर है। इसके लिए हमने कई जगहों पर कट लगा कर हैल्थ सेक्टर को अपने राजस्व से और अपने राज्य के धन से टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने की सोची। हम टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। फिर पता यह लगा कि जो पैरा मेडिकल स्टाफ, रेडियोग्राफर, लैबोरेटरी तकनीशियन, एनेस्थीसिया वाले

अस्पतालों में नहीं टिकते हैं क्योंकि उनको आउटसोर्स पर 12,000 से 15,000 रुपये वेतन मिलता है। कितने लोग निकलते

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.12.2025/1605/RKS/AG-1

मुख्य मंत्री... जारी

क्योंकि उन्हें आउटसोर्स में 12-15 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। जो छात्र MBBS में चयनित नहीं होते वे एनेस्थीसिया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन या रेडियोग्राफ़र का कोर्स करते हैं। हमने उनका वेतन बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। टांडा और IGMC, शिमला में वर्ष 2003 से इनकी सीटें 15 या 18 थीं जिन्हें बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया है ताकि कमी को पूरा किया जा सके। हमने मांग और आपूर्ति की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सीटों को बढ़ाया है। टांडा में GNM और ANM कोर्स चल रहे थे। मैंने ANM कोर्स बंद करवाया और GNM की जगह B.Sc. नर्सिंग कोर्स शुरू करवाया। इस वर्ष टांडा में 60 सीटों तथा IGMC, शिमला में 100 सीटों में B.Sc. नर्सिंग की कक्षाएं शुरू हुई हैं। मैं टेक्नोलोजी के बारे में भी सदन को अवगत करवाना चाहता हूं। टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग ही नहीं था। हमारी सरकार ने 15 वर्षों बाद टांडा में SRship की 27 पदों को स्वीकृति दी। आज Emergency Medicine Super Specialty में Assistant Professor की पोस्ट क्रिएट की गई है। यह पद टांडा मेडिकल कॉलेज में पहली बार सृजित हुआ है। जब सभी पद सृजित हो जाएंगे तभी यह मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चलेगा। इसके लिए हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अध्यक्ष महोदय, ऑन्कोलॉजी विभाग में लिनियर एक्सेलेरेटर पहले खरीद लिया गया परंतु वहां डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। कैंसर उपचार की मशीन पहले ले ली गई। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देता, मैं दोष उस व्यवस्था को देता हूं जिसे हम परिवर्तित कर रहे हैं। हमें पहले यह जानकारी होनी चाहिए थी कि मशीन का उपयोग किस प्रकार के उपचार में किया जाएगा। कैंसर उपचार के लिए लिनियर एक्सेलेरेटर ले लिया गया लेकिन कैंसर की डायग्नोस्टिक मशीन उपलब्ध नहीं थी। इस वर्ष हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए PET Scan मशीन स्वीकृत की है और खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 20 वर्ष

---

पुरानी X-Ray मशीन लगी हुई है। हम रोगियों को फोन कर देते हैं कि वे अपना उपचार करवाने के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज जाएं लेकिन जब वहां पर्याप्त सुविधाएं नहीं होंगी तो वे क्यों जाएंगे? इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने लेटेस्ट डिजिटल X-Ray मशीन का ऑर्डर दे दिया है। आप कह रहे हैं कि वहां 10 या 22 ओ0टी0 में ऑपरेशन चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एनेस्थीसिया के पद पहले सृजित ही नहीं हुए थे। अभी हमने 10 एनेस्थीसिया के पदों के सृजन का निर्णय लिया

01.12.2025/1605/RKS/AG-2

है और अगली कैबिनेट बैठक में इसकी स्वीकृति दी जाएगी। हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए 60 B.Sc. Nursing सीटें, 50 B.Sc. Lab Technician सीटें जो पहले केवल 12 थीं क्रिएट की हैं। 50 Radiographers जो पहले 15-18 थीं तथा 50 OTA की सीटें सृजित की गई हैं जिन्हें सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। हमने 12 Professors, 14 Assistant Professors तथा 458 Staff Nurses के पद सृजित किए हैं। OTA, Radiographers और Data Entry Operators के पद आउटसोर्स आधार पर अनुमोदित किए गए हैं और इनकी नियुक्तियां शीघ्र कर दी जाएंगी। हमें एक अन्य समस्या यह भी आ रही है कि इन आउटसोर्स पदों पर ठेकेदार ही स्टे करवा देते हैं। हम टांडा मेडिकल कॉलेज में Staff Nurses की नियुक्तियां करवाने जा रहे थे लेकिन आउटसोर्स ठेकेदारों ने उस पर स्टे ले लिया। OTA पदों पर भी स्टे करवाया गया है। इस विषय पर हम माननीय उच्च न्यायालय को अवगत करवाएंगे और इस बारे अनुरोध करेंगे। हम स्वास्थ्य क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां कर रहे हैं। हमने मेडिकल कॉलेजों के लिए 450 Assistant Staff Nurses की नियुक्तियां राज्य चयन आयोग के माध्यम से करने का निर्णय लिया है और इसकी रिक्विज़िशन आयोग को भेज दी है। हमने टांडा मेडिकल कॉलेज के साथ-साथ अपने सभी मेडिकल कॉलेजों को स्ट्रेंथन करना है।

श्री... बी0एस0द्वारा जारी

01.12.2025/1610/बी.एस./एम.-1

मुख्य मंत्री जारी...

लेकिन कोई भी बीमारी है उस बीमारी को न पकड़ा जाए तब तक वह ठीक नहीं हो सकती। मेडिकल कॉलेज में जो कारण है उन्हें आपने ढूंढा है और हमने उन कारणों को ठीक किया है। **मैं आज मंच के माध्यम से इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं और मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक साल के भीतर सभी पांचों मेडिकल कॉलेजिज चमियाना, आई0जी0एम0सी0, हमीरपुर, नेरचौक और टांडा को पहली स्टेज पर एक वर्ष के भीतर वर्ल्ड क्लास एक्सरे की फैसेलिटीज के साथ अपग्रेड कर दिया जाएगा।** आप महसूस करेंगे कि यहां हमें वर्ल्ड क्लास एम्स की फैसेलिटीज मिल रही हैं।

दूसरी स्टेज में जिला चंबा का मैडिकल कॉलेज जिसका कि आप बार-बार जिक्र करते रहते हैं और हमारे को भी आपने कई बार बताया कि चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए कुछ सोचो। चंबा के मेडिकल कॉलेज और नाहन के मेडिकल कॉलेज को स्ट्रेंथंन किया जा रहा है। वहां पोस्टें भरी जा रही है। उसके बाद जैसे ही वह मेडिकल कॉलेज स्ट्रेंथंन होगा हम उसमें और पोस्ट ग्रेजुएशन की पोस्टों स्वीकृत करवाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए हमने एक कमेटी बनाई है कि मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करना है, कैबिनेट ने उसके लिए सब कमेटी का गठन किया है अगली कैबिनेट में हम उसमें डिसीजन कर लेंगे और जहां नाहन के लोग चाहते हैं, नाहन के हमारे मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन चौहान जी और आदरणीय अजय सोलंकी जी तथा हमारे अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार जी और सब लोग जो चाहते हैं वहां उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इनकी सरकार की कार्यप्रणाली देखिए, पिछले 4 साल से इस मेडिकल कॉलेज को ऐसी जगह पर बना दिया गया है जहां आर्बिट्रेशन में क्या कर दिया गया है और आर्बिट्रेशन वाला काम 250 करोड़ रुपये का किया है और 350 करोड़ रुपया एक्सट्रा मांग रहा है। मैंने कहा कि ऐसे प्रदेश की संपदा को हम लूटने नहीं देंगे। उस मामले में हमने हाईकोर्ट में अपील की है।

01.12.2025/1610/बी.एस./एम.-2

मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, कि जायका की बात जो यहां कहते हैं, जायका से अभी तक कोई पैसा हमें स्वीकृत नहीं हुआ और कम-से-कम जायका का पैसा स्वीकृत करने के लिए 6-7 साल लगते हैं अभी तो हमारी जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट की लिमिट वही खत्म हो चुकी है। 16वां फाइनेंस कमीशन जब रिकमेंड करेगा उसके बाद हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही नहीं 69 अदर स्वास्थ्य संस्थानों को भी, मैं टांडा के अलावा बताना चाहता हूं सब जगह कम-से-कम 70 प्रतिशत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब वहां सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्दी ही देने जा रहे हैं। मैं माननीय बाली जी को यह भी बताना चाहता हूं के इंडिया की पहली स्मार्ट लैब एम्स में लगी है। मैंने उसके लिए 75 करोड़ रुपया चमियाना, आई0जी0एम0सी0 और टांडा के लिए स्वीकृत करवा दिया। उसका टेंडर भी जल्दी होने वाला है। यह ऐसी डायग्नोस्टिक लैब है जिसमें जब पेशेंट का ब्लड लेकर आपको सभी प्रकार की जो भी बीमारी होगी उसका पता लग जाएगा बार-बार ब्लड नहीं देना पड़ेगा। इसमें एक ही बार में पता लग जाएगा और आपको डायग्नोस्टिक सिस्टम को हम बहुत ज्यादा अपग्रेड करना चाह रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा भी स्मार्ट लैब के द्वारा भी और लेटेस्ट मशीनें लाकर और स्टाफ की नियुक्ति कर हम टांडा को मजबूत करवाएंगे। मैं माननीय सदस्य, रघुवीर सिंह बाली जी को और सभी साथी सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम जो भी स्टाफ की कमी है को पूरा करेंगे और वर्ल्ड क्लास फैसेलिटीज हम इन मेडिकल कॉलेज में देने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें सफलता अभी 50 प्रतिशत मिली है क्योंकि स्टाफ का राशनलाइजेशन करना है, स्टाफ में कई बार विरोध होता है। पैरामेडिकल स्टाफ में विरोध होता है **लेकिन हमने कहा विरोध के बावजूद भी हम डॉक्टर के सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं कुछ एक और समय में हम कड़े फैसले हेल्थ सेक्टर में लेंगे जिससे आम लोगों को इस सुविधा का फायदा हो। मैं यह आश्वसन माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।**

01.12.2025/1610/बी.एस./एम.-3

रिपेयर और मेंटेनेंस के साथ-साथ हम रोगी मित्र भी ला रहे हैं। 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग कहां जाएगा? हम इन्हें टांडा के लिए भी ला रहे हैं, बुजुर्ग को किस डॉक्टर के पास जाना है, वह एस0ओ0पी0 बन रहा है, 1000 पोस्टें मेडिकल कॉलेज के रोगी मित्र की भी सैंक्शन की है। बेचारा जो बुजुर्ग है उसको पानी पिलाने का और 01.12.2025/1610/बी.एस./एम.-3

उसको डॉक्टर तक ले जाने का और जहां ब्लड टेस्ट होने हैं या डायग्नोस्टिक होना है सब चीजों की सुविधा उस रोगी मित्र के द्वारा दी जाएगी ताकि उसको धक्का न लगे।

रिपेयर और मेंटेनेंस की लिफ्ट के लिए भी हमने 5 करोड़ रुपया आपके यहां दे दिया है और मैंने आपके चीफ इंजीनियर को भी बोला है कि इसको पूरी तरह चमकाया जाए। टांडा के हमारे मेडिकल कॉलेज में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। यह प्रिंसिपल का भी दायित्व बनता है, मैं प्रिंसिपलों से भी कहना चाहूंगा आपको नहीं दिखता है कि वहां पर घास उग रहा है कई जगह कुछ उग रहा है। एक बार तो आपको भी यह देखना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब यह नहीं कि वह एकेडेमिकल और वहां एडिशन डायरेक्टर का मतलब यह नहीं कि वह वहां बैठा रहे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**01.12.2025.1615.डी0टी0-ए0एस0.-1**

**मुख्य मंत्री जारी...**

मै डायरैक्शन्ज दूंगा मैं कही जगह देखता हूं की पी0एच0सी0 में घार उग रहा है सी0एच0सी0 में घास उग रहा है, उस कोई गौर ही नही करता। अपनी जिम्मेवारी को भी समझने की जरूरत होती है। माननीय सदस्य श्री रघुवीर सिंह बाली जी द्वारा नियम-62 के

अंतर्गत जो मामला इस माननीय सदन में उठाया गया है, मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूं कि एक साल के अंदर हम सभी मेंडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष** : अब माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

**डॉ0 जनक राज** : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948, जो अभी कोड ऑफ वेजिज -2019 में परिवर्तित हो चुका है, की व्यवस्था लागू करने के बारे में इस सदन का ध्यान आकृषित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-62 के अंतर्गत उपरोक्त विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने का मौका दिया, इसलिए संस्कृति और संस्कार के हिसाब से आपका अभिवादन करना मेरा दायित्व है। साथ-ही-साथ आपने इस शीतकालीन सत्र की शुरूवात भी संविधान दिवस के दिन की इसलिए मैं बहुत दुविधा में हूं कि आपका धन्यवाद करूं तो किस प्रकार करूं? क्योकि संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में Fundamental Right to Choice और मेरी आत्मा के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है और मैं आत्मा की आवाज को सुनते हुए मैं आपको राधे-राधे और जय श्री राम बोलता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, Constitution provides a framework for the Government to function within the limit to protect the citizens right and ensure accountability. Government's power is not absolute. It is restricted and regulated by the Constitution of India. भारत का संविधान हमें Right of dignified life का अधिकार देता है और इस संविधान में यह भी निहित है कि एक श्रमिक या एक कर्मी की इतनी कमाई जरूर होनी चाहिए जिस कमाई से वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, उनके लिए कपड़े का इंतजाम कर सके, जरूरत पड़ने पर दवाई, बच्चों के शिक्षा का प्रबंध कर सके। परंतु वर्तमान परिस्थिति में जब

**01.12.2025.1615.डी0टी0-ए0एस0.-2**

इस न्यूनतम वेजिज को देखा जाता है तो इस विषय पर माननीय उच्चतम न्यायालय की कई बार ये टिप्पणियां आई हैं कि न्यूनतम वेतन जब किसी को नहीं दिया जाता तो यह लगभग एक बंधुवा मजदुरी के समान है और उसके संविधानिक अधिकारों का हनन है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स् पर काम करने वाले लोग हैं, पार्ट टाइम वकर्ज हैं, नर्सरी के मजदूर और अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं जिनको बहुत कम वेतन मिल रहा है और वह वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा। इस बात पर मुझे गीता की एक बात याद आती है "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" कि डयूटी करना आपका काम है परन्तु वेतन मांगना आपका अधिकार नही है यानी बस कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत करो। अध्यक्ष महोदय,वर्तमान सरकार ने व्यवस्था परिर्वतन के मार्ग पर चलते हुए रोजगार का माध्यम चुना जिसके तहत वन मित्र, पशु मित्र, रोगी मित्र, मल्टी-टास्क मित्र और अनेको प्रकार के मित्र भर्ती किये ...(व्यवधान) मित्र ही मित्र भर्ती किए, परंतु आप उनसे मित्रता निभाने में कहीं-न-कहीं चूक गये हैं ...(व्यवधान) महिला सशक्तिकरण के लिए आपको सखियां भी रखनी पड़ेंगी मात्र मित्रों से ही काम नहीं चलेगा। 9 अक्तुबर,1925 को हिमाचल सरकार ने एक Revision of Rate of Wages of dailywage workers and workers engaged on part time basis in Himachal Pradesh इस संबंध में एक नोटिफिकेशन निकाली। बहुत दुःख की बात है कि इस नोटिफिकेशन में भी इन मित्रों का कहीं कोई ध्यान नहीं रखा गया। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि ये मित्र कौन सी श्रेणी के कर्मचारी हैं- skilled, semi-skilled, non-skilled or highly skilled?

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1620/डी.सी.-एन.जी./1**

**डॉ0 जनक राज........जारी**

या हाइली स्कीोल्ड और क्यों इन मित्रों को संविधानिक सम्मान-गरिमा के अधिकार व सुख से वंचित रखा जा रहा है? क्यों इन्हें ई0पी0एफ0, लीव्ज़ और मेडिकल लीव्ज़ जैसी

सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? व्यवस्था परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए इस सरकार ने सच में व्यवस्था परिवर्तन किया है क्योंकि पहले लोग सरकार में आने के लिए रोते थे लेकिन अब सरकार में आकर रो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार का एक नारा है और प्रदेश सरकार के लोग बड़ी जोर-शोर से कहते हैं तथा मैं भी उसका बड़ा आदर व सम्मान करता हूं कि "हम सत्ता में सत्तासुख के लिए नहीं आए हैं"। यह बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप सत्ता में सत्तासुख के लिए नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को दुःख देने के लिए आए हैं। मुझे इतनी ही बात कहनी थी और मैं चाहूंगा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में न्यूनतम मजदूरी और वेतन मजदूर संहिता-2019 जोकि केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसमें पार्ट टाइम वर्कर, आऊटसोर्स वर्कर आदि को कम-से-कम सम्मानजनक वेतन देने का प्रावधान है, मेरा आग्रह है कि उसके प्रावधानों को हिमाचल प्रदेश सरकार भी लागू करने का प्रावधान करे। धन्यवाद।

**अध्यक्ष** : अब माननीय उद्योग मंत्री इसका उत्तर देंगे।

**01.12.2025/1620/डी.सी.-एन.जी./2**

**उद्योग मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, डॉ0 जनक राज ने नियम-62 के तहत न्यूनतम वेतन अधिनियम विषय पर अपनी बात इस माननीय सदन में रखी है। मैं बताना चाहता हूं कि श्रम विभाग के अंतर्गत निजी क्षेत्र की लेबर को लिया जाता है। माननीय सदस्य ने सरकारी क्षेत्र के जिन कर्मचारियों का जिक्र किया है, जिसमें पार्ट टाइम वर्कर व मल्टी टास्क वर्कर आदि शामिल हैं, वे सभी Department of Personnel के अंतर्गत आते हैं। माननीय सदस्य का विषय ट्रांसफर होकर मेरे पास आया है।मैं कहना चाहता हूं कि मल्टी टास्क वर्कर आदि रेगुलर कर्मचारी नहीं बल्कि पार्ट टाइम कर्मचारी होते हैं। इनके वर्किंग ऑवर्ज़ डिफाइन भी नहीं हैं। Their working hours are not fixed for 8 hours per

day. इनके जितने वर्किंग ऑवर्ज़ बनते हैं, उसी के अनुसार इन्हें सैलरी दी जाती है। मिनिमम वेज एक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 425/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित किए हैं। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को 425/- रुपये प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में भी स्कील्ड वर्कर के लिए 425/- रुपये प्रतिदिन देने का नियम लागू होता है। हमारे सरकारी क्षेत्र में 19 विभाग/क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें यह नियम लागू होता है। उसमें कृषि, सड़क एवं भवन निर्माण, पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट, दुकान एवं वाणिज्य, वन, उद्योग आदि जैसे कुल 19 क्षेत्र/विभाग ऐसे हैं जिनमें मिनिमम वेज़िस एक्ट लागू होता है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इसमें 75/- रुपये की बढ़ौतरी की है। वर्ष 2023 में 350/- रुपये से बढ़ाकर 375/- रुपये, वर्ष 2024 में 375/- रुपये से बढ़ाकर 400/- रुपये और वर्ष 2025 में 400/- रुपये से बढ़ाकर 425/- रुपये किए गए हैं। माननीय सदस्य ने जिन-जिन कैटेगरीज़ का जिक्र किया है, उनका ध्यान रखा जाएगा। **मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार भी ईज़ ऑफ डुइंग बिजनस की तरफ बढ़ रही है और इससे संबंधित कानूनों में संशोधन करके उन्हें सरल बनाया जा रहा है। मजदूरों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने अनेक संशोधन किए हैं और सभी प्रदेशों को कहा है कि हम भी अपने-अपने प्रदेशों में इन कानूनों में संशोधन करें। हम हिमाचल प्रदेश में भी इस पर विचार कर रहे हैं और कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं।** माननीय सदस्य ने आऊटसोर्स कर्मचारियों के संदर्भ में कहा है तो मैं

**01.12.2025/1620/डी.सी.-एन.जी./3**

इन्हें बताना चाहता हूं कि वे आऊटसोर्स कम्पनियों के कर्मचारी हैं। पूर्व में यानी के वर्ष 2010 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब यह आऊटसोर्स प्रथा शुरू की गई थी। भारत सरकार ने भी आऊटसोर्स की नीति को लागू किया है और उसके बाद अन्य प्रदेशों में भी इसे लागू किया गया। यह ठीक है कि लेबर कानूनों के अनुसार आऊटसोर्स कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारी को

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

**01.12.2025/1625/डी0सी0-पी0बी0/1**

**उद्योग मंत्री ...जारी**

ई0पी0एफ0 या अन्य चीज़ें है जो लेबर लॉज के मुताबिक एक कर्मचारी को मिलनी चाहिए, वह नहीं दी जाती है। आउटसोर्स कंपनीज़ ई0पी0एफ0 काटती है लेकिन जब वह डेलीवेज कर्मचारी नौकरी छोड़कर जाता है तो उसे ई0पी0एफ0 नहीं मिलता है। आउटसोर्स कंपनीज़ इस प्रकार की बहुत-सी अनियमितताएं और कई उल्लघंन करती हैं जिसे माननीय सदस्य ने हमारे ध्यान में लाया है। माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी यदि आपके ध्यान में ऐसी कोई स्पेसिफिक कंपनी है तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार और लेबर डिपार्टमैंट मिनिमम वेजिस एक्ट को लागू करेंगी और वर्क प्लेस कंडीशंज तथा मेडिकल फेसिलिटीज़ को सुनिश्चि करेगी ताकि हमारे डेलीवेज कर्मचारियों को इन सब सुविधाओं का लाभ मिल सके।

**अध्यक्ष :** अब विधायी कार्य होगा।

**सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना**

**अध्यक्ष :** अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

**प्रस्ताव स्वीकार**

**अनुमति दी गई।**

**01.12.2025/1625/डी0सी0-पी0बी0/2**

**अध्यक्ष** : अब मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करेंगे।

**मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) को पुरः स्थापित करता हूं।

**अध्यक्ष** : हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 20) पुरः स्थापित हुआ।

**अध्यक्ष** : अब माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**अध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए?

**प्रस्ताव स्वीकार**

**अनुमति दी गई।**

**01.12.2025/1625/डी0सी0-पी0बी0/3**

**अध्यक्ष** : अब नगर एवं ग्राम योजना मंत्री भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करेंगे।

**नगर एवं ग्राम योजना मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) को पुरः स्थापित करता हूं।

**अध्यक्ष** : भू-संपदा (विनयमन और विकास) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 22) पुरः स्थापित हुआ।

अब नियम-130 के अंतर्गत जो विषय प्रस्तावित हैं उन पर आगे चर्चा होगी। माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा दिनांक 27.11.2025 को नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों" पर यह सदन विचार करे, पर आगे चर्चा होगी।

मेरे पास कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस विषय पर बोलने के लिए सदस्यों की लिस्ट नहीं आई है परंतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिस्ट आ चुकी है। मैं माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी से आग्रह करूंगा कि वह इस चर्चा में भाग लें। Kindly provide the list of participants from Congress side also.

**श्री विपिन सिंह परमार** : अध्यक्ष महोदय, मैं "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों" पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

**श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1630/H.K./A.P./ 01**

**नियम 130 के तहत चर्चा जारी .....**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी .....**

अध्यक्ष महोदय, यदि हम वर्ष 2022, 2023, 2024 और 2025 की बात करें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि विशेषकर इन तीन वर्षों 2023, 2024 और 2025 में हिमाचल प्रदेश की स्थिति का आंकलन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश जिसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, अब आपदा-ग्रस्त भूमि बनता जा रहा है। वर्ष 2025 में लगभग 65 से 70 दिनों तक लगातार भारी वर्षा हुई। इसके परिणामस्वरूप हजारों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, कई मकान पूरी तरह ढह गए और पशुधन का भी काफी नुकसान हुआ। इस आपदा में हिमाचल प्रदेश के अनेक लोगों की जानें चली गईं और कुछ लोग आज भी लापता हैं। पिछले तीन वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएं घट रही हैं, कहीं बादल फटने की घटनाएं तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है।

**(श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासिन हुए।)**

**श्री विपिन सिंह परमार** : हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण भी जनजीवन प्रभावित हुआ। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, वहीं दूसरी ओर मानव की प्रवृत्ति और दृष्टिकोण भी इसका कारण माना जा सकता है। जब हम आकलन करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम पहाड़ों को काट रहे हैं, नदियों और नालों का रुख मोड़ रहे हैं। विकास के नाम पर जिस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, मैं मानता हूं कि विकास होना चाहिए परंतु जिस प्रकार हम उस विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उसका परिणाम यह है कि हम अपने आप को विनाश की ओर भी धकेल रहे हैं। जिस तरह से विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रयास हो रहे हैं, उसमें ऐसी स्थिति भी सामने आई है कि सड़कों से निकली हुई मिट्टी, जिसे गाद कहा जाता है। उसे डंपिंग साइट पर फेंककर नदियों और नालों में ढेर लगाया जा रहा है, जिससे बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। मैंने अपने जिले में भी यह स्थिति देखी है। उदाहरण के लिए, मंडी का पंडोह डैम, उसका बैड लेवल ऊपर आ गया है। परिणामस्वरूप लगभग 50,000 क्यूसेक मीटर पानी छोड़ा गया जो सीधे पौंग डैम की ओर चला गया। उन दिनों में तीन बार 70 हजार से 75 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जिससे वह पानी पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब, जो कभी जलमग्न नहीं होता था, उसी पंजाब के बड़े-बड़े शहर पानी की चपेट में

**01.12.2025/1630/H.K./A.P./ 02**

आ गए। सभापति महोदय, इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां इस सबके लिए प्रकृति जिम्मेदार है, वहीं व्यक्ति की प्रवृत्ति भी उस विनाश के लिए जिम्मेदार है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। देश के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हाल ही में जी-20 के अधिवेशन में पूरी दुनिया, भारत और हिमाचल प्रदेश को यह अवसर मिला कि हम "वन नेशन,

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**01.12.2025/1635/AT/HK/01**

**श्री विपिन सिंह परमार जारी...**

वन अर्थ, वन फ्यूचर' जहां पूरी दुनिया आज आतंकवाद से चिंतित है, वहीं पर्यावरण में जो इकोलॉजी इंबैलेंस हो रही है, उसके लिए भी पूरे देश चिंतित हैं कि यह जो जलवायु परिवर्तन है इसे मिलकर कैसे हल किया जा सकता है। इसी को लेकर यह नारा दिया गया है कि जहां पूरी दुनिया में असमानता है। पूरी दुनिया आतंकवाद, अलकायदा जैसी घटनाओं से परेशान है, और साथ ही यह भी चिंता है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वे राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात भी मैं यहां कहना चाहता हूं। मुझे याद है कि इस वर्ष 30 जून 2025 को जब आपदा आई थी, तो सबसे पहले वह मंडी जिला में आई थी। अगले ही दिन रात को सोशल मीडिया पर खबरें आनी शुरू हो गई थीं। यानी जो लोग जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर ध्वस्त हो चुके थे, टूट चुके थे, खेत-खलियान, रोजमर्रा की दुकानें पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। ठीक है, सरकार ने राहत के प्रयास किए होंगे, परंतु जितने माकूल प्रयास होने चाहिए थे शायद उस हालत को ठीक करने के लिए और लोगों के जख्मों पर मलहम लगाने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थीं, शायद उतनी नहीं हो पाई। मैं कह सकता हूं कि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई। यह आपदा की घटना मंडी, कुल्लू, सिरमौर, कांगड़ा और अन्य जिलों में भी हुई। सरकार की ओर से इनिशिएटिव और प्रयास किए गए होंगे, परंतु आज भी उन इलाकों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसी आपदाएं पूरी दुनिया में आ रही हैं। जी-20 में भी अब यही चर्चा हो रही है कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इसे रोका कैसे जाए, पहल कैसे की जाय। चाहे भुज हो, सूरत हो, श्रीनगर हो, केदारनाथ हो या बद्रीनाथ ऐसी अनगिनत घटनाएँ घटती रही हैं। मुझे यह कहना है कि सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था, उतनी गंभीरता वहां नहीं दिखी, क्योंकि सरकार ने अपने पांव पसार दिए। वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2023 तक देश में कोरोना आया और कोरोना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरी

दुनिया में आया। इस करोना ने दुनिया के हर क्षेत्र और हर व्यक्ति को प्रभावित किया, चाहे विकसित देश हों या विकासशील। परंतु भारत सरकार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हेल्थ

**01.12.2025/1635/AT/HK /02**

डिपार्टमेंट के माध्यम से लोगों से निवेदन किया गया कि अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, लोगों का जीवन बचना चाहिए। एक नहीं, तीन-तीन वैक्सीनेशन लगे। अगर उस समय इस कोरोना आपदा को मन में बैठाकर हम शांत बैठे रहते, तो स्थिति और गंभीर होती। मैंने वह समय भी देखा है जब परिवार में ही लोग एक-दूसरे से मिलने से डरते थे... (व्यवधान)

**एम0डी0 द्वारा जारी ......**

**01-12-2025/1640/YK/MD/1**

**श्री विपिन सिंह परमार----जारी**

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा और समय दिया जाए। आपका विधान सभा क्षेत्र ज्वालामुखी भी प्रभावित है यह पनहार से ज्वालामुखी तक प्रभावित है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उस समय भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी थी, और छोड़नी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन इस समय का जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में हिमाचल प्रदेश सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था वह गंभीरता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहां जान-माल का नुकसान हुआ, घर क्षतिग्रस्त हुए, वहीं पर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की फ्लो इरिगेशन स्कीम का भी उल्लेख करना चाहता हूं। जिला कांगड़ा में यह स्कीम सबसे अधिक है चाहे न्यूगल खड्ड हो, बिनवा खड्ड हो, या मानूनी खड्ड के ऊपर हो मुझे सभी जगह जाने का मौका मिलता है। आज किसान दुखी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कूहल, कृपालचंद कूहल, जो 35 किलोमीटर क्षेत्र को जोड़ता है और वह न्यूगल बंदला से चलती थी, वह भी सूखी पड़ी है।

आज वह कूड़ा डालने की डस्टबिन बन गई है। किसानों की चिंता कौन करेगा? जो किसान खेत-खलीयान में फसल पैदा करता है राय-दी-कूहल जो कि पनापर, धीरा, नौरा से होते हुए बलौटा तक जाती थी वह पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी है। मिंया फतैह सिंह कूहल हो या दीवान चंद कूहल हो चाहे अन्य जितनी भी तमाम कूहले हैं। बिनवा नदी से निकलने वाली भी तमाम कूहले हैं वह सारी की सारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। पिछले 3 वर्षों से दुख इस बात का है, पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो हमने जो भी एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजे, वे नाबार्ड गए और वापस लौट आए। उस किटी में हमारा शेयर है परंतु वह वापिस आ गए वहां पर भी प्लानिंग डिपार्टमेंट से नाबार्ड के पास सूची जा रही है तो शायद इस तरफ के बैठे हुए सामान्य विधायकों की प्राथमिकताओं को सूची से हटाया जा रहा है। यानी सड़कों की बात को छोड़िए, परंतु कूहलों का निर्माण तक पूरा नहीं हो पा रहा और नाबार्ड से मिलने वाले हक से भी हमें वंचित किया जा रहा है। मुझे याद है कि हमनेठंबू-कंगैण स्कीम 60 करोड़ रुपये से बनाई थी। वह भी आज ठप पड़ी है। यानी जयसिंहपुर से पानी उठाकर, माननीय मंत्री के विधान सभा क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र की 12 स्कीमों को पुनर्जीवित करना था, लेकिन अत्यधिक ब्यास में खनन के कारण पांच पर्कुलेशन वॉल मिट्टी से भर गए हैं। इसका जिम्मेवार कौन है, पानी नहीं मिल रहा है यह

**01-12-2025/1640/YK/MD/2**

प्राकृतिक आपदा का परिणाम है। जब वहां से पाइपलाइन बिछाई गई तो खनन माफिया इतने सक्रिय हैं कि ठंबू कंगैण स्कीम की पाइपलाइन के नजदीक पहुंचकर 60 करोड़ से बनी हुई लागत को क्षति पहुंचाई तो प्राकृतिक आपदा में सरकार को जितना गंभीर होना चाहिए था वह गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही।

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

01.12.2025/1645/केएस/वाईके/1

**श्री विपिन सिंह परमार जारी** ---

और प्राकृतिक आपदा के सम्बन्ध में सरकार को जितना गम्भीर होना चाहिए था, वह गम्भीरता कहीं नहीं दिख रही है। विधायक निधि के बारे में तो मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आ गया और शायद अब तो यह बंद होने की कगार पर है। कुछ लोग तो हमें यह भी कहते हैं कि आप विधायक हैं, आपको 2.10 करोड़ रुपये मिलते हैं, आप कृपा करके हमारे गांव की टूटी हुई सड़क के लिए धन की व्यवस्था कर दीजिए। लोग कहते हैं कि आप चुने हुए हैं, हमने आपको अपना वोट और सहयोग दिया है, आप ही हमारी सरकार है। कई बार लोग कहते हैं कि आप हमारी सरकार है और आप ही धन की व्यवस्था करिए।

सभापति महोदय, आज जब हम गांव में कहीं लोगों के सुख-दुख में उनसे मिलने जाते हैं तो वे हमें अपने खेत-खलिहान और उन टूटी हुईं सड़कों को दिखाने ले जाते हैं परंतु हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि समाज की, लोगों की हमारे प्रति यह दृष्टि है कि जो हमारा विधायक जीत कर गया है वह विधान सभा में हमारी बात रखेगा परंतु हम मज़बूर हैं। हम दिल और मन से तो मज़बूत हैं। हम दृढ़ संकल्पी भी हैं परंतु सत्ता पक्ष ने हमें कमज़ोर बना दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्योंकि समाज यह कहता है कि आपने तो अपने बहुत ज्यादा मानदेय बढ़ा लिए हैं और आजकल तो यह कहा जा रहा है कि आपको 25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलेगा, लाभ मिलेगा, सोशल मीडिया ऐसी-ऐसी भ्रांतियां फैलाता है। सोशल मीडिया में भी जो इन्फ्लूएंसर्ज़ के रूप में काम करते हैं, वैसे तो उनकी भूमिका समाज में क्या ही है? प्रशांत किशोर ने बिहार में अपने आप को देख लिया है कि वह कहां पर खड़ा है। धरातल में काम करने वालों की ही जय-जयकार होती है। हवा-हवाई उड़ने वाले धरातल की परिस्थितियों को नहीं जान सकते। हम इस माननीय विधान सभा का हिस्सा हैं और एक विधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम 28 विधायक हिमाचल प्रदेश की

मज़बूत आवाज हैं। भारतीय जनता पार्टी के रूप में हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आशा और विश्वास के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं।

**सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

**01.12.2025/1645/केएस/वाईके/2**

**श्री विपिन सिंह परमार** : सभापति महोदय, मैं ये बातें आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि प्राकृतिक आपदा को ले करके यह सरकार गम्भीर होनी चाहिए लेकिन सरकार की गम्भीरता कहीं पर भी नहीं दिख रही है। गम्भीरता इनके व्यवहार में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर कहा गया कि राजस्व मंत्री जी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया लेकिन वह तो आपकी जिम्मेवारी है। आपको जाना चाहिए था। मणिमहेश की यात्रा चल रही थी। यहां पर हमारे एक विधायक महोदय ने कहा कि पहली बार हुआ कि वहां छड़ी नहीं पहुंची तो उसके लिए कहना चाहूंगा कि तीन सालों से ये घटनाएं घट रहीं थीं अतः हमें तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। जब यह आपदा आई तो सरकार ने प्रयास किए होंगे। मुझे भी चम्बा जाने का मौका मिला। हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉ0 राजीव बिंदल जी भी वहां गए। नेता प्रतिपक्ष तथा हमारे नैय्यर साहब भी वहां पर मिले। प्रदेश के महामहिम गवर्नर साहब का प्रवास भी हुआ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मण्डी गए। श्री जय राम ठाकुर जी के बारे में बहुत टिप्पणियां की गईं। आपदा के समय अपने मन की संतुष्टि के लिए इस मुंह से कभी इस प्रकार के शब्द नहीं निकलने चाहिए। जो संवैधानिक पदों पर हैं, मुझे लगता है कि वे समाज को जोड़ने की बात करें। समाज में कभी ऐसा विघटन न आए, यह मैं कहना चाहता हूं।

**सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप कीजिए।

**श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी** ---

**01.12.2025/1650/av/ag/1**

**श्री विपिन सिंह परमार**------- **जारी**

जो संवैधानिक पद पर हैं, वे समाज को जोड़ने की बात करें ताकि समाज में कभी कोई विघटन न आए। ...(घण्टी)... सभापति महोदय, मुझे दस मिनट्स का समय और दीजिए।

**सभापति** : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 20 मिनट्स का समय हो गया है और बोलने वालों की बहुत लम्बी लिस्ट है। ...(व्यवधान) और आप केवल सब्जैक्ट पर ही बोलिए। आप यहां पर व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए।

**श्री विपिन सिंह परमार** : सभापति महोदय, मैं जो बोल रहा हूं यह क्या सब्जैक्ट नहीं है? मैं यहां पर किसी विचारधारा के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर मैं किसी विचारधारा के ऊपर बोलूंगा तो अपना विषय पूरा नहीं रख पाऊंगा।

सभापित महोदय, मैं तो आपसे यह चाहता हूं कि यदि कभी मैं 'यू0सी0सी0' और इस देश को जोड़ने वाले 'राम जी' के ऊपर प्रस्ताव दूं, तो आप कृपा करके उसको स्वीकार कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के रिसोर्सिज को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

**सभापति** : अभी आप केवल इसी सब्जैक्ट पर बोलिए जिस पर चर्चा लाई गई है।

**श्री विपिन सिंह परमार** : सभापति महोदय, मैं तो आपके भविष्य हेतु शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपकी जो अदा, कद, व्यवहार और शालीनता है; आप सभापति नहीं बल्कि कुछ और बड़े बनें। मैं ईश्वर और माता ज्वालाजी के चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूं।

मैं यही कह रहा था कि अगर सरकार की ओर से मंत्री गए तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे नेता भी वहां पर गए। जब आपदा आई तो 'वसुधैव कुटुम्बकम'; क्योंकि हमारा शरीर केवल मन से नहीं बना है बल्कि यह मन, वचन और कर्म की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बना है। इसलिए जब ये लोग फैडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फैडरल स्ट्रक्चर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यहां आपदा आई तो हमारे साथ लगते प्रांतों ने बहुत सहायता

की और करनी भी चाहिए। जब हमारे किसी अंग में घाव या कष्ट हो जाता है तो यह हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। इसीलिए आपदा के दौरान

**01.12.2025/1650/av/ag/2**

हरियाणा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से राहत सामग्री भेजी गई। यहां पर बाढ़ प्रभावितों के लिए 5-5 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। असम से तो पूरी-की-पूरी ट्रेन आई और रेड क्रोस के माध्यम से चम्बा में दो स्थानों पर कार्यक्रम हुए। वहां पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से वे राशन सामग्री की किट्स वितरित की गईं। मुझे इस बात का भी गर्व है कि संगठन ही सेवा है। विकास तो होता है परंतु संकट में जब समाज साथ हो, तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 24813 राशन किट्स व नित्य उपयोग के सामान को वितरित किया। यहां पर लगभग 17582 कम्बल, 5900 तिरपाल, 9061 गद्दे, 9767 बर्तन किट्स, 1000 से अधिक स्टेशनरी किट्स व स्कूल बैग्ज, 9000 जोड़ी कपड़े, स्वेटर व ट्रैक सूट्स इत्यादि दिए गए तथा उस दौरान हिमाचल प्रदेश में लगभग 12000 कार्यकर्ताओं ने काम किया। ऐसा होता है और सभी काम करते हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपदा आई तो हम लोगों ने वहां पर काम किया और करना भी चाहिए। इस सदन में पहुंचने के लिए जिन्होंने हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तो वहां के लोगों के मर्म में जुड़ना भी बहुत जरूरी है। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय, आपके महादेव के साथ मेरे विधान सभा का जो बछवाई क्षेत्र लगता है, वहां पर भी प्राकृतिक आपदा आई और वहां पर पूरे-का-पूरा गांव बैठ गया। वहां पर 18 परिवारों के बहुत पुराने-पुराने व अच्छे घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहां जमीन और रास्ते दब गए परंतु सरकार की ओर से जो गरडनेर-बछवाई के लोगों को 7 लाख रुपये की सहायता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पाई है। इसके अतिरिक्त जो 3, 4 व 5 मरले जमीन देने की घोषणा की गई है, वह भी उनको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है।

**टी सी द्वारा जारी**

**01.12.2025/1655/टी0सी0वी0/ए0जी0/-1**
**श्री विपिन सिंह परमार ... जारी**

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा ने जिला कांगड़ा में प्रभु के आशीर्वादा से लोगों के जनजीवन को प्रभावित तो नहीं किया लेकिन 65 दिन तक चली इस आपदा में लोगों के मकान पूरी तरह गिर गए और कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कुछ एस्टीमेट्स तैयार करवाए हैं परंतु धीरा, पालमपुर और सुलाह तहसील में अभी तक लोगों को कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। मैं राजस्व मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आजकल कुछ अधिकारी सेल्फी बनाने और अपलोड करने में व्यस्त हैं। वे वहां जाकर वास्तविक परिस्थितियां देखने का कष्ट नहीं करते और न ही प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच कर लोगों के दुःख दर्द को समझते हैं। वे जरूरी नहीं समझते कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र में जाकर उन लोगों की रील बनाएं जो आपदा से प्रभावित हुए हैं। कुछ अधिकारी तो धर्मशाला से आते हैं और ढाड़ में गाड़ी खड़ी करते हैं। वे 12:00 बजे तक दफ्तर पहुंचते हैं और 03:00 बजे उनकी रवानगी शुरू हो जाती हैं। उन्हें सरकार का कोई भय नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों से रिपोर्ट अवश्य ली जाए और वे केवल कागजी कार्रवाई पूरी न करें बल्कि लोगों के दुःख-सुख में भी शामिल हों। आपदा से पूरे प्रदेश में लगभग 419 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। 479 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 47 से अधिक लोग लापता हैं। 28,922 पशुधन तथा पक्षी प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में 1,941 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और 6,515 गौशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। इस तरह से प्रदेशभर में लगभग 2,959 परिवार विस्थापित हुए हैं। कई जल आपूर्ति योजनाएं और नेशनल हाईवे भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। यह सारी स्थिति मैं यहां आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यहां माननीय सदन में कहा जा रहा है कि डिजास्टर एक्ट लागू है लेकिन पता नहीं यह कहां लागू है क्योंकि यदि यह एक्ट लागू होता तो यहां विधान सभा का सत्र क्यों हो रहा है? इसको भी वर्चुअली करवाया जा सकता था। नेचुरल डिजास्टर के नाम पर समाज में अनावश्यक सनसनी फैलाना और लोगों के

हितों की अवहेलना करना तथा ध्यान को भटकाने के लिए मुद्दों को मुद्दा बनाना यह सब उस तरफ (सत्तापक्ष) से हो रहा है।

**01.12.2025/1655/टी0सी0वी0/ए0जी0/-2**

सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बरसात के कारण क्यारवां कलूणा, परमार नगर, पनियाली, रझूं, टपेड़, लंझेड़, दरंग से धनेटा-झरेट आदि सड़कों की हालत बहुत खराब है क्योंकि इन सड़कों में केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। सभापति महोदय, आप भी सरकार में हैं और पनिनहार से ज्वालामुखी तक के रोड हमारे लिए लाइफलाइन हैं। आप इन कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र करवा सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन सड़कों को जल्द-से-जल्द ठीक करवाएं। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में जो डंगे, पुल, पुलिया, सड़कें और रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको ठीक करवाने के लिए हमारी विधायी क्षेत्र विकास निधि जारी करवाने की भी कृपा करें।

सभापति महोदय, हमने बड़े चाव से थुरल में एक हॉस्पिटल बनाया था जो बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया लेकिन उसके लिए राशि नहीं दी गई। हमने जनता की सुविधा के लिए भवारना में एक सिविल हॉस्पिटल बनाया था। हमें श्री जयराम ठाकुर जी ने परौर में पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया था लेकिन बरसात में उसमें पानी घुस गया। बरसार में जयराम ठाकुर जी की सरकार द्वारा दी गई आई0टी0आई0, रझूं भी क्षतिग्रस्त हो गई है।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

01-12-2025/1700/NS-AS/1

श्री विपिन सिंह परमार -----जारी

**सभापति** : माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करें। आपको बोलते हुए आधा घंटा हो गया है। आपने स्वयं कहा था कि 30 मिनट बोलेंगे और आपके 30 मिनट हो गए हैं।

**श्री विपिन सिंह परमार** : यह आपदा है और इस आपदा के कारण जो निर्माणाधीन भवन, सड़कें और पेयजल योजनाएं सारी की सारी प्रभावित हो गई हैं। हमारे आदरणीय बड़े ही वरिष्ठ मंत्री हैं।

**सभापति** : आपका प्वाइंट ऑफ व्यू आ गया है। प्लीज वाइंड अप करें।

**श्री विपिन सिंह परमार** : सभापति महोदय, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। हमें भारत सरकार ने जो 5500 करोड़ रुपये दिए हैं उसका हिसाब जरूर दें। प्रदेश के 12 जिलों में कितना पैसा गया, उसका हिसाब जरूर दें। हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं। केंद्र सरकार इनके मनसूबों को पूरा करने के लिए जो योजनाओं बना कर भेजेंगे उसी पर पैसा आएगा। आपने एयर सर्वे किया। आपने मण्डी, चम्बा और कांगड़ा का एयर सर्वे किया। आप भी आए थे और हम भी पहुंचे थे तो जो कहा है वह पूरा होगा क्योंकि वह पत्थर पर लकीर है। मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। किसको सबक सिखाएंगे? तुम भी प्रतिनिधि हो और हम भी प्रतिनिधि हैं। आज आप मंत्री हैं और कल मंत्री नहीं रहेंगे तथा हमें इसका पता है। हमारी विचारधारा के ऊपर जिस तरीके से छिंटाकशी की गई, कृपया करके वह अशोभनीय थी, तर्कसंगत नहीं थी और हमारे लिए वह बहुत कष्टदायी थी। मैं यही कहना चाहता हूं। प्राकृतिक आपदा में समाज, सुलह विधान सभा क्षेत्र और पूरा प्रदेश ग्रसित है परन्तु आप उसके लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे हैं। सभापति महोदय, आपने बार-बार घंटी बजाई मैं क्षमा चाहता हूं। शायद आपकी कोई मजबूरी होगी इतनी घंटी तो मैंने तब नहीं बजाई जब मैं उस कुर्सी पर विराजमान था। मैंने उस समय हमेशा ध्यान रखा है कि लोकतंत्र की आवाज मजबूत रहनी चाहिए। सभ्य शालीनता हमारे व्यवहार में है। किसी के बारे में बोलना हमारा स्वभाव नहीं है। आपने समय दिया, धन्यवाद।

**सभापति** : माननीय सदस्य आप अपने साथियों का बहुत सारा समय ले गए हैं। राजस्व मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

01-12-2025/1700/NS-AS/2

**राजस्व मंत्री** : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तीन-चार बार मेरा नाम लेकर बोला है इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप मेरा नाम नहीं लेते तो मैंने नहीं बोलना था और अंत में ही बोलना था। सभापति महोदय, माननीय विपिन सिंह परमार जी वरिष्ठ सदस्य हैं और इस विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं तथा मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने Blow hot and cold वाली बात कही। आखिर में इन्होंने कहा कि इतनी आपदा है। एक ही सांस में कह गए कि आपदा क्यों घोषित की है? इनकी बातों और तर्क में विरोधाभास है और इन्होंने अपनी बात को स्वयं ही काट दिया है। ये पता नहीं क्या बोलना चाह रहे थे और कैसे बोलना चाह रहे थे? ये उसमें खुद ही फंस गए हैं। अब बात यह रही कि आपदा में सदन में चर्चा क्यों हो रही है और सदन क्यों चला हुआ है? मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपदा वर्ष 2023 में चरम सीमा पर थी और ये बार-बार हल्ला कर रहे थे कि विधान सभा का सत्र बुलाओ और इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब सदन बुलाया गया, तीन दिन चर्चा हुई और जब हमने केंद्र सरकार से मदद के लिए प्रस्ताव पारित किया तो ये सदन से बाहर चले गए। इन्होंने अभी यहां पर बहुत कुछ कहा है। हमने कहा कि ठीक है कि विपक्ष को कहने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने एक बात फिर नहीं कही और उसको इन्होंने गोलमोल कहा कि पत्थर की लकीर है। इसी धर्मशाला के अंदर 1500 करोड़ रुपये जो घोषणा हुई उसका एक पैसा नहीं आया। ऐसा कौन सा पत्थर है जिसकी लकीर खींचने में तीन महीने लग गए? अभी भी ये कह रहे हैं कि छैणी से खींच लें। आजकल जमाना लेज़र का है खींच देते हैं। आपके तो महापुरूष लोग हैं। ये अपनी बात ही नहीं रख पाए। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। बाकी मैं जवाब दूंगा। आपने 5500 करोड़ रुपये के बारे में कहा है। अब तो मेरे कान पक गए।

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.12.2025/1705/RKS/AS-1

राजस्व मंत्री... जारी

मैंने अपने विभाग का एक पैम्फलेट छपवाकर सभी माननीय सदस्यों को दिया है। उसमें 5500 करोड़ रुपये का पूरा चिट्ठा दिया है। आप उसे पढ़कर देख लें। मैंने यह सब Black and White में दिया है। मैंने उसमें 5500 करोड़ रुपये का पूरा हिसाब-किताब दिया है।

**सभापति :** अब माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर गौड़ जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री भुवनेश्वर गौड़ :** अध्यक्ष महोदय, श्री केवल सिंह पठानिया जी ने जो नियम-130 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं इसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे क्षेत्र में वर्ष 2023 में भी बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था और इस वर्ष जब विधान सभा सत्र चला था तो उस समय मेरे चुनाव क्षेत्र में बाढ़ आई। मैं विधान सभा सत्र को छोड़कर जब मनाली गया तो मैं मंडी होता हुआ वहां पहुंचा। बीच में सड़कें काफी खराब थीं जिस कारण मुझे काफी पैदल चलना पड़ा। इस वर्ष जो बाढ़ आई उसने हमारे क्षेत्र की संपूर्ण आर्थिकी को नुकसान पहुंचाया। चाहे वह हमारा पर्यटन का सीजन था क्योंकि सड़कें टूटी हुई थीं जिस कारण पर्यटक मनाली नहीं आ पाए। जो कारोबारी पर्यटन से जुड़े हुए थे उनको भी भारी नुकसान हुआ। हमारी होर्टिकल्चर बैल्ट है। जब सेब सीजन पीक पर था तो उस समय सड़कें टूटी थीं, नेशनल हाइवे टूटा हुआ था जिसके कारण हमारे ग्रोअर्ज को अच्छे रेट नहीं मिल पाए। जिन लोगों का सब्जियों का कारोबार था उनका भी यही हाल हुआ। लाग अपनी सब्जियों को मार्किट तक नहीं पहुंचा पाए। इसी कड़ी में हमोर क्षेत्र में 26 सितम्बर को भारी बारिश के कारण मनाली गांव के मनालसू नाले में स्थापित मोटरेबल पुल को क्षति पहुंची और वह पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गया। मेरे चुनाव क्षेत्र में दुर्गम क्षेरी गांव है जहां पर बाढ़ आने के कारण एक बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हुआ। हम प्रदेश सरकार के धन्यवादी हैं क्योंकि जैसे ही मनाली में बाढ़ आई माननीय मुख्य मंत्री जी तुरंत मनाली पहुंचे। हमारी जो बिजली-पानी की योजनाएं बाधित हुई थीं उनके आने से वे एक रिकॉर्ड समय में सुचारु रूप से बहाल हो गई। हम माननीय मुख्य मंत्री जी के धन्यवादी हैं जिन्होंने हमारे मनाली गांव और ऊपरी क्षेत्र सनाग, गुशाल तथा भुरूआ गांव को जोड़ने के लिए एक पुल दिया जिसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और 2-4 दिन के बाद वहां ट्रैफिक सुचारु रूप से चलना शुरू हो जाएगा। क्षेरी गांव में एक बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। हम प्रदेश सरकार के दोबारा से

01.12.2025/1705/RKS/AS-2

धन्यवादी हैं जिसने एक रिकॉर्ड समय में वहां एक झूला लगाया जिससे हमारे क्षेत्रवासियों के सेब मेनलाइन तक पहुंचे और उन्हें अच्छे दाम हासिल हुए। इसी कड़ी में मैं पुनः मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे लोगों को मुआवजा राशि दी। वर्ष 2023 में जब बाढ़ आई थी तो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 7 लाख रुपये दिया गया था और इस बार इस रकम को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया है।

श्री... बी0एस0द्वारा जारी

01.12.2025/1710/बी.एस./डी.सी.-1

श्री भुवनेश्वर गौड़ जारी...

और जिनके पार्शियल डैमेजेस हुए हैं, उनके लिए भी यह रकम बढ़ाई गई है। इस वर्ष जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र में कटराईं में एक बहुत बड़ी गौशाला थी जिसमें 1200-1400 के करीब पशु रखते थे। वह गौशाला भी पूर्ण रूप से इस बार ध्वस्त हुई है। अभी तो हमने थोड़ी बहुत करके उसे सुचारु करने का प्रयास किया है। हम प्रदेश सरकार से भी निवेदन करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी गौशाला हमारे क्षेत्र में है। उसके लिए भी आने वाले समय में कोई अच्छी तरह से कोई राशि आवंटित की जाए ताकि वह भी एक सुरक्षित क्षेत्र बनें। एक बात में और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी जमीनें नदी या नालों के साथ थी और उनकी जमीनें बहुत बर्बाद भी हो गई और बह भी हो गई। मैं सरकार से एक आश्वासन भी चाहूंगा और एक मांग भी रखूंगा कि इस बार जिन लोगों की जमीनें गई हैं सरकार उन्हें तबादले के तौर कहीं और जमीन दें ताकि वह अपनी गुजारिश करने के लिए दोबारा प्रयास कर सकें। हमारे क्षेत्र में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई जमीन नहीं है जितनी जमीन है वह सारी फॉरेस्ट लैंड है। इन लोगों का एक बार तबादला हो जाए तो यह लैंड लैस तो न कहलाएं। मैं एक बार दोबारा से प्रदेश सरकार, मुख्य मंत्री जी और उप मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने पिछली बाढ़ के बाद हमारे क्षेत्र में तकरीबन 70 करोड़ रुपए फ्लड प्रोटेक्शन के लिए दिए जिससे बहुत सी हैबिटेशंस जो व्यास नदी के साथ थी जैसे वह आलू ग्राउंड हो, कलाथ हो 17 मील हो, 16 मील हो, पतली कुहल हो, रायसन हो या वाशिंग हो। यहां पर अमूमन यह देखा जाता था जब भी बाढ़ आती थी लोग अपने घर छोड़ कर पलायन कर देते थे जो फ्लड प्रोटेक्शन वाल्स हमारे क्षेत्र में

लगी है इससे इस बार जो हैबिटेशन इन क्षेत्रों में थी उसी वजह से वे लोग अपने घरों में आराम की नींद सोए हैं। एक और मांग में करना चाहूंगा कि इसी तरह से जो हमारी व्यास नदी है इसमें ड्रेजिंग का कार्य है वह जल्दी-से-जल्दी शुरू करवाया जाए, क्योंकि जो वॉल्यूम हमारे क्षेत्र में और हमारी नदी में पानी की है उसकी वजह से जो मक है वह बहुत सी जगह पर बहुत ऊंचा कलेक्ट हो गया है अगर यह मक वहां से निकाला जाता है तो आने वाले समय में फ्लड्स का डर हमारे क्षेत्र में कम हो जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

01.12.2025/1710/बी.एस./डी.सी.-2

**सभापतिः** अब माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री प्रकाश राणा :** सभापति महोदय, प्रदेश में आई आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं और जो कठिनाइयां आई हुई हैं उसमें सरकार द्वारा जो कार्य किए गए उसमें क्या कमी है उस संदर्भ में मैं बोलने के लिए यहां खड़ा हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह आपदा वर्ष 2023 में आई और हमारी काफी पंचायतें इससे प्रभातिव हुई हैं। मैंने पहले भी नाम पढ़े थे अगर आप चाहें तो फिर से पढ़ देता हूं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**01.12.2025.1715.डी0टी0-डी0सी0.-1**

**श्री प्रकाश राणा जारी...**

वर्ष 2023 में भी हुई वर्ष 2024 में थोड़ी कम प्रभावित हुई और वर्ष 2025 में वहां और ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन यह सोचने की बात है की वर्ष 2023, 2024 व वर्ष 2025 में, इसके आंकड़े सरकार के पास भी होंगे, जिस प्रकार से घोषणा हुई थी की 4500 करोड़ रुपये का पैकेज वर्ष 2023 में दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में कहना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में जो सड़कों पर लैंड स्लाइडज हुए थे उनका मलवा भी अभी तक सड़कों पर ही है, ये वर्ष 2023 की बात है। वर्ष 2025 में भारी वर्षा के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में टिक्करी मुशैहरा का एक गांव है वह खतरे में आ गया और उस गांव के लगभग 40 परिवार गांव छोड़ कर कहीं अन्य स्थान में रहना पड़ा। कोठी, चुल्ला, नेरी-लांगणा,

पीपली, खारसी, गुम्मा, भराड़ू, नौहली और पंडोल के क्षेत्र बाढ़ से काफी प्रभावित हुए। मैं सरकार से साढ़े चार हजार करोड़ रुपये के पैकेज के बारे मे पूछना चाहता हूं। टिक्करी मुशैहरा का सारा गांव चपेट में आया था। मंडी के काफी क्षेत्र प्रभावित हुए थे लेकिन अगर मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात करूं तो जिस तरह से वहां नुकसान हुआ था उसमें हमें डेढ़-दो सौ करोड़ रुपये जारी होने चाहिए थे। मुझे नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र की सड़कों के लिए 4-5 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हों। बरसात खत्म हुए 2-3 महीने हो गए लेकिन आज भी वहां कई सड़कें बंद हैं। लोगों के घरों के डंगे चले गए हैं, सड़के हवा में झूल रही है। लोग परेशान हैं, वहां शादियों का सीजन चला हुआ है। कई बुजुर्ग लोग बीमार पड़े हैं। हम सड़क खोलने की बात कर रहे हैं और जब प्रशासन को बोलते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। वहां पर ऑप्टीकल फाइबर लाइन बिछी थी जिसमें लगभग 150 किलोमीटर सड़कें खोदी गई हैं। उसके लिए जो 10-15 करोड़ रुपये आए थे उसमें कम-से-कम नालियां ही बन जाती तो अच्छा होता। हमने यह बात पहले भी उठाई थी। आपने एक्सिअन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा था लेकिन मुझे नहीं लगता वह हुई होगी। दो-अढाई महीने उन्हें पता नहीं कहां बिठा दिया फिर दोबारा से वहां ले आए। मैं सदन को कहना चाहूंगा कि एक्सिअन ने 8-10 महीने के अंदर 2900 टेंडर लगवा दिए। उन्होंने उस पैसे का पता नहीं क्या किया और वह सारा पैसा खत्म हो गया। यह सोचने की बात है कि 8-10 महीनों में इतने टेंडर कैसे लग गए? इस तरह का भ्रष्टाचार वहां पर चल रहा है। यह बात नहीं है कि कहां कितना नुकसान हुआ लेकिन जो बात आप सदन में कहते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले आप यह बताएं कि साढ़े चार हजार करोड़ रुपये कहां है? यह पैसा आपने किसको दे दिया? वह पैसा कहां खर्च किया गया इसका क्लीयर हिसाब यहां पर होना चाहिए। आप घोषणाएं कर रहे हैं और लोगों

**01.12.2025.1715.डी0टी0-डी0सी0.2**

को झूठे प्रलोभल दिए जा रहे हैं जोकि गलत बात है। मुझे खुशी है कि आज सदन सुचारु रूप से चला। हम इसलिए यहां बैठे हैं ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। हम टाइम पास करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। आज सैंकड़ों होटल्स के कमरे यहां पर बुक हैं। इसलिए इन चीजों का यहां पर हल होना चाहिए लेकिन यहां कोई हल नहीं होता। आज मुख्य मंत्री जी ने बताया कि हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। यह बात इनको पहले ही बता देनी चाहिए

थी। हम भी देख रहे हैं कि यह प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आज प्रदेश के यह हालत है।

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1720/एच.के.-एन.जी./1**

**श्री प्रकाश राणा........जारी**

आज प्रदेश के यह हालत है। सभापति महोदय, आप इस बात को समझते हैं कि आज प्रदेश के हालात क्या हो गए हैं? हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि कहां से पैसा आएगा यानी आय के साधन कैसे बढ़ाने हैं। हम तो कभी केन्द्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं या कभी अन्य एजेंसियों को कह रहे हैं कि हमारी मदद कर दो। ऐसे हालातों में कौन मदद करेगा या कितनी मदद कर देगा? हमें स्वयं अपने संसाधन जुटाने होंगे और हम सब यहां पर इसीलिए बैठे हुए हैं। हम सभी को जनता ने इसीलिए चुना है। आज प्रदेश के क्या हालात हो गए हैं, उनको देखने की आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जनता ने आपकी सरकार बनाई हुई है और आपसे उम्मीदें लगाई हुई हैं। आपसे जनता यह नहीं सुनना चाहती कि हम कर्ज के बोझ तले फंस गए हैं। आपका काम है कि प्रदेश को कर्ज से बाहर कैसे निकालें और इसके लिए आपको कड़े फैसले लेने होंगे। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहां से आप कड़े फैसले ले भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आपको ही तय करना है कि हिमाचल प्रदेश को कैसे चलाना है। इस प्रकार से बहाने मारने से प्रदेश नहीं चलेगा। आज इस प्रदेश की क्या स्थिति है? आपको हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना था लेकिन आपसे नहीं हो पाया। आपकी सरकार व पूर्व की सरकारों ने जिन बातों पर ध्यान देना था, वह नहीं किया। हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं आंकड़ों को स्वयं देखता हूं कि

इस प्रदेश के हालात ठीक नहीं हैं। हमारे आय के स्रोत वहीं-के-वहीं हैं। काफी समय से प्रदेश की वार्षिक आए 40 से 42 हज़ार करोड़ रुपये ही है और यह भी केन्द्र सरकार के टेक्सिस आदि से मिलने वाले हिस्से के कारण है। यह पिछले तीन वर्षों का आंकड़ा है और यह इससे आगे क्यों नहीं गया? इसको बढ़ाने का फैसला किसने लेना है? हम सभी ने ही यह फैसला लेना है कि आय के स्रोतों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। इस प्रकार से यह प्रदेश कैसे चलेगा? मेरा यह कहना है कि हमारे प्रदेश को हर माह लगभग 3600 करोड़ रुपये की आय हो रही है।

**01.12.2025/1720/एच.के.-एन.जी./2**

इसके हिसाब से प्रतिदन 115 से 120 करोड़ रुपये की आय हो रही है। काफी समय से यही आंकड़ा चला हुआ है। यदि हर माह लगभग 3600 करोड़ रुपये की आय हो रही है और खर्चा लगभग 6000 करोड़ रुपये का हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? हर दिन लगभग 115 से 120 करोड़ रुपये की आय में केन्द्र सरकार से मिलने वाला शेयर भी शामिल है जोकि लगभग 55-60 प्रतिशत है। मैं हिसाब लगा रहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतिदिन 40 से 45 करोड़ रुपये सैलरी देने के लिए चाहिएं। इसी प्रकार पेंशन देने के लिए प्रति माह लगभग 1000 करोड़ रुपये चाहिएं जोकि प्रतिदिन 30 से 35 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन को चुकाने के लिए भी पैसा चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है और कर्ज का आंकड़ा लगभग 1,05,000/- करोड़ रुपये हो गया है। इस कर्ज को चुकाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को हर दिन लगभग 35 से 40 करोड़ रुपये चाहिएं। इन तीनों को जमा करने पर लगभग 120 करोड़ रुपये बनते हैं। हमारी एक दिन की आय भी लगभग 120 करोड़ रुपये है और केवल तीन चीजों पर ही प्रतिदिन लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रदेश के अस्पताल व शिक्षण संस्थान कैसे चलेंगे? सड़कें व पेयजल-सिंचाई योजनाएं कैसे बनेंगी? हमें सबसे पहले इस पर चर्चा करनी चाहिए कि

प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर की जाए। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब यहां पर आते हैं तो इस माननीय सदन में ड्रामा नहीं चलेगा और बाहर आते हैं तो हा-हू करके चले जाते हैं। प्रदेश की जनता ने हम सभी को चुना है और हम सभी का फर्ज है कि हम उनके हित की बात करें। इस सदन में प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें। हमें चर्चा करनी चाहिए कि प्रदेश के आय स्रोतों को कैसे जनरेट करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह सब झूठ है। मुख्य मंत्री जी व उनके मंत्रिगण मुझे बता दें कि वे पैसा कहां से लाएंगे? मुझे बता दीजिए

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

**01.12.2025/1725/एच0के0-पी0बी0/1**

**श्री प्रकाश राणा ...जारी**

कि पैसा कहां से आएगा? प्रदेश में बार-बार परिवर्तन हुआ है और सरकारें बदली हैं। फिर आप कहते हैं कि पिछली सरकार हमारे लिए विरासत में यह कर्ज छोड़कर गई है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि श्री जय राम ठाकुर 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में छोड़ गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि हम बार-बार एक दूसरे को दोष देते रहते हैं जोकि ठीक बात नहीं है क्योंकि इससे प्रदेश के कर्ज का कोई हल नहीं निकलेगा।...(व्यवधान) यदि किसी ने गलत किया है तो सरकार उसके खिलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करती? आप तीन वर्षों से सत्ता पक्ष में क्यों बैठे हैं? आपको इसके खिलाफ कोई निर्णय लेना चाहिए लेकिन आप केवल बहाने-बाजी करते हैं। अब बहुत हो गया है और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एक माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर जी को 75 हजार करोड़ रुपये कर्ज के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं ...(व्यवधान) तो कोई 90 हजार करोड़ रुपये कहता है। सभी अलग-अलग राशि बताते हैं। सभापति महोदय, हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पर इतना कर्ज कैसे हुआ? अगर हमें इस कर्ज के लिए 35-40 हजार करोड़ रुपये दिन का नहीं भरना पड़ता तो महीने का कम-से-कम 1200-1400 करोड़ रुपये बच जाता। यदि हमें यह

राशि कर्ज के लिए नहीं देनी पड़ती तो हर विधान सभा क्षेत्र को महीने का 20-25 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए मिलता लेकिन अब यह पैसा बैंकों को जा रहा है। यदि 20 करोड़ मेरी कॉन्स्टीच्यूएंसी को मिलता तो मैंने वहां पर कई विकास कार्य करने थे लेकिन मुझे इतना तो एक वर्ष में भी नहीं मिलता। ...(घण्टी) मेरा आपसे आग्रह है कि पूर्व में जो भी मुख्य मंत्री रहे हैं, वे सभी हमारे लिए माननीय हैं लेकिन इस कर्ज में जिस-जिस की भी भागीदारी है उनकी लिस्ट सदन में ले कर दीजिए ताकि हम एक-दूसरे पर आरोप लगाना बंद कर दें। किस मुख्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में कितना कर्ज लिया, इसकी सूची सदन में ले होनी चाहिए। इससे कम-से-कम एक बात तो खत्म हो जाएगी क्योंकि सदन में जब भी कर्ज पर बात हुई है तो यही होती है कि किसने कितना कर्ज का पैसा खाया है।

**01.12.2025/1725/एच0के0-पी0बी0/2**

इसलिए हम भी देखना चाहते हैं कि कौन क्या कर गया है। मैं इस सदन में वर्ष 2017 में चुन कर आया और वर्ष 2018 में सरकार बनी। उस समय प्रदेश पर 47,200 करोड़ रुपये का कर्ज था और अब सात-आठ वर्षों में यह बढ़कर एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये हो गया है। अगले सात सालों में यह कर्ज दोगुना होकर ढाई लाख करोड़ रुपये हो जाएगा लेकिन हमारी इतनी इन्कम नहीं है जिससे हम यह कर्ज भर सकें। सरकार ने अभी तक इसके लिए कोई संसाधन क्यों नहीं जुटाए? क्यों सरकारें चुप रहीं और लगातार कर्ज लेती रहीं? मुख्य मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं है लेकिन सत्ता पक्ष के बाकी सदस्य सदन में मौजूद हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है लेकिन इसके लिए मुख्य मंत्री जी को स्टेंड लेना होगा। जनता ने आपको चुनकर भेजा है लेकिन आपने तीन वर्षों तक क्या किया? आपने इन्कम सोर्सिस क्यों नहीं जनरेट किए? ...(व्यवधान) यदि आपने किए हैं तो उससे हमें भी अवगत करवाईए कि आपने कितने करोड़ की इन्कम जनरेट की है। आपने 35-40 हजार रुपये का कर्ज क्यों लिया है? आपने इस बारे में कोई हल क्यों नहीं निकाला? जनता यह नहीं सोचती है कि कर्ज किसने लिया जिन्होंने गलत किया वह विपक्ष

में आ जाता है। आप सत्ता पक्ष में है इसलिए आप तो कुछ अच्छा कीजिए।...(व्यवधान) सरकार को तीन साल हो गए हैं और अगर आप इस बारे में कुछ कर रहे हैं तो हमें वह कब बताओगे? आज प्रदेश के ऐसे हालात हैं कि हमें भी किसी-से पैसा मांगने में शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक सरकार ने इन्कम सोर्सिस की बात की है? यह एक दुःख की बात है कि आज जब प्रदेश में बच्चा पैदा होता है तो हम उसे 1.5 लाख रुपये के कर्ज का गिफ्ट दे रहे हैं। सरकार नई पीढ़ी को भी इस कर्ज में क्यों धकेल रही हैं? हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कई अवसर हैं। हिमाचल में साधनों की कमी नहीं है लेकिन इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा है। सभी एक ही बात पर टिके रहते हैं कि कर्ज लेते रहो और उसे भरते रहो। अब कर्ज लेने की भी लिमिट हो गई है इसलिए सरकार के हाथ अब खड़े हो गए हैं। फिर सरकार चाहती है कि प्रदेश में विकास हो लेकिन इस तरह से कैसे विकास होगा? हमारे पास विधायक निधि भी नहीं है, बेचारे बुजुर्ग पेंशन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जो पटवारी हैल्पर या आई0पी0एच0 के कर्मचारी

**01.12.2025/1725/एच0के0-पी0बी0/3**

4-5 हजार में नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी वह समय पर नहीं मिल रही है। बुजुर्ग पेंशन भी नहीं मिल रही है

**श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1730/Y.K./A.P./ 01**

**श्री प्रकाश राणा ......जारी**

बुढापा पेंशन को भी आज पांच से छः महीने हो गये है वे भी नहीं दी गई है। लोग हमें पूछते है कि क्यों नहीं दी जा रही पेंशने।

**सभापति :** माननीय सदस्य, please wind-up.

**श्री प्रकाश राणा :** सर, मेरी आपसे बिनती है, कृप्या मुझे बोलने दें।

**सभापति :** विषय पर बोले, आप तो फाईनैंस की बातें कर रहे हैं।

**श्री प्रकाश राणा :** सभापति महोदय, आप खुद बताएं की आपदा तो तभी जाएगी न जब आपके पास पैसा होगा। पूरी समस्या तो पैसे की है। यहां पर पैसा होगा तभी तो आपदा जाएगी। अगर प्रदेश सरकार के पास पैसे होते तो हम आपदा को दो महिने में ही ठीक कर देते। आप ही बताइए कि हम कहां जाए? मैं सिर्फ सरकार को नहीं बोल रहा, बल्कि हम सबको प्रदेश के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे ताकि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ा सके। हमें खर्चे कम करने पड़ेंगे। सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा नहीं तो यह सदन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। आप ही बातओ की यह सदन कैसे चलेगा, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमें मालूम है कि जनता बहाने नहीं सुनना चाहती की आज आपकी स्थिति ऐसी है, कल वैसी थी। जनता यह नहीं सुनना चाहती कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या प्रदेश सरकार कर्ज में डूब रही है। हमें फैसले लेने होगें। जिस तरह के भी हम फैसले लें, वे सभी फैसले जनता के हित में हो। हमें जनता के हित में फैसले लेने पड़ेगें। जिस तरह से हमारे प्रदेश में आपदा आई है, अगर कल को किसी और प्रकार की आपदा आ गई तो आप क्या करोगे? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? अगर हम इंडस्ट्री या फैक्ट्री आदि लगाए तो हम प्रदेश के लिए आर्थिक सहयोग कर सकते है। माईनिंग, होटल आदि से अगर हम अपनी आर्थिकी को सुधारें। अभी हमारे सभी बोर्ड व निगम घाटे में हैं। हम कुछ ऐसे काम करें जिससे हमें इन सभी जगह से फायदा हो। प्रदेश के हाईड्रो प्रोजैक्ट्स से हम आर्थिक स्थिति को सुधारे। क्योंकि हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब भी हम सदन में आते है तो यहां पर यही बात होती है कि मुझे मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए

**01.12.2025/1730/Y.K./A.P./ 02**

कुछ नहीं मिला। आप ही बताए कि कहा से मिलेगा, पैसा कहा है? प्रदेश सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो आप ही बताए हम पैसा किससे मांगे? इस समय प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और इस स्थिति को सुधारने का समय अब आ गया है। हमारा हिमाचल प्रदेश देव भूमि है और आज के समय में वही देव भूमि वित्तीय संकट में है। हमें मालूम है कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज खराब है। हम तो यही सोच रहे है कि

हमारे पिछले पांच साल निकल गये। अगर दोबारा जीते तो फिर से आएंगे, नहीं तो चल पड़ेगें। लेकिन हमें इस स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ-न-कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपका फोकस यह होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाए। हमे डरामेबाजी नहीं चाहिए। ...(व्यवधान) चलो जो भी हुआ लेकिन हम आगे तो कुछ करें। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं कि सिर्फ इसी बारे में बात होनी चाहिए कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारे। हमें प्रदेश की स्थिति को समझना चाहिए। हमने पूरी उम्र यही काम किया है। पहल तो सरकार की ओर से ही होगी। अभी आप बोल रहे थे कि प्रधान मंत्री जी द्वारा जो 1500 करोड़ रुपये के आपदा राहत पैकेज की घोषणा की गई है, वह अभी तक प्रदेश सरकार को नहीं आए है। आप एक महीने का तो अपना काम कर लोगे। लेकिन अगर प्रदेश में कल ही कोई आपदा आ गई तो क्या करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपने साधन जुटाने होगें। जो आदमी दूसरे के कामों में नजर रखता है वे कभी कामयाब नहीं होता है। हमें अपने लिए साधन जुटाने होगें। अब आप सोच रहे हैं कि वह पैसा कब मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि मांगने का भी तरीका होता है। केंद्र सरकार द्वारा आपको दिया भी जा रहा है और ऊपर से आप दोष भी लगा रहे हैं। अगर आप संकट में है तो आपको अपने लिए साधन जुटाने होते हैं। हम जिस तरह से हाल ही के दिनों में एक दूसरे पर किचड़ उछाल रहे थे कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मुर्दाबाद, जिन्दाबाद आदि। हिमाचल प्रदेश की जनता यह नहीं देखना चाहती, बल्कि जनता यह देखती है कि कौन-सी सरकार क्या काम कर रही है। ...(व्यवधान)

**Chairman :** Please, please. ...(Interruption) Wind-up please.

**श्री प्रकाश राणा :** आज भी यह सदन वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे 25 से 40 वर्ष पहले चलाया जाता था। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, आज टैकनोलोजी

**01.12.2025/1730/Y.K./A.P./ 03**

का जमाना है। आज भी हम एक दूसरे के ऊपर किचड़ उछाल रहे हैं। यही बोल रहे हैं कौन क्या खा गया। अगर आपको लगता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है तो उसके ऊपर कार्रवाही करो। हम हिमालच की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी सरकार है

आपको कार्रवाही करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके ऊपर कार्रवाही होनी चाहिए। जो गलत है वह गलत है।

**Chairman :** Please wind-up.

**श्री प्रकाश राणा :** मैं आपको एडवाईज नहीं दे रहा बल्कि सुजेशन दे रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

**01.12.2025/1735/AT/YK /.01**

**श्री प्रकाश राणा जारी...**

मैं एडवाइज नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं और वह यह है कि हम प्रदेश के लिए कुछ कर जाएं। अगर कोई अच्छी बात बोल रहा हो तो उसे सुन लेना चाहिए। मैं प्रदेश के हित की बात कर रहा हूं इसलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं वर्तमान सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हू। मैं यह थोड़ी कह रहा हूं कि इन्होंने प्रदेश को कर्ज में डुबाया कर्ज तो पूर्व सरकारों के समय से चला आ रहा है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी उन पर भी गलत आरोप लगे कि वह विरासत में 80,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गए। यह गलत बात है। वह समय भी मैंने देखा है। वर्ष 2017 में हम चुनकर आए थे। उस समय कोविड लगा, कोरोना के कारण बहुत समस्या आई, फिर भी कर्ज कंट्रोल में था। देखिए वर्ष 2018-2019 में उन्होंने काम किया। वर्ष 2020 में कोरोना लग पड़ा। यह सचाई सामने होनी चाहिए। वर्ष 2021 में कोरोना था और 2022 में चुनाव लग पड़े। उस वक्त यही था इस चीज को आप सब सोचो। ...(व्यवधान)

**Chairman :** Please don't disturb. ...(Interruption) Hon'ble Member please wind-up now.

**श्री प्रकाश राणा :** सभापति महोदय, मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे कि कैसे भी इस कड़ी से निकलें, ताकि हमारे हालात सही हों। मैं सरकार से यही कहना

चाहता हूं कि आप जितने भी इनकम सोर्सिज जनरेट करना चाहते हैं आप करें। अगर जनरेट नहीं कर सकते, तो अपने खर्चे को कम करें। सरकार अपने खर्चे क्यों नहीं कम कर रही? सरकार खर्चा तो कम कर ही सकती है, क्योंकि सबकुछ सरकार के हाथ में ही है। यह जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ फॉर्च्यूनर गाड़ी में ही चलना जो 60 लाख रुपये की है। ...(व्यवधान)

**Chairman :** Please wind-up now.

**01.12.2025/1735/AT/YK /.02**

**श्री प्रकाश राणा :** सभापति महोदय, सबके लिए महिंद्रा की जीप कम्पलसरी कर दो, हमारे लिए भी कम्पलसरी कर दो। पहले के हालात कुछ और थे, अब हमारे हालात खराब है। ...(व्यवधान)

**Chairman :** Hon'ble Member, please address to the Chair.

**श्री प्रकाश राणा :** सभापति महोदय, आज के हालात कुछ और हैं। हम भी इसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमारा प्रदेश देवी-देवताओं का प्रदेश है। इसलिए हमें इस प्रदेश की कदर करनी चाहिए। अब हम प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं और करेंगे भी। हमने जो कदम उठाए हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। हमें अब यही सोचना चाहिए कि हिमाचल को कर्ज से कैसे बाहर निकालें। इसके लिए मिल-जुलकर प्रयास करने होंगे। एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा न आपका भला, न सरकार का, और न ही हमारे विधानसभा क्षेत्रों का, प्रदेश का कर्जा हम सबके लिए एक बदनामी है। इसलिए प्रदेश हित में फैसले इसी सदन में लो।

सभापति महोदय, मैं अपना एक निर्णय ले रहा हूं कि जब तक यह प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, **मैं प्रकाश राणा, विधायक, जोगिंद्रनगर, आज के बाद हर माह सिर्फ एक रुपया सैलरी लूंगा, जब तक प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर नहीं आता। और इसके लिए मैं अन्य प्रयास भी करूंगा।** माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में वित्त की बहुत कमी है, वह सही बोल रहे हैं। प्रदेश इस समय वित्तीय संकट में है। प्रदेश की जो

इनकम है, उससे तीन ही चीज़ें ठीक से नहीं चल पा रहीं हैं। मेरे जीवन में भी एक बार संकट आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। उस संकट के कारण मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसके बावजूद हमने बहुत कुछ देखा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मैं न गया हूं। हम जीवन में आर्थिक रूप से गिरे, लेकिन फिर उठे।

मैं इस माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसने मुंबई जाकर दो-दो रुपये में कार वॉश भी किया है। लेकिन फिर भी मैंने मेहनत की और जीवन में बहुत कुछ पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम हिमाचल के लिए अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। **इसलिए मैं अब से सिर्फ एक रुपया वेतन के रूप में लूंगा, जब तक हिमाचल**

**01.12.2025/1735/AT/YK /.03**

**प्रदेश वित्तीय संकट से नहीं उभर जाता।** अगर मुझसे अनजाने में कोई गलत शब्द बोला गया हो, तो उसके लिए भी मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मेरा किसी से कोई वैर-विरोध नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारा प्रदेश आर्थिक संकट से बाहर निकले और इस पर हमें काम करना चाहिए। आज प्रदेश में आपकी सरकार है, कल हमारी सरकार आएगी। हम प्रदेश के लिए बड़ा कुछ करेंगे। लेकिन अभी भी हम बड़ा कुछ करने को तैयार हैं। अगर प्रदेश बचेगा तभी हम सभी विधायकगण इस सदन के अंदर और प्रदेश में रहेंगे। अगर प्रदेश ही चला गया, तो हम सब क्या करेंगे? जिस प्रदेश की सरकार सैलरी, पेंशन और रिपेमेंट ही नहीं दे पा रही है तो वह प्रदेश कैसे चलेगा, आप खुद भी इसके बारे में सोचिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**एम0डी0 द्वारा जारी ......**

**01-12-2025/1740/AG/MD/1**

**सभापति :** अब इस चर्चा में संसदीय संसदीय कार्यमंत्री (उद्योग मंत्री) जी भाग लेंगे।

**उद्योग मंत्री** : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। अभी माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। वे पहले भी यह बातें कहते रहे हैं, पर किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। मैंने तो पहले भी उनका समर्थन किया है। आज प्रदेश जिस आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने भी जिक्र किया जब विधायक निधि की बात आई कि सरकार में विकास और काम होगा तब ही आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आज जो स्थिति है इसमें एक दूसरे को ब्लेम करने का समय नहीं है। आपने ठीक कहा चाहे कोई भी सरकार आ जाए, इस प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यह व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि हम debt trap में फंसते जा रहे हैं। आपने कहा कि salary, pension, loan repayment and interest यह चार चीजें का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जबकि रिर्सोजि बढ़ नहीं रहे। मैं एक बात विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप स्वयं भी व्यापारिक समुदाय से जुड़े हैं। मैंने मंत्री कार्यालय में रहते हुए और सत्ता में रहते हुए यह देखा कि जब भी किसी सरकार ने आवश्यक सुधार करने की कोशिश की, मान लो जैसे 118 का मसला ही ले लीजिए। इसे 50 वर्ष पहले हमारे पुराने लोंगो ने यह सोच के किया था कि हिमाचली के to protect the land of the State, परंतु आज 118 में कहता हूं as a Minister सोर्स ऑफ करप्शन का स्रोत बन गया है। पिछली श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार में इसमें सुधार का प्रयास किया, तो हमने भी राजनीतिक आधार पर विरोध कर दिया। विरोध सिर्फ विरोध के लिए करना आज एक चलन बन गया है। कुछ ऐसे इश्यू है जिस पर पक्ष और विपक्ष को कंन्सेंजिस बनाना पड़ेगा और ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिसमें चाहे वह पावर प्रोजेक्ट्स हों, उद्योग, रियल एस्टेट, या होटल इंडस्ट्री। ये नीतियां 'कटीन्यूअस होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक सरकार ने किया अब इन्वेसटर है वह इन्वेसटर आएगा एक सरकसरा उसको प्रोजेक्ट रियायतें और शर्तें दे देगी और अगली सरकार आते ही वे सब रद्द कर दिए जाते हैं। इससे हिमाचल प्रदेश की छवि राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। मैं तो as Industries Minister नेशनल प्रोग्राम में जाता हूं और स्टेटस में मैं देखता हूं

---

**01-12-2025/1740/AG/MD/2**

कि जब तक हम अपने सिस्टम में परिवर्तन नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उत्तराखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, हमसे बाद में बना, in terms of investment में हमसे बहुत आगे निकल गया है। मैंने श्री जय राम जी को एक दिन कहा कि आज जो हमारी स्थिति है अगर बी0जे0पी0 की सरकार वर्ष 2022 में दोबारा आ भी जाती, तब भी आर्थिक स्थिति आज जैसी ही होती, अलग नहीं। क्योंकि गर्वमेंट ऑफ इंडिया चाहे केंद्र में एनडीए की सरकार हो या कोई अन्य। गर्वमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेंड यह है कि वह untied grant किसी स्टेट गर्वमेंट को नहीं देगी। फिर चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो या बी0जे0पी0 की हो चाहे थर्ड फ्रंट की सरकार होगी। untied grant जैसे पहले के समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे, माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सती जी को याद होगा श्री प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे वह एक-एक हजार की घोषणा करते थे, untied grant यह प्रदेश सरकार के हाथ में था वह जहां मर्जी खर्च करते। मगर अब नेश्नल लेवल और गर्वमेंट ऑफ इंडिया पर सीनेरियो चेंज हो गया है। हमें हिमाचल प्रदेश सीनेरियो और सिस्टम कां चेंज करने की जरूरत है। इसलिए हमें हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण ढांचे, उसके कानूनों और प्रक्रियाओं में लचीलापन लाना होगा। कानूनों को आवश्यकता के अनुरूप आधुनिक बनाना होगा। 118 का ही उदाहरण लें किसी उद्योग को 118 की अनुमति देकर लगाया जाता है। अब यदि वह फैक्ट्री किसी कारणवश असफल हो जाती है और मालिक उसे बेचना चाहता है, तो उसे फिर से 118 की लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि 100 करोड़ रुपये की परियोजना को मालिक मजबूरी में दलालों को 50 करोड़ में बेच देता है। वे दलाल फिर 118 की अनुमति लेकर उसी परियोजना को 125 करोड़ में किसी अन्य को बेच देते हैं

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**01.12.2025/1745/केएस/एजी/1**

**उद्योग मंत्री जारी** ---

---

वह आनन-फानन में 100 करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट को दलालों को 50 करोड़ रुपये में दे देगा। फिर वह दलाल 118 के चैनल में चलेंगे, पर्मिशन ले आएंगे और जिस बंदे की 100 करोड़ रुपये की जमीन थी, जिसने 50 करोड़ में बेची, वह उसको 125 करोड़ रुपये में बेच देंगे। आपने कम्पनी का नाम चेंज करना है तो आपको 118 की अनुमति दोबारा लेनी है। अगर आपकी कम्पनी में कोई नया डायरैक्टर आ गया तो आपको 118 की पर्मिशन लेनी पड़ेगी। इसको हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। इसमें हमें लचीलापन लाना पड़ेगा। ...(व्यवधान) रणधीर शर्मा जी, आपने फिर राजनीतिक बात कर दी। ...(व्यवधान) रणधीर शर्मा जी, सरकार कोई भी होगी, दलाल हर सरकार में होते हैं। मगर प्रश्न यह है कि जो हम चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें एक पॉलिटिकल राय करनी पड़ेगी। स्टेट के हित में हमको एक राय करनी पड़ेगी । ...(व्यवधान) रणधीर जी, अदरवाइज़ यह हो रहा है कि आपकी सैलरी और पैंशन बढ़ रही है और बढ़ते-बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि हमारे टोटल बजट का 100 प्रतिशत सैलरी और पैंशन में ही चला जाएगा। प्रदेश के लोगों के विकास पर खर्च नहीं हो पाएगा। मुख्य मंत्री जी कानून चेंज करने के प्रयास कर रहे हैं मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि चाहे हम सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से हों, हमको in terms of investment हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए कन्सैंस ला कर एक हो कर कार्य करना पड़ेगा। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**01.12.2025/1745/केएस/एजी/2**

**सभापति :** अब माननीय सदस्या कुमारी अनुराधा राणा चर्चा में भाग लेंगी।

**कुमारी अनुराधा राणा :** सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत माननीय विधायक श्री केवल सिंह पठानिया जी द्वारा जो प्रस्ताव सदन में लाया गया है, जिसका शीर्षक है "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन विचार करे," इस प्रस्ताव के साथ मैं अपने आप को भी शामिल करती हूं और अपने विचार रखना चाहूंगी ।

सभापति महोदय, प्रदेश में वर्ष 2023 में भयंकर आपदा आई थी और उससे पूरा प्रदेश जूझा। अभी हमारे लोग और हमारी सरकार इस आपदा से उभर ही रही थी कि वर्ष 2025 में भी आपदा आ गई। हम मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का जिस प्रकार से डटकर सामना किया गया, वह एक तरह से पूरे देश में अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत है। जो इससे पूर्व सरकार द्वारा मुआवजा राशि दी जाती थी या हमें केंद्र सरकार द्वारा भी जो मुआवजा दिया जाता है, यदि हम उसकी पूरी लिस्ट चैक करे और प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी मुआवजा राशि में रिकॉर्ड बढ़ौत्तरी की गई, यदि उसकी तुलना की जाए तो यह पूरे देश में अभूतपूर्व है और इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरे मंत्रिमण्डल का हार्दिक धन्यवाद करते हैं।
सभापति महोदय, वर्ष 2025 की आपदा के सम्बन्ध में अगर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करुं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों की लगभग 80 प्रतिशत फसल बर्बाद हो गई क्योंकि मानसून का जो दौर चला था उसमें कुल्लू-मनाली की सारी सड़कें टूट गईं थीं। हालांकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में उतनी ज्यादा सड़कें डैमेज नहीं हुईं थीं। बी0आर0ओ0 के मुख्य मार्ग डैमेज होने के अलावा कुछ पी0डब्ल्यू0डी0 के सम्पर्क मार्ग ही डैमेज हुए थे परंतु मण्डी में एग्जोटिक वैजिटेबल्ज़ की सप्लाई हमारी उसी रूट से जाती है। दोनों छोर से जो हमारा रूट कट गया था उस वजह से हमारी फसलें समय पर मार्किट में नहीं पहुंच पाईं और लगभग 80 प्रतिशत फसल खेतों में ही बर्बाद हो गई। आप सभी जानते हैं कि लाहौल-स्पिति जिले की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, जहां पर लगभग 6 महीने बर्फ रहती है और साल की सिर्फ एक ही नकदी फसल रहती है। पूरे किसानों की आर्थिकी मुख्यतः कृषि और पर्यटन पर ही निर्भर है।

**01.12.2025/1745/केएस/एजी/3**

इस आपदा में हमारा पूरा पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हो गया। हम बी0आर0ओ0, सरकार और प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि रिकॉर्ड समय में सड़कों को बहाल किया गया परंतु आप जानते हैं कि एग्ज़ोटिक वेजिटेबल्ज़ की समयावधि बहुत कम रहती है। ये दो दिन बाद खराब हो जाती हैं अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यदि हम कृषि विभाग के रिकॉर्ड का आकलन करें और अगर मैं सिर्फ एग्ज़ोटिक

वेजिटेबल्ज़ और फसल की बात करुं तो उन्होंने किसान के नुकसान का लगभग 18 करोड़ रुपये का आकलन किया है । परंतु असामयिक बर्फबारी के कारण हमारे सेब का भी नुकसान हुआ। पट्टन वैली में सेब लगाया जाता है, वहां सेब के पौधों का नुकसान हुआ। जब आलू निकालने का समय आया तो अक्तूबर में असामयिक बर्फबारी के कारण आलू का भी नुकसान हुआ और मार्किट में आलू के रेट धड़ाम से गिर गए। हमारे किसानों की आर्थिकी को जो नुकसान पहुंचा,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**01.12.2025/1750/av/as/1**

**कुमारी अनुराधा राणा------- जारी**

हमारे किसानों की आर्थिकी को जो नुकसान पहुंचा, उसको शायद शब्दों में बयां करना सम्भव नहीं है। परंतु फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करती हूं कि उनके आशीर्वाद से मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई। पहले हम देखते थे कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए सिर्फ 1.30 लाख रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन अब जो बढ़ोतरी करके 7 लाख रुपये की राशि की गई है, उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करते हैं। इसके अतिरिक्त गौशालाओं और बर्तनों के लिए दी जाने वाली राशि में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। अगर केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि की दरें देखी जाए तो वह बहुत कम है। साथ ही, अगर हम फसलों के नुकसान की बात करें तो पहले 680 रुपये प्रति बीघा मुआवजा राशि दी जाती थी जिसमें 588 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा अब वह राशि 4000 रुपये प्रति बीघा दी जाती है। इसी तरह से हमारे खेतों में जो बाढ़ के कारण गाद भर जाती है उसमें पहले 1440 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा राशि मिलती थी। प्रदेश सरकार द्वारा 694 प्रतिशत बढ़ोतरी करके अब उसमें 5000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त

जो कृषि योग्य भूमि क्षतिग्रस्त हो जाती है या बह जाती है तो उसके लिए पहले 3760 रुपये प्रति बीघा मुआवजा राशि के रूप में दिए जाते थे, उसमें भी सरकार द्वारा 265 प्रतिशत रिकॉर्ड बढ़ोतरी करके अब वह राशि 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दी जाती है। सरकार द्वारा मुआवजा राशि में जो अढ़ाई सौ से पांच सौ प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है, हम उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री का विशेष धन्यवाद करते हैं।

सभापति महोदय, लेकिन यदि हम फसलों या जमीन के प्वाइंट ऑफ व्यू से उसकी तुलना करते हैं तो वह मुआवजा राशि फिर भी कम लगती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री इस विषय के हर पहलू को प्रत्येक स्तर पर उठा चुके हैं।

वर्ष 2023 की आपदा के दौरान हमने देखा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित टीम ने प्रदेश के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था और उस समय लगभग 950 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया था। जिसमें पी0डी0एन0ए0 की राशि

**01.12.2025/1950/av/hk/2**

हिमाचल प्रदेश को लगभग दो वर्षों के उपरांत वर्ष 2025 में प्राप्त हुई। उसमें भी जो उस दौरान दो हजार करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई थी उसमें से भी हिमाचल प्रदेश को केवल 490 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई।

इसी तरह से वर्ष 2025 की आपदा के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री स्वयं हिमाचल प्रदेश पधारे थे और उन्होंने यहां आकर स्वयं नुकसान का आकलन किया था। उन्होंने उस समय 1500 करोड़ रुपये की विशेष आपदा राशि देने की घोषणा की थी। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण वह राशि अभी तक हिमाचल प्रदेश को प्राप्त नहीं हुई है। हम इस सदन के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि उस आपदा राशि को जल्दी-से-जल्दी हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया जाए। मेरा खासतौर पर पी0डी0एन0ए0 की राशि के लिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा क्योंकि हम जनजातीय जिला से संबंध रखते हैं। हमारे वहां केवल 6 महीने ही वर्किंग सीजन रहता है और उसके बाद माइनस

टैम्प्रेचर में काम करना सम्भव नहीं होता। इसलिए लोक निर्माण विभाग या जल शक्ति विभाग के द्वारा जो भी कार्य एग्जीक्यूट होते हैं उसमें मार्च तक पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि जनजातीय क्षेत्र में इस समय-सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे वहां केवल 6 महीने ही वर्किंग सीजन रहता है और उसके उपरांत माइनस टेम्परेचर में कोई भी कार्य करना फीज़िबल नहीं होता। वहां सीमेंट नहीं जमता या इस प्रकार का कोई कार्य करना सम्भव नहीं होता।

आपदा के दौरान वहां पर किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम शुरू की गई थी ताकि किसानों को सस्ती दरों पर ऋण मुहैया करवाया जा सके। केंद्र में वर्ष 2008-09 के दौरान जब कांग्रेस गठबंधन की यू0पी0ए0 सरकार थी तो पूरे देश में किसानों का ऋण माफ किया गया था जिसके अंतर्गत 4 करोड़ किसान लाभान्वित हुए थे। उसमें के0सी0सी0 के ऋण भी शामिल थे जिसके अंतर्गत हमारे हिमाचल के भी कई किसान लाभान्वित हुए थे। आज वैसी ही भयावह स्थिति हम फिर से अपने हिमाचल में देख रहे हैं। मैं खासकर अपने जिला की बात करूंगी क्योंकि वहां पर पूरे वर्ष में केवल एक ही नकदी फसल होती है। यह केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए मेरा अपनी प्रदेश सरकार से

**01.12.2025/1950/av/hk/3**

निवेदन रहेगा कि आप इस विषय को बहुत ही ठोस तरीके से केंद्र सरकार के समक्ष रखें। जब वर्ष 2008-09 में केंद्र की यू0पी0ए0 सरकार ऋण माफ कर सकती थी तो आज की केंद्र सरकार को भी यह करना चाहिए। यहां से इसके लिए और ज्यादा दबाव बनाया जाए ताकि हमारे के0सी0सी0 के अंतर्गत जो किसान हैं, मेरे जिला में लगभग 5500 किसानों ने के0सी0सी0 के अंतर्गत ऋण लिया है और उन्होंने लगभग 130 करोड़ रुपये के करीब बैंकों को राशि वापिस करनी है। किसानों को आपदा के दौरान कृषि में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, उसको देखते हुए यदि ऋण माफी हो या उन्हें कुछ समय दिया जाए। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में यह विषय केंद्र सरकार के समक्ष रखा जाए। हम केंद्र सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि वे पूरे प्रदेश को इसमें रियायत प्रदान करे।

**टी सी द्वारा जारी**

**01.12.2025/1755/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1**

**कुमारी अनुराधा राणा... जारी**

हम पहले सेशन से आपदा पर चर्चा करते आ रहे हैं और हर बार वही बातें दोहराई जाती हैं क्योंकि आपदाओं की लहर लगातार चली आ रही है और समस्याएं अभी भी जस-की- तस बनी हुई हैं। इस आपदा में कई लोग बेघर हुए, कई लोगों के मकान और जमीनें चली गईं परंतु हम घरों के बदले घर और जमीनों के बदले जमीन नहीं दे पा रहे। यह मुद्दा पहले भी सदन में आया था और राजस्व मंत्री महोदय द्वारा माननीय सदन में एफ0सी0ए0 कानून में संशोधन के लिए प्रस्ताव लाकर इसे पारित करके केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था क्योंकि एफ0सी0ए0 कानून एक ऐसा कानून है जिसके तहत एक इंच भूमि उपलब्ध करवाई जाना भी संभव नहीं है।

सभापति महोदय, हर वर्ष विंटर सेशन धर्मशाला में होता है। धर्मशाला देवभूमि है और यहां मैक्लोडगंज एक नगर है जिसे मिनी ल्हासा कहा जाता है। वर्ष 1959 के बाद तिब्बत की निर्वासित सरकार मैक्लोडगंज में रहती है और परम श्रद्धेय दलाई लामा जी भी यहीं पर निवास करते हैं। भारत और हिमाचल वह भूमि है जिन्होंने विदेश से आए लोगों को यहां पर जमीन देकर निवास उपलब्ध करवाया है लेकिन आज हम अपने ही लोगों को हिमाचल में जमीन नहीं दे पा रहे हैं और यह केवल एफ0सी0ए0 कानून की वजह से है। यह मामला हमने पहले भी उठाया था और हमारी सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है। मैं जानना चाहूंगी कि इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है। साथ ही मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना चाहिए क्योंकि यह बात हमने सांसद महोदय के समक्ष भी रखी थी कि इसे पार्लियामैंट में उठाया जाए। इस एफ0सी0ए0 कानून में संशोधन आवश्यक है ताकि बेघर हुए लोगों को दो या तीन बिसवा जमीन उपलब्ध करवाई जा सके जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण और हर प्लेटफार्म पर कहा है परंतु कई चीजें प्रदेश सरकार के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है फिर

भी सरकार लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। जब प्रधान मंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे तो उन्होंने उनके समक्ष भी यह बात रखी थी लेकिन अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि केन्द्र सरकार के लिए इसे करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। सविंधान बनने के

**01.12.2025/1755/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2**

बाद आज तक 130 संशोधन हमारे कानून में हो चुके हैं। यदि जनहित में यह संशोधन हो जाए तो यह अत्यंत संवेदनशील कदम होगा। यह केवल हिमाचल का मुद्दा नहीं है बल्कि उत्तराखंड तथा अन्य पहाड़ी प्रदेशों में भी यही परिस्थिति है। इसलिए इसके लिए सभी प्रदेशों को एक प्लेटफार्म पर आना होगा। विशेषकर जनजातीय और दूरस्थ इलाकों में जहां भौगोलिक परिस्थितियां अत्यधिक कठिन हैं वहां जनजातीय क्षेत्र के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा ताकि जमीनों के नुकसान की भरपाई जमीन देकर की जा सके।

सभापति महोदय, एक और कानून जो कांग्रेस सरकार की देन है, वह 1968 का नौतोड़ कानून है जिसकी बदौलत नौतोड़ भूमि लोगों को मिली। नौतोड़ कानून विशेष रूप से हमारे ट्राइबल जिला स्पीति जैसे क्षेत्रों में लाभकारी रही है जहां कस्टमरी लॉ लागू होता है और वहां पर छोटे बेटों को प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होता परंतु नौतोड़ की वजह से स्पीति में छोटे भाई आज आर्थिक रूप से सक्षम हैं। यदि नौतोड़ न होता तो उनकी स्थिति अत्यंत खराब होती इसलिए हम तत्कालीन सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने नौतोड़ और एफ0आर0ए0 जैसे क्षेत्र में कार्य किया। यदि एफ0सी0ए0 में संशोधन करने में समय लगता है तो एफ0आर0ए0-॥। (1) में हमारे कम्युनिटी राइट्स का क्लेम बनता है इसलिए मेरा मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि सभी डी0सी0, एस0डी0एम0 तथा अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि एफ0आर0ए0 के सैक्शन -॥। (1) में कम्युनिटी राइट्स में लचीलापन दिखाएं क्योंकि कानून कहता है कि वर्ष 2005 से पहले उस भूमि पर अधिकार होना चाहिए और यह 50 बीघा तक भी हो सकता है। यदि एफ0सी0ए0 में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है तो एफ0आर0ए0 एक विकल्प है

लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारी कितने लचीलेपन से कार्य करते हैं और मुझे लगता है कि जनहित में यह लचीलापन अत्यंत आवश्यक है।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

01-12-2025/1800/NS-DC/1

कुमारी अनुराधा राणा -----जारी

अंत में, मेरा सरकार से पुनः निवेदन रहेगा कि के0सी0सी0 ऋण माफी के प्रति सरकार केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करवाए और मेरा केंद्र से निवेदन है कि वह इसमें के0सी0सी0 माफ करे। मेरे क्षेत्र में बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष अधिक नुकसान हो रहा है। फ्लड मिटिगेशन में मेरे कई प्रपोजल्ज पेंडिंग हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इसकी स्वीकृति शीघ्र दें क्योंकि पहले भी आपके सहयोग व आशीर्वाद से सगनम में 4 करोड़ रुपये का फ्लड मिटिगेशन में कार्य पूरा हुआ था। उसी दिशा में मयाड़ नाले के कारण पूरी वैली में बहुत ज्यादा नुकसान आपदा के समय हुआ। मेरे क्षेत्र के 4-5 पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक गांव अभी भी आपदा से प्रभावित है। हमें अभी से अगले वर्ष की चिंता हो रही है कि अगले वर्ष मानसून किस भयावह स्थिति में आएगा? हमें उस मिटिगेशन का कार्य अगले मानसून से पहले करना पड़ेगा और तभी हम लोगों के बीच में जा पाएंगे तथा लोगों की जवाबदेही को सही साबित कर पाएंगे।

मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपने मुझे समय दिया आपका हार्दिक धन्यवाद।

**सभापति** : अब इस चर्चा में श्री विनोद कुमार जी भाग लेंगे।

**श्री विनोद कुमार** : सभापति महोदय, नियम- 130 के अंतर्गत श्री केवल सिंह पठानिया जी व श्री राकेश जम्वाल जी जो चर्चा लेकर आए हैं कि "प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों" पर यह सदन विचार करे, के विषय को लेकर मैं भी अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस बार की बरसात ने सारे तमाम रिकॉर्ड तोड़े। इस बार की बरसात की शुरुआत जिला मण्डी से ही हुई है। जिला मण्डी में बहुत तबाही हुई है और फिर प्रदेश के अधिकतर जिलों में इस बरसात ने भारी नुकसान किया है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक पूरे प्रदेश में 468 लोगों ने अपनी जानें गवाईं हैं। इसके अलावा 1817 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने आशियाने खोये हैं। जिनके आंशिक रूप से घर तबाह हुए हैं तो 8023 परिवार ऐसे हैं जिनके घर न रहने योग्य हैं और न ही रखने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम गौशालाओं की बात करें तो 7858 ऐसे परिवार हैं जिनकी गौशालाएं इस आपदा में तबाह हुई हैं। अगर मैं दुकानों की बात करूं

01-12-2025/1800/NS-DC/2

तो 518 दुकानें इस आपदा की शिकार हुई हैं। नदी-नालों के किनारे जो घराट होते हैं अगर उनकी बात करें तो 107 ऐसे घराट हैं जो इस आपदा के कारण तबाह हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बार की आपदा बहुत भयंकर थी। हमने और आपने आपदा के कई दौर देखे हैं। पहले बरसात होती थी तो लोगों के छोटे नुकसान होते थे। इस आपदा में हमने देखा कि लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों के बगीचे तबाह हो गए गए जिन बगीचों के कारण वे अपने परिवार को पालन-पोषण करते थे। उनके पूरे बगीचे तबाह हो गए। हिमाचल में हजारों ऐसे परिवार हैं

आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

01.12.2025/1805/RKS/DC-1

श्री विनोद कुमार... जारी

जो कृषि करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे लेकिन वह कृषि योग्य भूमि भी इस आपदा में बह गई। आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने पोलीहाउस लगाए थे, उन्होंने अभी बैंकों की किश्त भी देनी थी लेकिन इस आपदा के

कारण उन हजारों परिवारों के पोलीहाउस तबाह हो गए। इन पॉलीहाउसिज से वे किसान साथी अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि चाहे किसी का भी घर बर्बाद हुआ हो, किसी की भी भूमि चली गई हो, चाहे किसी का भी पोलीहाउस और खेती योग्य उपजाऊ भूमि बर्बाद हो गई है, इसमें सरकार को सभी चीजों से हटकर इस विषय पर विचार करना चाहिए। मैं देख रहा था कि इस आपदा के कारण आज भी बहुत सारे परिवारों को काफी दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। हम इन चीजों को छिपा नहीं सकते। आज हम चाहे पूरे हिमाचल की बात करें या अपने चुनाव क्षेत्र की, इस आपदा के कारण बहुत सारे परिवारों के लैंटर वाले पक्के घर धंस गए हैं। उनकी भूमि 3-4 इंच भूमि बैठ गई है। उन घरों में 2,3 और 4 ईंच दरारें आ गई हैं। अब वे घर रहने के लायक नहीं है। पटवारी कहता है कि ये घर अनसेफ हैं और आप वहां नहीं रह सकते। एक तरफ आप कहते हैं कि घर अनसेफ हैं और जब मुआवजा देने की बारी आती है तो आप उसे फुली डैमज नहीं कहते। आप रिपोर्ट में उस घर को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दर्शाते हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे हजारों मामले होंगे जहां जगह धंस चुकी है। आप डी0सी0 साहब को आदेश करें कि अगर ऐसे मामले आपके ध्यान में आएं तो उन परिवारों के घरों को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सूची में लाया जाए क्योंकि यह पीड़ा हिमाचल प्रदेश के हजारों साथियों की है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के एक नहीं बल्कि दो या तीन जगह भी घर हो सकते हैं। कुछ लोग शहरों में बसे हुए हैं लेकिन उनकी जमीन और घर गांव में भी है। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए शहरों में बसे हैं लेकिन गांव में भी उनका अपना घर है। वे गांव के घर में कम रहते हैं लेकिन वह घर भी उनका ही है। इस आपदा के कारण उनके गांव के घर डैमेज हो गए। पटवारी रिपोर्ट देता है कि यहां पर वह व्यक्ति कम रहता था या रहता ही नहीं था। अगर श्री संजय रत्न जी या विनोद कुमार शिमला में रहते हैं और इनका ज्वालाजी वाला घर या मेरा चैलचौक वाला घर गिर जाता है तो क्या हमें पैसे नहीं मिलने चाहिए? हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे कई परिवार हैं जिनके

01.12.2025/1805/RKS/DC-2

घर 2-3 जगह हैं लेकिन जहां उनका नुकसान हुआ है, जो जगह और घर उनके नाम है, उस व्यक्ति को सरकार की ओर पूरी राहत मिलनी चाहिए। इसके अलावा मैं यह भी देख रहा था क्योंकि मैंन नाचन विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर घरों में विजिट किया है।

श्री... बी0एस0द्वारा जारी

**01.12.2025/1810/बी.एस./ऐच.के.-1**

**श्री विनोद कुमार जारी...**

मैंने तो नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र के ज्यादातर घरों का दौरा किया है। जितनी जगह भी इस आपदा के कारण नुकसान हुआ है, मैं हर जगह गया हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ज्यादातर विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में गए हैं और यह हमारी जिम्मेवारी भी है। आपने देखा होगा कि लोगों ने बड़ी-बड़ी चौकियां बनाई होती है जिसके अंदर 3-4-5 परिवार इकट्ठे रहते हैं। इनकी ज्वाइंट फेमिली होती है और बड़े-बड़े घर बनाए होते हैं। राशन कार्ड अलग होता है खाता अलग होता है उनका किचन और वाथरूम अलग होता है लेकिन घर के 10-15 कमरे होते हैं। इस बार एक नया काम शुरू हो गया। अब चौकी गिर गई तो उस चौकी में पांच परिवार रहते हैं पटवारी आता है और कहता है कि एस0डी0एम0 ने कहा है कि पांच परिवारों को मुआबजा नहीं मिलेगा केवल एक परिवार हो ही मुआबजा मिलेगा, ऐसा क्यों? क्या एक छत के नीचे चार-पांच परिवार रहते हैं तो यह बुरी बात है? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप सरकार के माध्यम से सभी उपयुक्त महोदय को यहां से यह पत्र जारी करें कि जिस घर में 2-3-4 परिवार रहते हैं, चौकियों में लोग रहते हैं। अगर उनका नुकसान हुआ है तो सभी को मुआबजा मिलना चाहिए। यह मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा।

सभापति महोदय, मेरे नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र के 19 लोगों ने इस भारी बारिश के कारण जान गवाई है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा सराज विधान सभा चुनाव क्षेत्र में और दूसरे नम्बर में नाचल विधान सभा क्षेत्र के 19 लोगों की जान गई है और उन 19 लोगों में से 10 लोगों के शव प्राप्त हुए हैं। अब जिन लोगों के शव प्राप्त हुए हैं उनको तो सरकार

की ओर से मदद दी जा रही है। लेकिन जो शव नहीं मिले हैं उन परिवारों की अभी तक मदद नहीं की जा रही है। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जिनके शव बरामद नहीं हुए हैं, सरकार इस बात को ले करके चिंता करें कि इस आपदा के दौरान जो लोग बह करके चले गए उनको कहां ढूंढेंगे? जो लोग बह करके चले गए हैं, उन परिवारों की मदद सरकार करे। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कई बार मंत्री महोदय की यहां से स्टेटमैंट आई कि हमने 36 घंटे में सारी-की-सारी सड़के रिस्टोर कर दी। मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो स्कूल के भवन गिरे थे उनको ठीक

01.12.2025/1810/बी.एस./ऐच.के.-2

करने के लिए पैसों की व्यवस्था की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इसमें से सही कौन है? यह बात समझ में नहीं आ रही है? एक तो हम कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर डिजास्टर एक्ट लगा है और डिजास्टर एक्स के तहत आपने देखा होगा तो अधिकतर उपायुक्तों ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि हमारी सड़कें रिस्टोर नहीं हो पाई है। हमारे पीने के पानी की योजनाएं अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। हमारे अधिकतर स्कूल के भवन गिरे थे वे अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। इस कारण से हम चुनाव नहीं करवा सकते। प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। मंत्री जी, पैसे नहीं जिसके कारण आप काम नहीं करवा पा रहे हैं। परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो परिवार का मुखिया होता है उसकी यह जिम्मेवारी होती है कि उस परिवार को कैसे चलाना है। हमारे विभाग के मुखिया आप हैं हम तो आपको कहेंगे। दूसरी तरफ मैं यह भी देख रहा था कि एक हाई पावर कमेटी ने एक बैठक ली है और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

**01.12.2025.1815.डी0टी0-एच0के0.-1**

**श्री विनोद कुमार जारी...**

दिनांक 11.12.2025 को मंडी के पड्डल ग्राउंड में सरकार के तीन साल के पूर्ण होने के अवसर पर वहां एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा, सेलिब्रेशन मनाया

जाएगा। मेरा मानना है कि आप की परिस्थिति में इस सेलिब्रेशन की आवश्यकता नहीं है। एक तो हम कह रहे हैं कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा है और प्रदेश के पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक बहुत भव्य जश्न हम मंडी में मनाएंगे और वह भी उस जिला में जिस जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा डिजास्टर, सबसे बड़ी तबाही हुई है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हमारा ध्यान सेलिब्रेशन पर नहीं होना चाहिए बल्कि हमारा ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि आपदा के कारण जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, उन परिवारों तक हमारी मदद पहुंचे। इस बात को लेकर हाइपॉवर कमेटी की बैठकें होनी चाहिए। इस बात को लेकर नहीं होनी चाहिए की सरकार के तीन साल के कार्यक्रम का हम जश्न मनाएंगे। मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि सरकार किस बात का जश्न मनाना चाहती है? क्या हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण जो सड़के टूटी थी, जिनकी मरम्मत सरकार अभी तक नहीं करवा पाई है,क्यों उस बात का जश्न मनाना चाहिए। प्रदेश के अंदर पीने के पानी की ऐसी स्कीम्ज हैं जो टूटी पड़ी हैं, जिनकी रिपेयर नहीं हो पा रही है । क्या हम इस बात का जश्न मनाएं की लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है? मैं सरकार से फिर पूछना चाहता हूं कि जश्न किस बात का मनाया जाएगा? प्रदेश में हजारों ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूल के भवन आपदा के कारण क्षतिगस्त हो गये और शिक्षा मंत्री जी कह रह हैं कि इन स्कूलों को बनवाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। पैसे की व्यवस्था करना भी सरकार की ही जिम्मेवारी है। मैं इस सदन के माध्यम से इस बात को भी दावे के साथ कहना चाहता हूं जिस दिन श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश को चलाने की जिम्मेवारी हमारी होगी उस दिन उस जिम्मेवारी को जिम्मेवारी की तरह निभाया जायेगा। क्या सरकार ने सत्ता पाने के लिए जो झूठी गारंटियां लोगों को दी है और जो गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं, क्या उस बात का जश्न मनाया जाएगा? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे छोटे-बड़े पुल जो टूटे हैं उन पुलों का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 6 ऐसे पुल हैं जिनको लेकर मैं वर्ष 2023 से बात कर रहा हूं लेकिन अभी तक सरकार द्वारा एक भी पुल का निर्माण नहीं किया गया है। जश्न को लेकर सरकार जिस तरह

**01.12.2025.1815.डी0टी0-एच0के0.-2**

---

चिंता कर रही है, जिस तरह सरकार ने इस चुनाव को आगे टाल दिया है इसमें मेरा निवेदन है कि जो जश्न का आप कार्यक्रम कर रहे हैं इस डिजास्टर एक्ट के तहत आप इस जश्न को भी यहां पर विराम दें। जो आप जश्न के लिए पैसा लगा रहे हैं उस पैसे को उन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए जिनका इस आपदा में नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय नाचन।

**सभापति** : अब माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

**श्री नीरज नैय्यर** : सभापति महोदय, श्री केवल सिंह पठानिया और हमारे भाजपा के साथी ने जो नियम -130 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। अगस्त, सितम्बर की भारी बारिश में जो प्रदेश को नुकसान हुआ है इससे हमारा जिला चम्बा भी अछूता नहीं रहा। अगर मैं चम्बा म्यूनिसिपल एरिया की बात करूं क्योंकि चम्बा एक ऐतिहासिक शहर है लेकिन हमें ऐसा पहली बार देखने को मिला की शहर के

**श्री एन0जी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1820/वाई.के.-एन.जी./1**

**श्री नीरज नैय्यर ........जारी**

साथ लगते म्यूनिसिपल वाड्र्स के इलाकों में नदी-नालों के कारण अनेक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मेरा अपना आंकलन है कि लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये का नुकसान केवल नगर परिषद् क्षेत्र में ही हुआ है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में तो असीमित नुकसान हुआ है। विपक्ष के साथी जब घरों के बारे में बोल रहे थे तो उन्होंने यहां पर बड़े अच्छे प्वाइंट्स रखे हैं। पिछले सत्र के दौरान मैं सत्र को बीच में ही छोड़ कर अपने विधान सभा क्षेत्र में चला गया था और मैंने 49 ग्राम पंचायतों का दौरा किया था। मैंने पाया कि कई जगहों पर ऐसे घर थे जोकि बिल्कुल इंटैक्ट थे यानी के परफेक्ट थे लेकिन खाई के ऊपर

लटके हुए हैं। यदि वहां पर रिटेनिंग वॉल लगाने जाएंगे तो वह लग ही नहीं सकती क्योंकि नीचे से उसकी हाइट 250 से 300 फीट होगी। इसका मतलब यह हुआ कि सर्दियों में जब भी बारिश या बर्फबारी होगी तो वे घर नीचे आएंगे-ही-आएंगे। मैं प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिलाधीष महोदय को आदेश दिए जाएं कि इस प्रकार के घर जोकि बिल्कुल लटके पड़े हैं और आने वाले समय में 100 प्रतिशत नीचे आएंगे तथा वहां पर प्रोटेक्शन वॉल भी नहीं लग सकती है, उनको भी फुली डैमेज मानकर 7 लाख रुपये की राहत राशि दी जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत सारे घर हैं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गुज्जर समुदाय रहता है। जब मॉनसून का समय होता है तो वे धारों में जाकर रहते हैं। इन लोगों के पास दो-दो घर होते हैं। ऊंचाइयों पर उनके डेरे होते हैं और निचले क्षेत्र में चम्बा के आस-पास पंचायतों में उनके पक्के घर होते हैं। इनके डेरों में भी बहुत नुकसान हुआ है। जब कोई पटवारी उनके डेरों में नुकसान का आंकलन करने के लिए जाता है तो वह कहता है कि ये लोग इन डेरों में रहते नहीं हैं।

**01.12.2025/1820/वाई.के.-एन.जी./2**

ये लोग nomadic tribes होते हैं और आधा समय डेरों में तथा आधा समय नीचले क्षेत्रों में जब अपनी भैंसों को लेकर आते हैं तब चम्बा के आस-पास की ग्राम पंचायतों के अपने घरों में रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 300 से 350 लोग ऐसे हैं जिनके घरों को पटवारियों ने नुकसान के तहत कवर नहीं किया है। वे कहते हैं कि ये हाइट वाले घर हैं और टाइम पास करने के लिए 2-3 माह के लिए ही ये लोग यहां पर आते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीष महोदय को आदेश दें कि nomadic tribes के हाइट वाले

घरों/डेरों, जिनका नुकसान हुआ है, का भी लॉस असेसमैंट करें क्योंकि उनके घरों का लॉस असेसमैंट नहीं किया जा रहा है। मैंने जब पटवारियों व तहसीलदार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें इसी प्रकार के आदेश हैं कि यदि किसी का लेंटर पुरी तरह से टूट गया है तभी उसे फुली डैमेज में डाला जाएगा। इस प्रकार की छोट-छोटी समस्याएं हैं और इनका हल करना बहुत जरूरी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक जड़ेरा गांव है और एक कुटेठ ग्राम पंचायत है। जडेरा गांव हमारे इलाके का मुख्य ऐरिया है और यहां की जमीन लगभग 15 फीट नीचे धंस गई है क्योंकि वहां से एक नाला गुजरता है तथा वहां पर बिल्डिंग्स वैसी-की-वैसी खड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए मनरेगा के माध्यम से फंड्स उपलब्ध करवाए जाएं ताकि आने वाले समय में इस इलाके का नुकसान न हो।

सभापति महोदय, यहां पर विपक्ष के अनेक साथी बैठे हुए हैं और मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अभी हालही में भारत सरकार ने मनरेगा के कार्यदिवसों को सीमित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है, उससे बहुत भारी नुकसान हुआ है और मुझे लगता है कि इससे पूरा प्रदेश लगभग 10 साल पीछे चला गया है। चाहे सड़कें हों, चाहे ब्रिजिज़ हों, चाहे लोगों के घर हों और चाहे खेत-खलियान हो, हमारे प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। मनरेगा ही ऐसी स्कीम है

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

**01.12.2025/1825/वाई0के0-पी0बी0/1**

**श्री नीरज नैय्यर...जारी**

जिससे हम गांव के हर व्यक्ति तक मदद पहुंचा सकते हैं। मैं मुख्य मंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने दो लाख रुपये के डंगों के आपदा के शैल्फ खोलें हैं। इससे गरीब व्यक्ति को बहुत सहायता मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आप इन डंगों में सीमेंट और अन्य मटीरियल भी डालेंगे क्योंकि ये सूखे डंगे हैं। यदि आप इसमें सीमेंट इत्यादि मटीरियल डालेंगे तो ये डंगे और भी मज़बूती से खड़े रहेंगे।

हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 की वजह से बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है। हम इस अधिनियम की वजह से लोगों को घर बनाने के लिए ज़मीनें नहीं दे पाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ही ऐसे लगभग 20-25 घर हैं जो टोटल डेमेज की केटेगरी में आ रहे हैं लेकिन उनकी ज़मीन दोबारा उस जगह पर घर बनाने लायक नहीं बची है। यदि हम उन्हें ज़बरदस्ती कहेंगे कि आप घर बनाने के लिए स्वीकृत हुए सात लाख रुपये से दोबारा उसी ज़मीन पर घर बनाइए तो हो सकता है कि अगले वर्ष वे घर फिर गिर जाएं। मुझे लगता है कि यह एक तरीके से उस पैसे का भी दुरुपयोग होगा। इस अधिनियम पर पक्ष-विपक्ष को मिलकर सोचने की जरूरत है क्योंकि इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। I am very sure कि अब हर इलाके में इस तरह की समस्या खड़ी होगी। यदि इस अधिनियम के संशोधन में समय लगेगा तो हमें कोई अन्य तरीका निकालना पड़ेगा। अभी मुख्य मंत्री जी हर क्षेत्र में जिनके फुली डैमेजिज और पार्शिअली डैमेजिज हाउसजि हैं उनको चैक आबंटित करेंगे। लेकिन वे लोग चैक लेने के बाद घर कहां बनाएंगे? अगर वे उसी जगह घर बनाएंगे तो अगले वर्ष वे घर दोबारा क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण चीज है और इसके ऊपर ध्यानपूर्वक काम करने की आवश्यकता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो वर्ष 2025-26 के नुकसान की पी0डी0एन0ए0 की असैसमेंट हुई है, जैसे नेशनल हाइवे, पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें है उनके आकलन के लिए भारत सरकार से एक टीम आई थी उन्होंने यह असैसमेंट की है कि कितना नुकसान पी0डब्ल्यू0डी0, जल शक्ति विभाग और विभागों को हुआ है। वर्ष 2023-24 में जो पी0डी0एन0ए0 का पैसा

**01.12.2025/1825/वाई0के0-पी0बी0/2**

था वह अभी आया है और अब जाकर टेंडर लग रहे हैं। मुझे लगता है कि पी0डब्ल्यू0डी0 के अंदर ऐसे कई प्वाइंट्स हैं और अगर यह पी0डी0एन0ए0 का पैसा पहले आ गया होता तो आज जो नुकसान हुआ है वह पूरी तरह बच जाएगा। अभी मण्डी क्षेत्र की बात हो रही है और ये सब चीजें विपक्ष के साथियों को भी मैटर करेंगी। पी0डी0एन0ए0 के पैसे से नेशनल

हाइवे या पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं इनके ऊपर डंगे लगेंगे। अगर यह टाइमली लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि भगवान न करें कि हमें ऐसी आपदा का सामना करना पड़े। अगर माड़ी-मोटी बारिश हुई और ये डंगे न लगे तो फिर नुकसान हो सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कों के ऊपर 250 ऐसे घर हैं जो सड़कों के ऊपर लटके हुए हैं। अगर हमें टाइमली पी0डी0एन0ए0 का पैसा मिल जाता है तो हमें कुछ इमदाद अपने लोगों के लिए करने का मौका मिलेगा। मैं अपने विपक्ष के साथियों से एक ओर आग्रह करना चाहूंगा कि जब यह आपदा आई तो हमारे विपक्ष के साथियों ने हमार बहुत साथ दिया। हमने यहां से एक रेजोल्यूशन पास किया और दिल्ली की सरकार को लिखा कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए लेकिन किसी कारण यह हो नहीं पाया। शायद दिल्ली की सरकार

**श्री ए0पी0 द्वारा जारी...**

**01.12.2025/1830/A.G/A.P./ 01**

**श्री नीरज नैय्यर जारी...**

आप लोगों इतना महत्व नहीं देती। हमारे प्रदेश से 7 लोग उसमें राज्य सभा और लोक सभा दोनों की ही बात करते हैं, सात सांसद इस प्रदेश के हैं। अगर हम बिहार चुनाव की बात करें यह चुनाव अभी-अभी हुए हैं और इन चुनाव के दौरान एक करोड़ 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये इलैक्शनों के दौरान उनके खातों में डाले गये। हमारे प्रदेश के लिए आपदा से निपेटने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा 1,500 करोड़ रुपये की राहत राशि की घोषणा की गई। हमें मालूम है कि वह पैसा आ जाएगा, लेकिन क्या यह राशि प्रदेश में आई आपदा के लिए पर्याप्त है? एक कारोड़ 25 लाख महिलाओं को जो 10,000 रुपये दिये गये अगर आप इन्हें गुणा करोगे तो यह राशि 10250 करोड़ रुपये की राशि बनती है। जब कि हिमाचल प्रदेश आपदा से हुए नुकसान का आंकलन लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का किया गया है। अगर केंद्र से हमें 4,000 से 5,000 हजार करोड़ रुपये भी

मिल जाते तो हमारी समस्या का हल काफी हद तक हो जाता। लेकिन दुःख के साथ बोलना पड़ता है कि बिहार में इलैक्शन के दौरान महिलाओं को 10, 500 करोड़ रुपये देने के लिए था जबकि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ था वहां पर सिर्फ चुनाव थे। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जहां से सात सांसद वह भी भाजपा के हैं, उस प्रदेश को एक भी रुपया राहत राशि के रूप में केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया । इस बात को दुःख के साथ कहना पड़ता है, मैं अपने विपक्ष के साथियों को कहूंगा कि वे मेरी बात का बुरा न माने। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 1,500 करोड़ रुपये की प्रधान मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है और मुझे आशा है कि वे पैसा हमें जरूर मिलेगा। अगर वह पैसा समय से मिल जाए तो हमें फायदा होगा। I hope so कि हमें untied मनी के रूप में मिले। अंग्रेजी में एक कहावत है मैंने पहले भी कही थी। One stitch at a time saves another nine. अगर एक टांका टाईम का लगता है तो वह आगे के नो टांको को बचाता है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आपदा की इस घड़ी में आप फिर से केंद्र सरकार से अनुरोध करें आपने पहले भी हमारा साथ दिया लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र की

**01.12.2025/1830/A.G/A.P./ 02**

सरकार आपको ज्यादा महत्व नहीं देती। क्योंकि इस समय मात्र चार एम0पी0 और तीन राज्य सभा सांसद हिमाचल प्रदेश से रखते है। साथ ही में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भरमौर, मणिमहेश यात्रा के दौरान आपदा आई जिससे क्षेत्र को भारी क्षति का सामना करना पड़ा। माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं चम्बा आए और उन्होंने चम्बा में आकर वहां की स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद जो 16,000 श्रद्धालु भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान फंसे थें उनके लिए चिनूक हैलीकॉप्टर का प्रबंध माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऑन-स्पॉट किया । मैं उस मिटिंग में था। लगभग 275 एच0आर0टी0सी0 की बसिज सरकार के द्वारा चलाई गई। मैं राजस्व मंत्री जी का खासतौर से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी चम्बा से ही वापिस लौट आएंगे। मैंन उस समय मंत्री जी को बोला की मैं भी आपके साथ चलता हूं। उस समय माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैं भरमौर पद यात्रा करते हुए

जाऊंगा उसमें चाहे चार दिन लगे या पांच दिन लगे। क्योंकि भरमौर मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं था, अगर मैं भी भरमौर चला जाता, तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग मुझे बोलते कि इसको अपने इलाके की जरा भी चिन्ता नहीं है, ये अपना घर नहीं देख रहे। इसलिए आपके साथ में उस समय उस यात्रा में नहीं जा पाया। क्योंकि नेगी जी यह बहुत बड़ी की वह पैदल गये और जो लोग वहां से वापिस आ रहे थे क्या-क्या बातें वे बोल रहे थे, वह बातें सुनते ही बनती थी, लेकिन हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने अपने व्यवक्तित्व के अनुसार धैर्य पूर्ण उन लोगों की बातें सुनी। मैं एक अन्य बात इस आपदा के संदर्भ में इस सदन में बोलना चाहता हूं क्योंकि गोदि मीडिया कह रहा था कि इस आपदा में 5000 लोगों की जान चली गई, आज जब स्थिति सामने आई तो पता लगा कि मात्र 17 लोगों की जान गई है। इस दौरान प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के लोग जो मणिमहेश यात्रा के लिए आऐ थे, उनमें चाहे पंजाब से थे या

**श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....**

**01.12.2025/1835/AT/AG /01**

**श्री नीरज नैय्यर जारी...**

जम्मू-कश्मीर से जो लोग थे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि मोबाइल चल नहीं रहा था और हम उन्हें सूचना दे नहीं पा रहे थे। जो भी अधूरी-टूटी हुई सूचना उन्हें मिल रही थी उससे मुझे लगता है कि लोगों को बहुत परेशानी हुई। इसीलिए मैं आज माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो गोदी मीडिया और फेक ID से न्यूज़ चलती है इसके ऊपर एक रूल बनना चाहिए। So that these people are booked and they are put to justice because यह सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी पार्टी की बात नहीं है यह पूरे समाज के लिए एक समस्या है। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। इन्हीं शब्दों

के साथ मैं विराम लूंगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**मुख्य मंत्रीः** माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे और यह सही बात है। सोशल मीडिया में मेरी माननीय सदस्य से बात हुई उन्होंने कहा इतने हजार लोग मर गए। मैं भी उसके बाद वहां गया लेकिन माननीय मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी तो पैदल गए और 9 दिन वहां रहे। आज हमने स्टेटमेंट दी कि ऐक्चूअल में 17 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने PDNA की बात की। PDNA का अभी तक सिर्फ वर्ष-2023 का केंद्र सरकार ने आकलन किया जो 9300 करोड़ रुपये का था और दो साल बाद उसका पैसा हमें मिला। जो पहले 2000 करोड़ रुपये बोला गया था उसमें से 1500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार का था और 25 प्रतिशत अंश हमारा था। अभी तक केंद्र सरकार से PDNA का वर्ष-2013 की आपदा का सिर्फ 451 करोड़ रुपये आया है पर अभी पूरा पैसा नहीं आया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। यह स्पष्ट है कि हमें अभी तक 451 करोड़ रुपया ही मिला है। फिर भी हमने संसाधनों और अपने राजस्व से आपदा-प्रभावित परिवारों की वर्ष-2023 में भी मदद की है और वर्ष-2025 में भी पूरी मदद कर रहे हैं।

**सभापतिः** अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री सुरेंद्र शैरी जी

**01.12.2025/1835/AT/AG /02**

**श्री सुरेंद्र शैरी :** सभापति महोदय, अभी जो प्रदेश में आई आपदा को लेकर चर्चा चली है प्रदेश आज भी किस मुश्किल हालत में है, उस पर मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, हमने आपदा का दौर वर्ष-2023 का भी देखा और वर्ष-2025 का भी देखा। इस आपदा के दौर में प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा जान-माल का नुकसान हुआ।

इस बार की आपदा में आंकड़ा यह है कि 468 लोग मारे गए, लगभग 1800 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए और लगभग 8000 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। मैं अपनी विधानसभा के अंदर यह आंकड़े देख रहा था मेरी बंजार विधानसभा में 415 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त, 812 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, 322 गौशालाएं, 61 ढाबे, और शॉप्स लगभग 1000 बीघा जमीन बह गई। आज यहां मैंने प्रश्न पूछा था कि बंजार विधानसभा के अंदर आपदा के दौरान कितना नुकसान हुआ। अभी मेरे साथी नीरज नैय्यर जी कह रहे थे कि सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से काम किया और राजस्व मंत्री लगातार लोगों के बीच रहे। सभापति महोदय,मेरी विधानसभा के अंदर जून महीने में बादल फटे थे। उसके बाद अगस्त में सत्र हुआ उसमें भी हमने यह बात रखी। लेकिन उसके बाद सत्र खत्म होते ही 2 सितंबर को हम वापस चले गए। कुल्लू जिला का वह दृश्य देखने लायक था। सितंबर का महीना पूरा निकल गया, अक्टूबर गुजर गया और इन पांच महीनों में बंजार में वर्षा के कारण आई आपदा में पांच लोग बह गए और 415 मकान पूरी तरह बैठ गए जिसमें बड़े-बड़े गांव

**एम0डी0 द्वारा जारी ......**

**01-12-2025/1840/AS/MD/1**

**श्री सुरेन्द्र शौरी---जारी**

पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जिसमें हमारी विधान सभा का एक कसारी गांव पूरे-का-पूरा सैंज खड्ड से लेकर पूरी पहाड़ी बैठ गई उसमें 80 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उसी तरह से सैंज घाटी का एक मातला गांव जहां पर पीछे से पहाड़ी दरक गई और वहां पर 30 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इसी तरह से तीर्थन घाटी का बांदल गांव पूरे-का-पूरा बैठ गया। गडसा का शेघली धार गांव पूरे-का-पूरा टूट गया। इसी तरह से दोगाधार, शोघी इत्यादि सारे-के-सारे टूट गए। लेकिन आज भी वहां पर सारी-की-सारी

ग्रामीण सड़कें टूटी हुई हैं। मैं जो आंकड़ा बता रहा हूं तो इन महीनों के अंदर वहां लगभग 400 से ज्यादा लोग बेघर हो गए लेकिन माननीय मुख्य मंत्री एक बार भी बंजार विधान सभा क्षेत्र में नहीं आए। प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री इस दौरान एक बार भी बंजार विधान सभा क्षेत्र में नहीं आया जबकि वहां पर 400 से ज्यादा मकान टूट गए थे। लोगों का विश्वास टूट गया और मैं आज की अखबार 'अमर उजाला' में पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि 'बाढ़ ने पुल तोड़ दिया, सिस्टम से भरोसा टूटा और सुरक्षा दीवार लगने का दावा भी बह गया'। 'आपदा के तीन महीने बाद भी दिक्कतें झेल रहे कुल्लू जिला के बाशिंदे'। यानी बंजार विधान सभा क्षेत्र के अंदर आज भी छोटी ग्रामीण सड़कों को खोलने के लिए सरकार ने कोई बजट जारी नहीं किया है। माननीय मुख्य मंत्री, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जैसे ही आपदा का दौर आया, लोगों ने तुरंत मुरम्मत करने के लिए कि हमारी सड़कें, पुल ठीक हो जाएं, डंगा लग जाए, इसके लिए पंचायतों ने एस्टिमेट बनाए और कुल्लू जिला के उपायुक्त कार्यलय के लिए एस0डी0आर0एफ के माध्यम से भेजे कि आपदा से थोड़ा-बहुत पैसा आ जाए। लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे सारे एस्टिमेट लिस्ट-आउट किए गए। उनको दोबारा बंजार भेज दिया गया कि अब इनको प्रीयोरोटाइज कीजिए और वहां पर केवल सत्ता धारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए एस्टिमेट को ही एप्रूवल मिलेगी बाकी सारे पैंडिंग कर दिए यानी कि आपदा के अंदर भी इस प्रकार का भेदभाव किया गया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या आपदा पूछकर आती है? किसी भी व्यक्ति का नुकसान

**01-12-2025/1840/AS/MD/2**

हुआ हो परंतु उसको पैसा मिलना चाहिए। उसकी सड़क ठीक होनी चाहिए, उसमें इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बारे में विधान सभा के अंदर आज ही एक प्रश्न लगा है। उसमें पूछा गया है कि इस वर्ष मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितना-कितना पैसा किस-किस विधान सभा क्षेत्र के लिए गया है। जिसके उत्तर में बताया गया कि बंजार विधान सभा क्षेत्र के लिए मात्र 61 लाख रुपये दिए हैं। नदौन विधान सभा के लिए 20

करोड़ रुपये और देहरा के लिए 12 करोड़ रुपये दिए हैं। सभापति महोदय, यह कहां का न्याय है? आपदा और सड़कें टूटी बंजार विधान सभा के अंदर और पैसा जा रहा देहरा तथा नदौन विधान सभा क्षेत्रों के लिए, ये आज का प्रश्न लगा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां सड़कें टूटी हैं, वहां पैसा लगना चाहिए।

**श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी**---

**01.12.2025/1845/केएस/एएस/1**

**श्री सुरेन्द्र शौरी जारी** ---

मुख्य मंत्री जी, आपको बड़ा हृदय रखना चाहिए। एक या दो चुनाव क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जहां लोगों को ज़रूरत है, वहां पैसा मिलना चाहिए। आज भी बंजार विधान सभा क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है। नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ लेकिन जो आंकड़े मैं यहां पर रख रहा हूं, उस दृष्टि से सबसे ज्यादा नुकसान बंजार के अंदर हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस है कि इतने महीनों के बाद भी सरकार का कोई आदमी वहां पर नहीं आया। जून से ले कर नवम्बर तक प्रदेश का कोई भी मंत्री वहां आता, दो दिन वहां पर संवीक्षा करते कि वहां लोगों को क्या-क्या ज़रूरतें हैं। सैंज, तीर्थन घाटी, बंजार, बजौरा आदि में बैठते। इस प्राकृतिक आपदा ने मेरी विधान सभा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जहां नुकसान न हुआ हो। प्रत्येक पंचायत में 8 से 10 मकान टूट गए। सड़कें लगातार बंद रहीं। आपदा का दौर बहुत भयानक था। लोग उसको भूल नहीं पाएंगे। लोगों का गांव के अंदर राशन आना बंद हो गया। हमें उस दौरान लोगों के फोन आए कि हमने सेब खा कर रातें गुज़ारी हैं। बच्चों को खिलाने के लिए गांव में राशन ही खत्म हो गया। वर्ष 2025 का आपदा का दौर बंजार विधान सभा की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। जनता इस सरकार को भी नहीं भूल पाएगी कि ऐसे संकट के दौर में सरकार ने हमें लावारिस छोड़ दिया, हमारी किसी तरह की सुध नहीं ली।

सभापति महोदय, मेरे पास स्कूलों का आंकड़ा भी है। इस दौरान लगभग 65 प्राइमरी स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए। 2 गवर्नमैंट मिडिल स्कूल, 5 हाई स्कूल तथा 9 सीनियर सैकंडरी स्कूल यानी कुल मिलाकर 81 स्कूल इस आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए और स्कूलों का 8.77 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पिछले कल जो यहां पर प्रश्न लगा था, यह मंत्री महोदय ने उसका जवाब दिया है। मेरा कहना है कि आपदा का दौर बहुत ही भयानक था लेकिन सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह नहीं किया। लोगों की किसी तरह की कोई सुध नहीं ली गई। वहां हमारा एन.एच.-5 लगभग पांच दिन तक बंद रहा। आज भी यह सरकार वहां की सड़कों का मलबा नहीं उठा पा रही है। बंजार विधान सभा क्षेत्र के अंदर दो-तीन सड़कों को छोड़कर आपदा के तीन महीने बीतने के बाद आज भी लगभग 35 रूटों पर बसें नहीं चल रही हैं। लिंक रोड सारे ही बंद हैं। लोग वहां पर छोटी गाड़ियों में, जीपों में भर-भर

**01.12.2025/1845/केएस/एएस/2**

कर सफर कर रहे हैं। लेकिन सरकार को जिस तरह से वहां पर इंतज़ाम करने चाहिए था, नहीं किए हैं।

सभापति महोदय, मैं सरकार की नोटिफिकेशन देख रहा था। अगर किसी का मकान टूट गया, रहने लायक नहीं रह गया तो उसको टोटल डैमेज नहीं बताया जा रहा है। पटवारी कह रहा है कि अगर 70 प्रतिशत से ऊपर मकान डैमेज होगा तभी आपका टोटल लॉस माना जाएगा। 70 प्रतिशत पैमाना पता नहीं कैसे किया जा रहा है? जो घर रहने लायक नहीं है वह टोटल डैमेज में आना चाहिए यानी किसी का अगर पटवारी ने 65 प्रतिशत नुकसान बता दिया, नुकसान तो उसका भी उतना ही हुआ है जितना कि 71 प्रतिशत वाले का हुआ है। उसको तो 7 या 8 लाख रुपये दिए जा रहे हैं लेकिन 65 से 69 प्रतिशत वाले को 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। मुझे तो यह मापदंड भी समझ नहीं आ रहा है। सरकार को चाहिए कि जो घर रहने लायक नहीं है उसको टोटल लॉस घोषित किया जाए, यानी पूरा पैसा दिया जाए। जो घर आंशिक रूप से टूटा है, जिसकी मुरम्मत हो सकती है, उसको 1

लाख रुपये दीजिए। परसेंट वाइज़ दे रहे हैं तो फिर परसेंटेज वाइज़ ही फिक्स कीजिए। यानी जिसका 5 परसेंट यानी थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसको 50 हजार, अगर किसी का 20 परसेंट नुकसान हुआ है तो उसको डेढ़ लाख और 60 परसेंट वाले को 5 या 6 लाख रुपये के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। इस पॉलिसी को भी ठीक करने की आवश्यकता है। सिर्फ 70 परसेंट से ऊपर नुकसान वाले को आप पैसा देंगे लेकिन जिसका नुकसान 60-65 रह गया, उसको एक लाख ही देंगे, यह ठीक नहीं है और इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। हमारे गांव में एक छत के नीचे दो या तीन भाई रहते हैं, उनका बिजली का मीटर अलग है, राशन कार्ड अलग है 20 वर्षों से वे अलग ही रह रहे हैं लेकिन उनका भी मुआवजा एक ही बन रहा है और वे उसको आपस में बांट रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

**01.12.2025/1850/av/dc/1**

**श्री सुरेन्द्र शौरी** ------- **जारी**

मेरे कहने का मतलब यह है कि इसकी अलग-अलग डेमेज रिपोर्ट बननी चाहिए कि दोनों के मकान टूट गए हैं और दोनों के ही मकान रहने लायक नहीं है। इसलिए दोनों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें भी रिव्यू करने की जरूरत है। मेरा सरकार और राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि इसको इस तरह से करें कि एक मकान के अंदर अगर बिजली के मीटर और राशन कार्ड दोनों भाइयों के अलग हैं, तो उनके दो केस बनने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपदा के कारण हमारे कुल्लू जिला में एन0एच0 की स्थिति बहुत दयनीय है। एन0एच0 305 की स्थिति एक खच्चर रोड से भी दयनीय है। आप उस रोड से एक बार सफर कीजिए। जब आग लगी थी तो वहां पर माननीय मंत्री आए थे और इन्होंने उस रोड की स्थिति देखी है। हमने कहा कि इसको ठीक कीजिए। केंद्र

सरकार ने उसके लिए 4 करोड़ रुपये की राशि दी परंतु उस रोड का काम नहीं हो पा रहा है। वहां पर जब केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा जी (राष्ट्रीय राजमार्ग) आए थे तो उन्होंने उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। परंतु उसके बावजूद भी उस रोड की हालत नहीं सुधर रही है। केंद्र सरकार से लगभग 34 करोड़ रुपये की राशि सेंक्शन हुई परंतु उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय उच्च मार्ग 305 की हालत वैसी ही है और उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए और उस सड़क को जल्दी-से-जल्दी ठीक करे।

उस सड़क के कारण बंजार की टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लॉप होती नज़र आ रही है। अगर हमारी सड़कें ही ठीक नहीं होंगी तो गांवों के अंदर हमारे लोगों ने जो छोटी-छोटी कोटेजिज बनाई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर लगभग 800-900 कोटेजिज हैं। परंतु वहां सारी जनता परेशान है कि कब ये सड़कें ठीक होंगी और हमारे होम स्टे चलेंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस आपदा के कारण जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि वहां के सभी केसिज को तुरंत रिव्यू करे और वहां की स्थिति का जायजा लें। आजकल सर्द रातों में हमारे लोग बाहर टैंट्स में रहने को मजबूर हैं। उनके लिए अपना जीवन-यापन

**01.12.2025/1850/av/dc/2**

करना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि लोग यह सोच रहे हैं कि अब अपने घर बनाएं या अपने लिए कोई दूसरा बसेरा ढूंढे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री सहित पूरी सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे बंजार विधान सभा क्षेत्र का विशेष ध्यान रखें और इस आपदा के संकट से हम कैसे उभर सकते हैं तथा कैसे लोगों की रीहैबिलिटेशन हो सकती है, उस नाते प्रयास करें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**01.12.2025/1850/av/dc/3**

**सभापति :** माननीय मुख्य मंत्री, आप बोलिए।

**मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी ने कहा कि आपदा में यह हो गया, वह हो गया और वहां पर मुख्य मंत्री जी नहीं आए। मैं सदन के माध्यम से यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आग लगी थी तो वहां पर हमारे लोक निर्माण मंत्री जी और राजस्व मंत्री जी गए थे। ...(व्यवधान) वह भी आपदा ही होती है। अगर आप यह कहते हैं कि बंजार में जो गांव जला वह आपदा नहीं है, तो यह गलत बात है। वहां पर हमारे दोनों मंत्री पैदल गए। उसके बाद मुझे माननीय राजस्व मंत्री ने वापिस आकर बताया कि वहां पर सबको बहुत नुकसान हुआ है और फिर हमने उनको आपदा राहत के तहत पैसा दिया। मैं खुद एक रात ठहर कर वहां की स्थिति को अण्डरस्टैंड करके आया। वहां आपके एक गांव में रात गुजारी और आपदा प्रभावित के तहत पिछली बार भी बंजार विधान सभा क्षेत्र में लोगों को मकान के लिए राहत प्रदान की गई थी। पिछली बार जिसका पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था उनको पहली किस्त में 4 लाख रुपये की राशि दी गई थी और इस बार भी जिनके मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए उनको 4 लाख रुपये की राशि दी गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार और मंत्रियों के माध्यम से बंजार विधान सभा क्षेत्र के लोगों को हर सरकारी नीति का लाभ पहुंच रहा है और यही प्रेजेंस होती है कि हम उनके दर्द को समझें। हम वहां पर एक रात ठहरे भी थे। आपका इस प्रकार से बात करना उचित नहीं लगा इसलिए मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर रहा था।

**सभापति :** अब कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी चर्चा में भाग लेंगे।

**टी सी द्वारा जारी**

**01.12.2025/1855/टी0सी0वी0/डी0सी0/-1**

**कैप्टन रणजीत सिंह** राणाः सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-30 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सुजानपुर में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। मैं मुख्य मंत्री ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को राहत देने का कार्य किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की चौतड़ा पंचायत में भारी आपदा आई और लोगों के घर जमीन में ही दब गए। हमारी सरकार ने इस आपदा का डटकर सामना किया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखकर उनका पूरा ध्यान रखा। उनके खाने और रहने का प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से किया गया। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्वयं दौरा किया और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया तथा लोगों को संतुष्ट किया। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में बहुत घोटाले किए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर हुई। उस समय कई लोगों की मृत्यु हुई और इन्होंने उन परिवारों को 50-50 हजार रुपये देने का वायदा किया था लेकिन वह राशि आज तक नहीं दी गई, सिर्फ झूठी घोषणाएं की गईं। जो समाजसेवी बनने का दिखावा करते थे वे सुजानपुर छोड़कर ही चले गए और जब वापिस आए तो केवल एक मास्क लेकर आए और 50 पैसे का मास्क दान करके स्वयं को दानी बताने लगे। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आपदा क्षेत्र का दौरा किया और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही हल किया। जिन घरों में दो-दो लोगों की मृत्यु हुई थी उन्हें उस समय की सरकार ने 50-50 हजार रुपये देने का वायदा किया था लेकिन आज तक एक रुपया नहीं दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा मकान के लिए 1.30 लाख रुपये दिए जाते थे जबकि आज हमारी सरकार और मुख्य मंत्री जी 7 लाख रुपये और एक लाख रुपये सामान के लिए दे रहे हैं। इससे दोनों सरकारों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। वैसे तो ये अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे लेकिन डबल इंजन की सरकार की बात करने वाले खुद कुछ नहीं कर पाए और जब हिमाचल में डबल इंजन वाली सरकार थी तो इनकी सरकार में पी0पी0 किट, दवाइयों और कई अन्य घोटाले हुए। जो लोग दवाइयों के पैसे

**01.12.2025/1855/टी0सी0वी0/डी0सी0/-2**

खा गए वे जनता की क्या सेवा करेंगे? इनके कई विधायक सही कह रहे थे कि यदि प्रदेश को सुधारना है तो ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी जो फैसले ले रहे हैं, विपक्ष को उनका स्वागत करना चाहिए।

एन0एस0 द्वारा जारी .....

01-12-2025/1900/NS-HK/1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा -----जारी

अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इस आपदा में प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही हुआ है। बरसात में सड़कें 15 दिन और तीन महीने बंद रहती थीं। इस बार सड़कें एक घंटा या डेढ़ घंटे बंद रही हैं और उसके बाद खुल जाती थीं। हर जगह जे0सी0बी0 खड़ी रहती थी। जैसे ही पानी आता था या मलबा गिरता था तो उसको आधे घंटे के भीतर ही साफ किया जाता था। इनकी सरकार के समय सड़कों के बीच पड़े हुए ल्हासों को अभी हमारी सरकार ने उठाया है। ...(व्यवधान) ये अपनी सरकार के समय चहेतों के फर्जी टेंडर लगाते थे और अपने लोगों को फायदा देते थे।

**सभापति** : कृपया माननीय सदस्य को बोलने दें। Please let him complete.

**कैप्टन रणजीत सिंह राणा** : सभापति महोदय, ये अपने ठेकेदारों को फायदा देते थे। जो मेरे क्षेत्र में थे उनकी तो अपनी ही ठेकेदारों की फौज थी। उनको फायदा देने के लिए वे कोई जमीनी स्तर पर काम नहीं करते थे लेकिन फिर भी उनको फायदा पहुंचाया जाता था। आपकी सरकार (विपक्ष) ने प्रदेश के धन का दुरुपयोग किया है। बिना मतलब के भवन बना दिए। दस मंजिले भवन बना दिए और आज उनमें कोई नहीं रह रहा है। ये भवन इसलिए बनाए कि हमारे ठेकेदारों और चहेतों को फायदा मिले।

**सभापति :** माननीय सदस्य कृपया आप इसे कल कंटिन्यू करें।

अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

**धर्मशाला**-176215 **(यशपाल शर्मा)**
**दिनांकः 01 दिसम्बर, 2025** **सचिव।**